पेज-06

RNI No.- 52143/91

सीधी और सच बात, साहस के साथ

आज की जनधारा

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण

www.aajkijandhara.com

www.jandhara.in

Jandhara24x7

@AJandhara/Jandhara24/7

AajkiJandhara & Jandhara24x7

6232949114, 8959444440

वर्ष : 35, अंक : 182, रायपुर, मंगलवार 07 जुलाई 2026

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, मध्यप्रदेश व नई दिल्ली से प्रकाशित epaper www.aajkijandhara.com | email:aajkijandhara@gmail.com | अषाढ़ कृष्ण पक्ष-8, वि.सं. 2083 | पृष्ठ : 12 | मो. : 9425203900, 9425243430 ❁❁❁ मूल्यः 2.00 रु.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

चंपतराय और अनिल का इस्तीफा मंजूर

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी प्रकरण में आठ लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्टियों पर गंभीर आरोपों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला किया है।ट्रस्ट ने महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बताया कि ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक इस्तीफा देते ही वो स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। गोविंद देव गिरि ने कहा कि ट्रस्ट के नियमों में प्राविधान है कि अगर कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है तो उसे स्वतः ही मान्य माना जाता है। इसी कारण चंपतराय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है।

स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार हुआ और परासरन जी के दखल के बाद दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन राम संभालेंगे। 22 जुलाई को एक बार फिर हम बैठेंगे। हम उम्मीद करते हैं तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी।

उस बैठक में हम नए न्यासी की नियुक्ति भी करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच यह ट्रस्ट की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। बैठक में कई सदस्य संतों ने भारी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद इस्तीफे पर मुहर लगी। बिना बुलाए ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे गोपाल राव को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास ने की। ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

वो चढ़ावा दिखाया जिनकी चोरी का हुआ था दावा

बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी सामान के गायब होने की बात सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट ने उन सभी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, जिनके चोरी होने या गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे। सोने की रामचरितमानस, भगवान राम के चरण चिन्ह, हार और काकभुशुंडि को कॉन्फ्रेंस में रखा गया।

भगवान राम भारत की आत्मा के स्रोत हैं

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और श्रीराम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि राम का मतलब राष्ट्र है। वह भारत की आत्मा के स्रोत हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज जो भव्य अयोध्या और श्रीराम मंदिर देश देख रहा है, वह अशोक सिंघल के संकल्प और सपने का परिणाम है। 1980 और 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पूरे देश में एक ही नारा गूंजता था- रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।सीएम योगी ने कहा कि उस समय एक और नारा युवाओं में जोश भरता था कि मंदिर के काम न आए, ये जवानी बेकार है।

कृष्ण मोहन राम होंगे अंतरिम महासचिव

ट्रस्ट ने सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई के कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत अधिकारी हैं। उन्होंने भी राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर सहमति जताई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि जब तक नए महासचिव की नियुक्ति नहीं होती है तब तक मैं इस पद का निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से हुई चोरी में जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकरण में जो भी हुआ है उस से हम सभी लोग आहत हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां थी।

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई ऊंचाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक के स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमिपूजन किया

- आधुनिक छात्रावास और कैंसर सेंटर विस्तार की रखी गई आधारशिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार 5 जुलाई को रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इस दौरान आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सकों-कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री बोले- स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी पूरा होगा जब प्रदेश के नागरिक स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों की छात्रावास संबंधी मांग को पूरा करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कई स्वास्थ्य परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं और भविष्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल विद्यार्थियों से बस्तर, सरगुजा सहित दूरस्थ क्षेत्रों में भी सेवाएं देने का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने गुणवत्ता पर दिया जोर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि करीब 104 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है। साथ ही लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय से पहले और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल और रिसर्च सेंटर का निर्माण जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरबा, कांकेर और महासमुंद मेडिकल कॉलेजों के लंबित निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए हैं। बिलासपुर के सिम्स का उन्नयन किया जा रहा है, डीएम कार्डियक कोर्स शुरू हो चुका है और जगदलपुर में जल्द ही प्रदेश का दूसरा ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

दिल्ली-पंजाब से 6 और आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और पंजाब से छह और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार सभी आरोपी पाकिस्तान के गैंगस्टर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के एजेंट शहजाद भट्टी के मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं।

स्पेशल सेल ने कार्रवाई के दौरान इस नेटवर्क के दो अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इनमें एक मॉड्यूल आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई पिस्टल और पेट्रोल बम बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मॉड्यूल के सदस्य देश में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने

पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावत, चन्नी दिल्ली रवाना

- इंचार्ज बघेल की मीटिंग का बायकॉट, 1 सांसद-6 एमएलए का समर्थन, वड़िंग अकेले पड़े

लुधियाना। पंजाब कांग्रेस में खुली बगावत हो गई है। पूर्व सीएम व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल की मीटिंग का बायकॉट कर दिया है। चन्नी अपने समर्थक सांसदों, विधायकों व पूर्व विधायकों से मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। जहां वे हाईकमान से मिलेंगे। चन्नी समर्थकों ने बघेल को रिसीव तक नहीं किया। बघेल अब साइलेंट बैठे नेता विपक्ष प्रताप बाजवा के घर गए हैं।

चन्नी को नया प्रधान बनने के लिए अब तक एक सांसद सुखजिंदर रंधावा और 6 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके अलावा नए वर्किंग प्रधान संगत सिंह गिलजियां भी उनके गुट में शामिल हो गए हैं। मौजूदा प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग के पक्ष में सिर्फ एक सांसद डॉ. अमर सिंह आए हैं। कोई भी विधायक उनके समर्थन में नहीं बोला है।

चन्नी ने प्रभारी के आने से पहले ही मोहाली में अपने समर्थक नेताओं से मीटिंग की। जिसमें प्रभारी के बायकॉट का फैसला लिया गया। चन्नी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि यह मोरिंडा में हुई पहली मीटिंग की ही कड़ी है। कांग्रेस हाईकमान ने बगावत थामने के लिए बघेल को 5 दिन के लिए पंजाब भेजा है। वह चंडीगढ़ में दोनों गुटों से मीटिंग करने के लिए आए हैं।

सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने दी नसीहत: वहीं पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉ. ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

ब्रीफ न्यूज

अमरनाथ में शिवलिंग 90फीसदी गायब

श्रीनगर। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार एक फीट रह गया है। सोमवार को एक फीट के बाबा बर्फानी की फोटो सामने आई। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। पिछले 3 दिनों में 56 हजार से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से 18.6फीसदी ज्यादा रहा।

लाल किला ब्लास्ट केस अवशेषों की रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किलाब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मृतकों के शरीर के अवशेषों से जुड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। विशेष एनआईए अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसकी जांच के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। साथ ही पेश किए गए नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

देशभर में 58 टेक्निकल कॉलेज बंद हुए

नई दिल्ली। 2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज फेज वाइज बंद कर दिए गए। इनमें मौजूदा छात्रों को डिग्री पूरी करने दी जाएगी। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में नए एडमिशन नहीं होंगे। यूपी और महाराष्ट्र में 12-12, मप्र में 8 कॉलेज बंद हुए हैं।

निजी कोचिंग सिस्टम खत्म हो

नई दिल्ली। निजी कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को स्कूल शिक्षा से जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोचिंग संस्थानों व डमी स्कूल मॉडल ने समानांतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है।

मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह गया: राहुल

- राहुल गांधी जयपुर में बस-ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप पहुंचे

जयपुर। राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं। तकनीकी खराबी के कारण बसों में लगने वाली आग का दोष उन कारीगरों पर लगाया जा रहा है, जो केवल गाड़ी की बॉडी तैयार करते हैं। सोमवार को मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

राहुल बोले- छोटे उद्योग बंद होने से रोजगार खत्म हो रहा: राजस्थान के स्थानीय बस और ट्रक बॉडी-बिल्डर्स से मुलाकात के दौरान ऐसा भारत देखने को मिला, जो अपने दम पर रोजगार पैदा करता है। लोहे की चादरें, वेल्डिंग की चिंगारियां, हथौड़ों की आवाज इन सबके बीच कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। जयपुर की बस-ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप में ऐसा भारत दिखता है, जो ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

इंदिरा आवास योजना घोटाला: 426 खातों में आधार बदलकर 79 लाख का गबन

परियोजना अधिकारी के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश

रायपुर। इंदिरा आवास योजना घोटाला मामले में एसीबी ने कोरबा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गौरव शुक्ला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार और मोबाइल नंबर बदलकर सरकारी रकम निकाल ली गई। जांच में सामने आया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी ने हितग्राहियों के बैंक खातों से 79 लाख रुपए निकाल ली गई। बैंक के सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर 426 हितग्राहियों के खातों से रकम निकाली।

ऐसे किया गया घोटाला: आरोपी गौरव शुक्ला ने इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के हितग्राहियों के बैंक खातों, जिनमें अधिकांश खाते डिएक्टिव थे, को बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग कर दोबारा सक्रिय कराया।

इसके बाद हितग्राहियों के आधार नंबर हटाकर उनकी जगह अपने, अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र के आधार नंबर लिंक (सीड) कर दिए। इसके बाद एईपीएस के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर हितग्राहियों के खातों की राशि सीधे अपने खातों में ट्रांसफर करता रहा।

426 खातों में 620 बार आधार सीडिंग में बदलाव: जांच में पाया गया कि 9 अलग-अलग स्टाफ यूजर आईडी का उपयोग कर 426 खातों में 620 बार आधार सीडिंग में बदलाव किया गया। इनमें अधिकांश बदलाव बिना आधार कार्ड के फिजिकल सत्यापन के दर्ज किए गए। और जांच में यह भी सामने आया कि कुछ एंट्रियां बैंक के फिनेकल सिस्टम और कियोस्क ऑपरेटर आईडी का इस्तेमाल कर भी की गई थीं।

2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत मिली थी राशि: जांच में पता चला कि, साल 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत कोरबा जिले के अलग-अलग गांवों ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी

- पहलगाम आतंकी हमला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को अपनी पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी ने हमले की साजिश और आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी अतिरिक्त साक्ष्य अदालत में पेश किए हैं।

हाफिज सईद के खिलाफ क्या-क्या आरोप?: जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने हाफिज सईद पर व्यक्तिगत तौर पर और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व उसके सक्रिय प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के चीफ के तौर पर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 5 की मौके पर मौत

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सोमवार दोपहर आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर ग्राम मेना गोदी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग वाहन के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

विकास की अजब दास्तां

उफनते नाले पर बांस में बाइक फंसा कर कंधा देकर करा रहे पार

अबूझमाड़ में आज भी मानसूनी जीवन का संघर्ष कायम

(मधुकर दुबे)

रायपुर। जहां कभी सशस्त्र नक्सलवाद के दौर में बूंदक के गोलियों की गूंज थी, वहां हर साल मानसून के दौरान जीवन जीने का संघर्ष कायम है। इसकी तस्वीरें हर साल सामने आती हैं। गौरतलब है कि अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलवाद का घनघोर काला साया था, जिसे अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से समाप्त हो चुका है, लेकिन विकास के मुद्दे पर सवाल आज भी है, सरकारें योजनाएं बनाती हैं लेकिन इसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जिम्मेदार सरकारी अमला क्यों फेल हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, उसके शोध और जांच के बजाए सरकारें अंधाधुंध विकास के जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती हैं, पर उसकी मॉनिटरिंग करने में पीछे रह जाती हैं।

नतीजा, सरकार की छवि खराब होती है, चाहे वह ग्रामीण अंचल हो या शहरी। यही कारण है लोगों के मन में सरकार के प्रति विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब हो जाता है। योजनाओं को मूर्तरूप देने वाले अधिकारियों के चेहरे बदलते हैं लेकिन उनका रवैया नहीं बदलता। सिर्फ कागजी दस्तावेजों में उलझे रहते हैं। जबकि उनका नैतिक धर्म है कि उनके विभाग या जिलों में चल रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्या हाल है, उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जनता चाहे शहरी हो या ग्रामीण की, वे मांगें रखते हैं, लेकिन वह नक्कारखाने की तूती बनकर रह जाती हैं। मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं की स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिली तो सरकारी कागजों में ऐसे उलझती है, उसे पूरा होने में वर्षों लग जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की परपाटी के चलते जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान जनसंपर्क के लिए जाते हैं तो उन्हें जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में रायपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग समेत अन्य जिलों में धरातल स्तर पर जिस तरीके से योजनाओं को मूर्तरूप देने में जिम्मेदार विभागों के अधिकारी विफल नजर आ रहे हैं, उससे यह भी प्रतीत होता है, इसका बड़ा खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा।

दूरस्थ गांवों में क्यों दिखती हैं मानसूनी जीवन के संघर्षों की कहानी: सवाल है, मानसून में हर साल आखिर क्यों मानूसनी जीवन के संघर्षों की तस्वीरें और कहानियां मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। चाहे वह वनांचल हो या मैदानी इलाके। कहीं मरीज को खाट पर नाला पार करते परिजन तो कहीं जान हथेली पर लेकर नाला पार करते नौनिहाल छात्र। इस मानसून में बीजापुर जिले में ग्राम चोखनपाल से गंगालूर से एक तस्वीर और विडियो वायरल हो रहा है कि लोग अपने बांस में बाइक को फंसाकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। जब इसकी वास्तविकता की पड़ताल ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य

- एमपी पहला ऐसा राज्य, सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को मेंबर बनाया

भोपाल। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्यप्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार का दावा है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं। इससे पहले वक्फ अधिनियम-1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि, कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। 2025 में कानून में संशोधन के बाद पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम-से-कम दो ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

बस्तर में कृषि-क्रांति की तैयारी

अबूझमाड़ के जंगलों में महकेगी कॉफी

ओडिशा के कोरापुट में ट्रेनिंग लेंगे अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बेहद अनूठी पहल की है। बस्तर के इस अंचल में अब बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में कलेक्टर नारायणपुर ने भारत सरकार के कॉफी बोर्ड के विशेषज्ञों के साथ कुतुल, कच्चापाल, कोडलियार, ईरकभट्टी और तोके सहित आस-पास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत जमीनी निरीक्षण किया।

जलवायु और मिट्टी कॉफी के लिए बेहद अनुकूल

निरीक्षण के दौरान कॉफी बोर्ड के विशेषज्ञ दल ने क्षेत्र की जलवायु, वार्षिक वर्षा, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और समुद्र तल से ऊंचाई का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया। बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अबूझमाड़ का प्राकृतिक वातावरण कॉफी उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। यहाँ 'कॉफी आधारित कृषि वानिकी मॉडल' विकसित कर बड़े पैमाने पर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

चार साल में शुरू होगा उत्पादन, ग्रामीणों को मिलेगी स्थायी आय

विशेषज्ञों के अनुसार, कॉफी के पौधों का करीब चार वर्षों तक रख-रखाव करने के बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। इसके बाद यह ग्रामीणों के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी नियमित आय का जरिया बनेगा। इस पूरी परियोजना में स्थानीय स्व-सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीणों की सीधी भागीदारी तय की जाएगी, जिससे हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अबूझमाड़ के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण का सही उपयोग करना, वनों का संरक्षण करना और स्थानीय ग्रामीणों को आय का एक स्थायी व मजबूत जरिया देना है। प्रारंभिक चरण में भूमि का चयन कर प्लांटेशन और स्थानीय स्तर पर नर्सरी की शुरुआत की जा रही है।

ओडिशा के कोरापुट में ट्रेनिंग लेंगे जिले के अधिकारी

कॉफी बोर्ड के अधिकारियों के सुझाव पर कलेक्टर ने जिले के कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ओडिशा के कोरापुट भेजने के निर्देश दिए हैं। वहाँ अधिकारी कॉफी उत्पादन, पौध प्रबंधन, पर्यावरणीय आवश्यकताओं और तकनीकी पहलुओं की बारीकियों को सीखेंगे, ताकि वे आकर स्थानीय किसानों का मार्गदर्शन कर सकें।

भविष्य में चाय की खेती की भी संभावना

विशेषज्ञ दल के साथ चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि अबूझमाड़ की वादियाँ चाय की खेती के लिए भी उपयुक्त हैं। इस पर कलेक्टर ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए चरणबद्ध कार्ययोजना (Phase-wise Action Plan) तैयार करने के निर्देश दिए।

इस महत्वपूर्ण दौरे में भारत सरकार कॉफी बोर्ड से उप निदेशक, आंध्र प्रदेश, प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, आंध्र प्रदेश, वरिष्ठ संपर्क अधिकारी, कोरापुट, जिला उप संचालक कृषि और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुशासन तिहार से टीबी उन्मूलन अभियान को मिली नई गति

42 स्वास्थ्य शिविरों में 5,890 डिजिटल एक्स-रे और 538 बलगम जांच

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में आयोजित सुशासन तिहार जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी अभियान बनकर उभरा है। इसी क्रम में 1 मई से 10 जून 2026 तक सरगुजा जिले में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर टीबी की समय पर पहचान, उपचार और जनजागरूकता पर व्यापक अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 42 विशेष स्वास्थ्य शिविरों में 5,890 लोगों की डिजिटल एक्स-रे जांच की गई, जिनमें 30 व्यक्तियों में टीबी की पुष्टि हुई। वहीं 538 बलगम (स्पुटम) जांच में 23 मरीज टीबी पॉजिटिव पाए गए। अभियान के दौरान कुल 53 नए टीबी मरीजों की पहचान कर उनका तत्काल उपचार प्रारंभ कराया गया, जिससे बीमारी के प्रसार को रोकने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में सफलता मिली।

अभियान के दौरान संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं नियमित फॉलोअप की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। साथ ही निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचाररत मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। जिले की 40 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने निक्षय मित्र के रूप में सहभागिता निभाते हुए उपचाररत 38 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किए, जिससे उपचार अवधि में उन्हें आवश्यक पोषण सहयोग मिल सके। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच एवं सचिवों को जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस पहल से अन्य ग्राम पंचायतों को भी टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप सुशासन तिहार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या टीबी के अन्य लक्षण दिखाई दें तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क जांच अवश्य कराएं। समय पर जांच, नियमित उपचार और जनसहभागिता से टीबी मुक्त सरगुजा तथा टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को शीघ्र साकार किया जा सकता है।

हरी खाद से संवर रही खेतों की सेहत, प्राकृतिक खेती की मिसाल बने किसान नरेंद्र सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हरी खाद के उपयोग हेतु लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी पहल का सकारात्मक परिणाम सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केशगंवा में देखने को मिला है, जहां प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह ने लगभग चार एकड़ भूमि में ढैंचा की फसल उगाकर उसे खेत में पलट दिया है। अब वे इसी खेत में धान की खेती करेंगे। किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से ढैंचा की खेती अपनाई। उन्होंने बताया कि फूल आने से पहले ढैंचा को खेत में पलट देने पर यह कुछ ही दिनों में सड़कर प्राकृतिक जैविक खाद में परिवर्तित हो जाती है। इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ढैंचा जैसी दलहनी हरी खाद वाली फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। इसके साथ ही फास्फोरस, जिंक एवं आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है, जिससे आगामी फसल का विकास बेहतर होता है। हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार होता है। ढैंचा के अपघटन से बनने वाला ह्यूमस मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे उसमें हवा और पानी का बेहतर संचार होता है। इससे जड़ों का विकास मजबूत होता है और फसल अधिक स्वस्थ एवं उत्पादक बनती है। साथ ही मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रहती है और सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ढैंचा की सघन बढ़वार खरपतवारों की वृद्धि को भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में सहायक होती है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुवाई से पहले ढैंचा, सनई अथवा अन्य हरी खाद वाली फसलों का उपयोग करें। इससे रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम होगा, मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरता बनी रहेगी और टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल तथा लाभकारी कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो: राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लैबोरेट्री का लोकार्पण किया। इस लैबोरेट्री की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से राशि प्रदान की गई है ।

इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स जैसे तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाते है। लेकिन आधुनिक तकनीक तभी सार्थक है, जब उसका उपयोग मानव जीवन के कल्याण और समाज के विकास के लिए किया जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की वास्तविक पहचान केवल उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से नहीं होती, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों से होती है जो ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दें। प्रणवानंद अकादमी शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, अनुशासन और चरित्र निर्माण को भी समान महत्व देती है यह प्रसन्नता का विषय है।

राज्यपाल ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकें विश्व को नई दिशा दे रही हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों को भी आत्मसात करना चाहिए। कोई भी नया आविष्कार या नवाचार मानवता के हित में होना चाहिए। मानव पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए न कि कोई तकनीक उसे नियंत्रित करे।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में संतोष का विशेष महत्व है। हमें जो प्राप्त है, उसमें प्रसन्न रहना सीखना चाहिए तथा कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में उतार-चढ़ाव एवं चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन गिरने के बाद फिर से उठना और आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है।

उन्होंने कहा कि समाज ने हमें क्या दिया, यह सोचने के बजाय हमें यह विचार करना चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। समाज के प्रति सेवा, सहयोग, संवेदनशीलता और पड़ोसियों के प्रति आत्मीयता की भावना हमारे जीवन में आनंद लाता है।

कार्यक्रम में अकादमी के अध्यक्ष स्वामी शिवरूपानंद ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा प्राचार्य श्रीमती नीति यदुवंशी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

नदी-नालों के भरोसे रहने वाले 25 परिवारों के घर पहुंचा स्वच्छ पेयजल

अबूझमाड़ के कस्तूरमेटा में जल जीवन मिशन ने बदली जिंदगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की एक नई किरण दिखाई दी है। जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कस्तूरमेटा में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। कभी पीने के पानी के लिए नदी, नालों और पहाड़ी झरनों पर निर्भर रहने वाला यह गांव आज देश के उन चुनिंदा गांवों में शामिल हो गया है, जहां हर घर तक नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है।

'महिलाओं को मिली मीलों के सफर और दूषित पानी से मुक्ति': जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले कस्तूरमेटा के ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पेयजल एक बड़ी चुनौती थी। गांव की महिलाओं को हर रोज कई किलोमीटर का सफर तय कर जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता था। इस भारी मशक्कत में उनका काफी समय और श्रम बर्बाद होता था, जिसका सीधा असर परिवार की आजीविका और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता था। इसके अलावा, नदी-नालों का दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीणों में हमेशा जलजनित (पानी से फैलने वाली) बीमारियों का खतरा मंडराता रहता था। ग्रामीणों की इस बुनियादी और पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए कलेक्टर के कड़े निर्देशानुसार जल जीवन मिशन के तहत विशेष कार्ययोजना तैयार की गई। दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद प्रशासन ने यहां बुनियादी ढांचे का निर्माण किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), नवा रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक संवेदनाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण अभियानों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

महिला स्व-सहायता समूहों के 'विष्णु भोग' चावल की खुशबू पहुंची पुलिस मुख्यालय तक

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिला समाधान

रायपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का स्वागत स्थानीय पहचान और कृषि समृद्धि के प्रतीक 'विष्णु भोग' चावल से किया गया। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने उन्हें जिले की विशिष्ट पहचान माने जाने वाले 'विष्णु भोग' चावल का पैकेट भेंट कर सम्मानित किया। यह चावल जिले में बिहान योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन का सफल उदाहरण बनकर उभरा है।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने पुलिस महानिदेशक को 'विष्णु भोग' चावल की विशेषताओं, उसकी गुणवत्ता तथा इसके उत्पादन और विपणन में महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान दिला रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय में भी वृद्धि कर रही है। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'विष्णु भोग' चावल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण का प्रतीक है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारिता के भविष्य पर हुआ मंथन

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर राजधानी स्थित कृषि मंडपम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, लाभांडी में सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किया।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विगत 4 जून को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर यह विशेष आयोजन किया गया। पैनल चर्चा में विकसित भारत-2047 के लिए सहकारिता क्षेत्र से अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

सफलता की नई उड़ान: पारंपरिक मजबूरी से 'लखपति दीदी' बनने तक का सफर

नारायणपुर की अनिता वड्डे ने 'बिहान' और उन्नत मुर्गीपालन से बदली अपने परिवार की तकदीर, ग्रामीण महिलाओं के लिए बनीं मिसाल

रायपुर। मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो और सही मार्गदर्शन यदि मिल जाए, तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। इसे सच कर दिखाया है नारायणपुर जिले के विकासखंड नारायणपुर अंतर्गत ग्राम भाटपाल की रहने वाली अनिता वड्डे ने। कभी आर्थिक तंगहाली और अनिश्चित भविष्य से जूझने वाली अनिता आज समाज में 'लखपति दीदी' के रूप में अपनी एक नई और सम्मानजनक पहचान बना चुकी हैं।

चुनौतियों भरा था शुरुआती सफर

कुछ समय पहले तक अनिता वड्डे के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन बेहद सीमित खेती और अस्थायी मजदूरी थी। आमदनी इतनी कम थी कि घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती थी। भविष्य को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती थी, लेकिन अनिता ने अपनी इस नियति को स्वीकार करने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की ठानी।

'बिहान' ने जगाया आत्मनिर्भरता का विश्वास

अनिता के जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया, जब वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत 'जीवन स्व-सहायता समूह' से जुड़ीं। समूह में होने वाली नियमित बैठकों, बचत की आदतों और वित्तीय प्रबंधन के तौर-तरीकों ने उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास फूंका। इसी दौरान उन्हें बिहान के तहत संचालित एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) परियोजना के बारे में पता चला। पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नया करने की चाह में उन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक आजीविका पद्धतियों को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बिहान योजना और एकीकृत कृषि क्लस्टर ने मुझे केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जीने का गौरव भी दिया है।

वैज्ञानिक पद्धतियों से पाई सफलता

आईएफसी क्लस्टर के माध्यम से मिले तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग ने अनिता के प्रयासों को पंख लगा दिए। उन्होंने 1500 चूजों की ब्रूडिंग (Brooding) की कमान संभाली और स्थानीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले चूजों की आपूर्ति शुरू की। इससे न केवल उनकी बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई। संतुलित आहार, नियमित टीकाकरण और बेहतर प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उन्होंने मुर्गीपालन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वैज्ञानिक प्रबंधन का ही नतीजा था कि शुरुआती चरण में ही उन्हें 16 हजार रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई।

आज की जनधारा City Dhara

मंगलवार 07 जुलाई 2026, www.aajkijandhara.com

लोगों को भड़काने का घिनौना कृत्य कर रही कांग्रेस

नकटी प्रकरण पर पीसी में मंत्री केदार कश्यप ने लगाया गंभीर आरोप

रायपुर। नकटी गांव मामले में जारी सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और साय सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने एक तरफ गांव में जमीन अधिग्रहण की कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई प्रक्रिया की जानकारी दी, दूसरी ओर भ्रामक जानकारियां फैलाकर कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का घिनौना कृत्य करने का आरोप लगाया।

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के साथ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी अराजक स्थिति बना रही है। नकटी गांव प्रकरण में सरकार पर लांछन लगा रही कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

बकौल मंत्री नकटी गांव का घटनाक्रम आज का नहीं है, 1 सितंबर 2020 को

आवंटन की मांग दी गई, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 15.47 हेक्टेयर भूमि मांगी गई थी, जिसके आधार पर नकटी गांव में भू आबंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 9 नवंबर 2020 को आपत्ति आमंत्रित की गई। 4 फरवरी 2021 को सभी विभागों से आपत्ति मांगी गई, किसी विभाग ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। 26 जून 2021 को उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि आबंटन के लिए प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सरकार के ऊपर आरोप लगाना निराधार है।

केदार कश्यप ने बताया कि वास्तविकता यह है कि नकटी गांव में भूमि आबंटन की प्रक्रिया तत्कालीन सरकार ने की। कब्जा हटाने की प्रक्रिया भी कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू हुई, लेकिन अतिक्रमण करने काम भी उसी रफ्तार से बढ़ता गया। चिन्हांकन के बाद अतिक्रमण 3 हेक्टेयर से 15 हेक्टेयर तक बढ़ गया। जिला प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया। धरना-प्रदर्शन का भी असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार के समय ग्राम सेरीखेड़ी में लगभग 150 परिवारों को बलपूर्वक हटाया गया था, तब न तो किसी का पुनर्वास किया गया और न ही रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इसके विपरीत विष्णुदेव साय सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नकटी के प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराया, मकानों की आवास की चाबी सौंपी और सम्मानपूर्वक उन्हें नए आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की।

मंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधायकों का आवास बनेगा। यह भूमि हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित की गई है। वह भूमि किस उपयोग में आएगी, यह अब हाउसिंग बोर्ट तय करेगा। मुख्यमंत्री साय मामले में पूरी संवदेनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों को नया रायपुर में विस्थापन के बाद भी भड़का रही है। ऐसा बता रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि सरकार की नीति स्पष्ट है कि किसी भी गरीब के साथ में अन्याय नहीं होगा।

पेट्रोल पंप में मिल रहा मिलावटी पेट्रोल!

- **पानी मिला ईंधन भरने से कई गाड़ियों के इंजन सीज**

रायपुर। राजधानी के मरीन ड्राइव स्थित जय जवान पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पेट्रोल पंप के नोजल से पानी मिला हुआ पेट्रोल निकल रहा, जिससे कई वाहनों के इंजन खराब हो गए। कुछ वाहन चालकों का दावा है कि पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ियां बंद हो गईं और कई मामलों में इंजन सीज होने की नौबत आ गई।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वाहन मालिक और ग्राहक पेट्रोल पंप पहुंचे। नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्राहकों का आरोप है कि पेट्रोल में पानी की मिलावट के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई लोगों ने अपने वाहनों की मरम्मत का खर्च पेट्रोल पंप संचालक से दिलाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पेट्रोल के सैंपल लेकर जांच की तैयारी की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ईंधन में वास्तव में मिलावट हुई थी या नहीं। फिलहाल पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का आक्रोश जारी है और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है।

सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

छत्तीसगढ़ में निकायों को निर्देश, सीपीसीबी पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग ने सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा है।

विभाग ने बताया कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। अब चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन नियम, 2026 के तहत लागू की गई है। इसके अनुसार बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, परिसरों और अन्य चिन्हित इकाइयों का पंजीयन केंद्रीकृत पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द सुनिश्चित कराया जाए। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

19 दिन पहले पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी जारी किया था सख्त आदेशः बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बैटरी वेस्ट के अवैध कारोबार पर सख्ती के आदेश जारी किए थे। मंडल ने स्पष्ट किया था कि बिना पंजीयन और जरूरी दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करना गैरकानूनी है।

सीएम साय ने डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद् और राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मां भारती के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

भूपेश बोले–भगवान राम और झूलेलाल दोनों को ठगा गया

- **हर फैसला पीएम लेते हैं, अब चुप क्यों? धीरेंद्र शास्त्री पर कहा–सच्चा साधु कभी डरता नहीं**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि, राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे में गड़बड़ियां हुई। यहां तक भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगा गया। हर फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, अब वो चुप क्यों हैं? बीजेपी नेता विनय कटियार ने धीरेंद्र शास्त्री को चोर कह दिया था। जिस पर उन्होंने कहा कि, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सबसे पहले सवाल मैंने ही उठाए थे। अब धीरेंद्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, जबकि एक सच्चा साधु कभी भयभीत नहीं होता और न ही किसी से डरने की बात करता है। पंजाब रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर बघेल ने यह बयान दिया है।

भूपेश बोले- 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब नहीं: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि, यह मामला नया नहीं है। शिलापूजन के समय से ही गड़बड़ियां शुरू हो गई थीं। जमीन खरीदी से लेकर मंदिर निर्माण तक भ्रष्टाचार हुआ और निर्माण में 40 प्रतिशत कमीशन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज की तरफ से भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के साथ दी गई 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब नहीं है। साथ ही एक आईएएस अधिकारी की ओर से भेंट की गई सोने की रामायण भी गायब हो गई। उन्होंने कहा कि, इस मामले में भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगने का काम हुआ है।

भूपेश बघेल ने कहा कि, अमित शाह को भी इसकी जानकारी है, इसलिए वे राम मंदिर नहीं गए। न वे शिलान्यास में गए, न उद्घाटन में गए। जब शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कौन-कौन ट्रस्ट का सदस्य रहेगा, यह भी प्रधानमंत्री ही तय कर रहे हैं।

बारिश में करंट से बचें, बिजली कंपनी ने जारी की सावधानी की अपील

रायपुर। मानसून के आगमन के साथ बिजली दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने आम जनता के लिए विशेष सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।कंपनी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों, हाई टेंशन लाइनों और किसी भी टूटे तार से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बिजली के किसी भी उपकरण से छेड़छाड़ न करें। बारिश में पानी में करंट फैलने की आशंका रहती है, इसलिए बिजली उपकरणों के आसपास पानी में चलने, खड़े होने या तैरने से पूरी तरह बचें।

विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करते समय हाथ-पैर सूखे रखें और रबर या प्लास्टिक के जूते-चप्पल पहनना सुनिश्चित करें। अगर कहीं बिजली का खंभा, तार या ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त नजर आए तो तुरंत टोल-फ्री नंबर 1912 पर, मोर बिजली ऐप के जरिए या निकटतम बिजली केंद्र को सूचना दें।कंपनी ने खेतों में बाड़ में करंट लगाने, बिजली लाइनों के नीचे निर्माण कार्य करने और हुकिंग के जरिए अवैध बिजली उपयोग से बचने की भी सलाह दी है। खासतौर पर बच्चों को बिजली के खंभों, तारों और उपकरणों के आसपास खेलने से सख्ती से रोकें।

यदि कोई व्यक्ति करंट की चपेट में आ जाए तो सबसे पहले मुख्य स्विच बंद कर बिजली की आपूर्ति रोक दें। अगर स्विच बंद करना संभव न हो तो सूखी लकड़ी, सूखी रस्सी या सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर पीड़ित को बिजली के स्रोत से अलग करें। सीधे हाथ से छूने से बचें और तुरंत प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाएं।

मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन होगा: अगस्त से लागू होंगे नियम, लव जिहाद रोकने की पहल

छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह पर लेनी होगी इजाजत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह पहल की है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन

भी होगा।

मौलानाओं का होगा पंजीयनः नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे फर्जी पहचान, दस्तावेज छिपाकर विवाह कराने और विवादित मामलों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बोर्ड के मुताबित, अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को संबंधित कानूनों का पालन करना होगा और आवश्यक अनुमति के बाद ही निकाह कराया जाएगा।

अंतरधार्मिक निकाह में होगी दस्तावेजों की जांचः नई व्यवस्था के तहत अंतरधार्मिक निकाह के लिए विशेष प्रक्रिया लागू की जाएगी। अगर किसी मुस्लिम युवक या युवती का निकाह गैर मुस्लिम युवक या युवती से कराया जाता है, तो दोनों पक्षों की पहचान, धर्म परिवर्तन (अगर आवश्यक हो), कानूनी औपचारिकताओं और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही निकाह कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कथित लव जिहाद, फर्जी निकाह और दस्तावेजों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।

सरकारी दस्तावेज बनवाने में होगी सुविधाः छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के अनुसार, वर्तमान में कई स्थानों पर बिना किसी केंद्रीय रिकॉर्ड के निकाह कराए जाते हैं। इससे भविष्य में पहचान, वैवाहिक स्थिति और अन्य दस्तावेजों को लेकर विवाद सामने आते हैं।

वक्फ बोर्ड के पास रहेगा निकाह का रिकॉर्डः प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, हर निकाह का पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा।

निकाह के बाद जारी होने वाला प्रमाणपत्र भी बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा।

हज 2027 के आवेदन के लिए नि:शुल्क ई-सुविधा केंद्र शुरू

20 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म

रायपुर। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने मुखर्जी बड़ा, बैरन बाजार स्थित अपने कार्यालय में निःशुल्क ई-हज सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हज 2027 के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क भरे जा रहे हैं। अनेक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होती है। ऐसे में समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाईः हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 31 दिसंबर 2027 तक वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। बेग ने हज यात्रा के इच्छुक सभी आवेदकों से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अपील की है।

बजट 3000 करोड़ का, सामान्य सभा में टपकने लगी छत

रायपुर निगम में जलभराव पर बैठक, व्यवस्था सुधारने आयुक्त को एक हफ्ते का अल्टीमेटम

रायपुर। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक खत्म हो गई है। मानसून के बीच बुलाई गई इस बैठक में शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और बारिश के दौरान लोगों के सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जलभराव और पार्षदों की अधिकारियों को लेकर शिकायतों पर आयुक्त को मिला एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। एक हफ्ते में जलभराव से निपटारे और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए वर्किंग प्लान बनाने कहा गया। साथ ही महापौर नेता प्रतिपक्ष साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, निगम मुख्यालय में भी जगह-जगह पानी टपक रहा था। बता दें कि नालों की सफाई के लिए निगम ने 2026-27 के बजट में करीब 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले साल के लगभग 2 हजार करोड़ रुपए के बजट की तुलना में काफी ज्यादा है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी अखबारों की कतरनों से बनी लाइफ जैकेट लेकर सामान्य सभा पहुंचे। उन्होंने नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार को फेल बताया। वहीं, भाजपा पार्षद ने स्वप्निल मिश्रा अधिकारियों को चोर कहा। उन्होंने कहा कि जोन अधिकारी ना तो काम कर रहे हैं, ना सहयोग कर रहे हैं।

चोर कहने पर सभापति ने टोकते हुए कहा कि आपका मुद्दा ठीक है, लेकिन शब्दों का सही चयन करें।

महापौर ने अधिकारियों पर जताई नाराजगीः महापौर ने कहा कि विशेष सामान्य सभा जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से बुलाई गई है। अधिकारियों पर नाराज़गी जताते हुए महापौर ने कहा कि पार्षदों को लगातार विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से यह बैठक बुलाई गई है, ताकि अधिकारी समझ सकें कि जनप्रतिनिधियों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनका समाधान समय पर किया जा सके। शहर में जलभराव को लेकर महापौर ने कहा कि शहर का तेजी से कंक्रीटीकरण हुआ है और जगह-जगह मकान बन गए हैं।

रायपुर में पीएचई ठेकेदारों ने बरसते पानी में किया प्रदर्शन

- **भुगतान नहीं होने से नाराज, बोले- कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल, अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की**

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्यालय नीर भवन के बाहर सोमवार को ठेकेदारों ने लंबित भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उनके कामों का भुगतान अटका हुआ है। इससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं।

ठेकेदारों ने कहा कि उन्होंने विभाग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं समेत कई विकास कार्य समय पर पूरे किए हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा। कई बार अधिकारियों से मुलाकात और लिखित आवेदन देने के बाद भी केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही।

आर्थिक तंगी से परेशानः ठेकेदारों का कहना है कि, भुगतान नहीं मिलने से बैंक की किस्तें, मशीनों का किराया, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का बकाया और मजदूरों की मजदूरी देना मुश्किल हो गया है। छोटे और मध्यम स्तर के कई ठेकेदार आर्थिक तंगी के कारण नए काम लेने की स्थिति में भी नहीं हैं।

पुलिस ने रूट किया डायवर्टः पीएचई के बाहर प्रदर्शन होने के कारण सुभाष स्टेडियम से कटोरा तालब जाने वाले रास्ते का पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है। पुलिस ने रूट डायवर्ट की एडवायजरी रविवार शाम को ही जारी कर दी थी। यातायात व्यवस्था बदहाल ना हो, इसलिए अफसरों ने अतिरिक्त बल लगाया है।

रायपुर में कहार भोई समाज को मिली बड़ी सौगात

रायपुर। वार्ड क्रमांक-69 माधवराव सप्रे वार्ड में छत्तीसगढ़ कहार भोई समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित इस समारोह में रायपुर पश्चिम विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत, महापौर मीनल चौबे सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत ने भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी।

30 लाख रुपये से बनेगा सामुदायिक भवनः समाज के लंबे समय से सामुदायिक भवन की मांग को पूरा करते हुए वार्ड क्रमांक-69 में भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई। समाजजनों ने इसे सामाजिक गतिविधियों और आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ली 'दिशा' की मैराथन बैठक

- ग्रामीण क्षेत्रों में 100फीसदी वाटर हार्वेस्टिंग और स्कूलों में अव्यवस्था पर दिखाई कड़ाई

जिले में केंद्र की योजनाओं के तहत 8800 कार्यों को मिली मंजूरी, धरातल पर काम पूरा करने के निर्देश

रायपुर। लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा गया। श्री अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र की 124 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और इनका शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए।

इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मंत्री टंक राम वर्मा, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायकगण सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे।

जल संकट से निपटने का मास्टरप्लान: 100फीसदी वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

बैठक में पानी की किल्लत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जल संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के 8,500 ट्यूबवेलों में से लगभग 5,000 ट्यूबवेल गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी ट्यूबवेलों के पास अनिवार्य रूप से वाटर रिचार्जिंग पिट बनाए जाएं। साथ जिले में पहले के 180 कुओं के साथ 48 नए कुएं खोदे गए हैं और 56 नए कुओं को मंजूरी दी गई है सभी में रीचार्जिंग पिट बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के सभी स्कूलों, पंचायत भवनों और आंगनबाड़ियों में 100 फीसदी वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग सिस्टम लगाया जाए। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि, विकसित भारत योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए जिले में 8,800 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिन्हें समय सीमा में पूरा करना है। उन्होंने मनरेगा के सभी अपूर्ण कार्यों को विकसित भारत जी राम जी के तहत तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण और पशु संरक्षण: मानव चेन बनाकर होगा रोड-साइड प्लांटेशन

पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सांसद ने क्रेडाई, सीएसआर, कैम्पा और अन्य मदों के समन्वय से एक वृहद कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

उन्होंने रायपुर से बिलासपुर हाइवे और बलौदाबाजार हाईवे पर जिले में मानव चेन बनाकर रोड साइड प्लांटेशन करने को कहां। साथ एक एकड़ से बड़े सभी स्कूलों और सरकारी भवनों की जमीनों को सुरक्षित करने और पर्यावरण सुधार के लिए कटीले तारों (बार्बेड वायर) की फेंसिंग कर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। आवारा पशुओं के कारण हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए 10 गांवों के बीच एक चोधामज बनाने का सुझाव दिया गया, जिसके तहत 5 गोधाम स्वीकृत किए जा चुके हैं। गोधाम में हाईवे पर घूमने वाले पशुओं को रखने को कहा जिससे पशु और यात्री दोनों सुरक्षित रहेंगे।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के संरक्षण के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली के तहत काम करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की लापरवाही पर बरसे सांसद, कार्रवाई के निर्देश

बैठक में स्कूलों में पाठ्यसामग्री और यूनिफॉर्म वितरण की समीक्षा के दौरान श्री अग्रवाल ने भारी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले के 207 संकुलों में सामग्री पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 113 संकुलों में ही पहुंच सकी है। सरकारी स्कूलों से पहले प्राइवेट स्कूलों में सरकारी पुस्तकें वितरित होने की शिकायत पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के 15 जर्जर स्कूली भवनों को तत्काल डिस्मेंटल करने को कहा और वहां जल्द से जल्द नई भवन निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।

स्मार्ट होंगी आंगनबाड़ियां, लखपति दीदियों ने रचा इतिहास

जिले की 1,17,000 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं में से 68,000 महिलाएं च्लखपति दीदीज् बन चुकी हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। समूहों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पिंक ऑटो योजना की सफलता को देखते हुए (जिससे महिलाएं 25-30 हजार रुपये महीना कमा रही हैं), इसे अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। जिले के सभी 1941 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ियों को स्मार्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां टीवी, फ्रिज और बच्चों के बौद्धिक विकास की आधुनिक सुविधाएं होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस दीदी योजना के तहत 200 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। हर ब्लॉक में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कौशल विकास और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए श्री अग्रवाल ने जिले में नई गैस एजेंसियां खोलने और पीडीएस के तहत नई राशन दुकानें खोलने का सुझाव दिया। उज्ज्वला योजना के तहत बचे हुए 2,767 परिवारों को जल्द से जल्द गैस कनेक्शन देने के निर्देश दिए। पीएम कौशल विकास के तहत 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में तब्दील हो चुके ग्रामीण युवाओं को टाइल्स फिटिंग, एसी रिपेयरिंग और मशीन ऑपरेटर जैसे आधुनिक ट्रेड सिखाए जाएंगे।

3 दिन की बारिश से अमेठी एनीकेट उफान पर

- 3 फीट ऊपर पानी बह रहा, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

बलौदाबाजार। जिले में शनिवार से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पलारी ब्लॉक का अमेठी एनीकेट उफान पर आ गया है। महानदी में जलस्तर बढ़ने से एनीकेट के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। इससे आसपास के दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। अमेठी एनीकेट से आवाजाही करने वाले गांवों में अमेठी, दौनाझार, पिपरछेड़ी, रिवासरार, मुड़ीपार, सुकदा, अर्जुनी, बरबसपुर, घिरघोल, बल्दाकछार, रोहासी और खैरा शामिल हैं। ये सभी गांव थाना गिधपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एनीकेट पर पानी होने के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है।

नदी के उस पार खेती करने वाले किसान और मजदूर अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय निवासी जय राम और गेंद ध्रुव ने बताया कि हर साल बारिश में एनीकेट पर पानी चढ़ जाता है, लेकिन इस बार पहली बारिश में ही जलस्तर 3 फीट से ऊपर बह रहा है। एनीकेट पूरी तरह डूबा हुआ है और आवाजाही पूरी तरह बंद है।

नदी पार न करने की अपील : स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना गिधपुरी प्रभारी सुखेन देशमुख स्वयं अमेठी एनीकेट पहुंचे। उन्होंने नदी के जलस्तर का जायजा लिया और आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी सलाह दी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के पथप्रदर्शक: नरहरि पोर्ते

बसना। भाजपा मण्डल गढ़फुलझर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। डॉ मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, साहस और भारत की एकता एवं अखंडता के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है।

डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण कम आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्र भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। किंतु राष्ट्रहित के प्रश्न पर उन्होंने पद से अधिक सिद्धांतों को महत्व दिया और अपने विचारों के अनुरूप कार्य करने का मार्ग चुना।

वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना कर उन्होंने देश की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया। जम्मू-कश्मीर में अलग व्यवस्था के विरोध में उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका प्रसिद्ध उद्घोष– एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे–आज भी राष्ट्रीय एकता के संकल्प का प्रतीक माना जाता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि भारत की शक्ति उसकी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और जनसहभागिता में निहित है। उनके विचार आज भी देश के युवाओं को राष्ट्रसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी को उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेना चाहिए। विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला महामंत्री माधव साव, मण्डल अध्यक्ष नरहरि पोर्ते, महामंत्रीद्वय प्रहलाद साहू,रंजन साहू, युवा मोर्चा महामंत्री चन्द्रशेखर चौहान, सहकारी समिति बिछियां अध्यक्ष निमित साहू,गणेशराम साव, यादराम साव, क्रान्ति, तुलसी यादव, सुभाष बारीक , पिलाबाबु बरिहा , कीर्तन सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नकटी गांव के पीड़ितों को न्याय दिलाने कांग्रेस का प्रदर्शन

- विधायक का किया पुतला दहन, उचित मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग

धरसींवा। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धरसींवा विधानसभा के अंतर्गत सभी मंडलों में सम्मानपुर-नकटी मामले को लेकर भाजपा विधायक अनुज शर्मा का पुतला दहन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरसींवा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर भाजपा और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रभावित परिवारों को न्याय, सम्मानजनक पुनर्वास, उचित मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पूर्व विधायक अनीता शर्मा ने क्या कहा ?: पूर्व विधायक अनीता शर्मा ने कहा कि सम्मानपुर-नकटी की घटना भाजपा सरकार की संवेदनहीन कार्यप्रणाली का जीता-जागता उदाहरण है। गरीब, किसान और मेहनतकश परिवारों के घर उजाड़ दिए गए, लेकिन सरकार के जिम्मेदार लोग आज भी जवाब देने से बच रहे हैं। जिन लोगों का सब कुछ उजड़ गया, उनके आंसू पोंछने के बजाय सरकार उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ पहले दिन से खड़ी है और न्याय मिलने तक यह लड़ाई पूरी मजबूती से जारी रहेगी।

नदी-नालों एवं पुराने पुल-पुलियों को पार करते समय एहतियात बरतें : कलेक्टर

- घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल जिला बाढ़ कंट्रोल रूम 07723-223305 पर दें सूचना

महासमुंद। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मानसून के दौरान वर्षा की संभावना को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे नदी-नालों, पुराने पुल-पुलियों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को पार करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति की जानकारी तत्काल जिला स्तरीय बाढ़ कंट्रोल रूम 07723-223305 पर दें। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित किया जा रहा है।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि नागरिक अपने क्षेत्र में संभावित बाढ़ प्रभावित स्थानों एवं पूर्व वर्षों के उच्चतम जलस्तर की जानकारी रखें। आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें तथा निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राहत केंद्र की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। उन्होंने प्रत्येक परिवार से आपातकालीन किट तैयार रखने की अपील की, जिसमें सूखा खाद्य सामग्री, पेयजल, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च, आवश्यक दस्तावेज, आपातकालीन संपर्क नंबर, मोमबत्ती, माचिस एवं रस्सी जैसी जरूरी सामग्री शामिल हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आशंका होने पर पालतू पशुओं को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दें। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साथ ही अपने परिजनों एवं परिचितों को अपने सुरक्षित स्थान की जानकारी अवश्य दें। पुलिस, राजस्व, दमकल एवं अन्य बचाव दलों के निर्देशों का पालन करें तथा उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। कलेक्टर ने नागरिकों को मौसम विभाग की चेतावनियों एवं प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं पर लगातार नजर रखने कहा है।

महासमुंद में एनीकट में मछली पकड़ते युवक बहा

- तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में दिक्कत, मौके पर टीम मौजूद, शादी के कुछ महीने बाद हादसा

महासमुंद। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुरा एनीकट में सोमवार दोपहर मछली पकड़ने के दौरान एक युवक तेज पानी के बहाव में बह गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और युवक लापता हो गया।

जानकारी के अनुसार, गोपालपुर निवासी रामेश्वर निषाद (21 वर्ष), पिता दसरू निषाद सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गोपालपुर एनीकट में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। पास खड़े तिरथ निषाद ने लकड़ी के सहारे उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज धारा के कारण वे सफल नहीं हो सके।

घटना के बाद एनीकट में चला रेस्क्यू ऑपरेशन : घटना की सूचना मिलने पर तुमगांव पुलिस और नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, नदी में पानी का बहाव और दबाव अत्यधिक होने के कारण सुरक्षा कारणों से रेस्क्यू दल तत्काल पानी में नहीं उतर सका। युवक की तलाश के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विधायक ने किया माल्यार्पण

राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को किया स्मरण

महासमुंद। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने सोमवार को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता एवं अखंड भारत के प्रति उनके अतुलनीय योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

विधायक सिन्हा ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और दूरदर्शी राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार, आदर्श और राष्ट्रसेवा का भाव आज भी देश के करोड़ों युवाओं एवं जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्पष्ट विश्वास था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और देश की एकता एवं अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनका त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आगे कहा कि आज आवश्यकता है कि हम सभी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों एवं विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज एवं राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार किया जा सकता है।

जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ करने विभिन्न वार्डों में पहुंचे नपाध्यक्ष

- कर्मचारियों के साथ फावड़ा व जेसीबी लेकर शहर के जल भराव क्षेत्रों में पहुंचे निखिलकांत

महासमुंद। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद नगर के विभिन्न वार्डों में जलभराव और नालियों के अवरुद्ध होने की सूचना पर नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू बरसते पानी में मैदान में उतर गए। उन्होंने शहर के जलजमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

नपाध्यक्ष ने पालिका कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर महामाया मंदिर के सामने, सिविल लाइन, एकता चौक, गुलशन चौक, स्वामी चौक, ओवरब्रिज के नीचे, अयोध्या नगर, कुर्मीपारा एवं शारदा मंदिर के आसपास का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर नालियों में कचरा और गाद जमा होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही थी। जहां पानी भर रहा था वहां निकासी के लिए रास्ता बनाया गया और अवरोधों को तत्काल हटवाया गया। स्वयं फावड़ा लेकर उन्होंने जाम नालियों की सफाई कराई, जिससे रुका हुआ पानी बाहर निकल सका और आम जनजीवन सामान्य हो सका। निचले इलाकों में जलभराव न हो इसके लिए विशेष व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई। अध्यक्ष ने पालिका कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मानसून भर लगातार निगरानी रखी जाए।

मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 और मनरेगा के समन्वय से मजल संरक्षण को मिली नई दिशा

महासमुंद। जिले में भू-जल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी समन्वय से व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों से महासमुंद जिले में जल संरक्षण को नई दिशा मिली है।

जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले की सभी 551 ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी के साथ भू-जल संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई। अभियान के तहत बोरी बंधान, डब्ल्यूएटी, एससीटी, प्रधानमंत्री आवासों में सोख्ता गड्ढे, 5 प्रतिशत मॉडल, ब्रश वुड जैसी लघु जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया गया। वहीं मनरेगा के माध्यम से गेबियन, एलबीसीडी, डाइक, आजीविका डबरी, नवा तरिया, जल अवशोषण खंती, सतत कंटूर ट्रेंच, कुएं निर्माण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत नंदनवार के मार्गदर्शन में एक ही वित्तीय वर्ष में 36 हजार जल अवशोषण खंतियां, 8, 200 स्टैगर्ड ट्रेंच, 30 हजार सतत कंटूर ट्रेंच, 51 डाइक, 52 गेबियन, 800 आजीविका डबरी सहित विभिन्न जल संरक्षण कार्य पूर्ण किए गए। मानसून की पहली ही बारिश में इन सभी संरचनाओं में पर्याप्त जल भराव हो गया, जिससे वर्षा जल का अपव्यय रुककर उसका भू-जल में पुनर्भरण सुनिश्चित हो रहा है। इन सभी जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से जिले में लगभग 31 करोड़ लीटर पानी के एकमुश्त भंडारण की क्षमता विकसित हुई है, जिससे आने वाले समय में भू-जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत नंदनवार ने कहा कि जिले की 551 ग्राम पंचायतों में जल संकट की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 एवं महात्मा गांधी मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मानसून की पहली बारिश से इन संरचनाओं में जल भराव होना इस अभियान की सफलता का प्रमाण है तथा यह भू-जल पुनर्भरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

बसना में एक ही रात में 7 दुकानों में चोरी

बसना। नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। विगत रात्रि बसना नगर में एक ही रात के दौरान सात दुकानों में चोरी की वारदात सामने आने से व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चोरों ने अलग-अलग स्थानों पर स्थित दुकानों को निशाना बनाकर नकदी एवं अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने भारत मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, राधे कपड़ा बाजार, लक्ष्मी चॉइस सेंटर (कन्याशाला, बसना) तथा वाधवा कॉम्प्लेक्स स्थित दो दुकानों सहित कुल सात दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगातार हुई इन घटनाओं से नगर के व्यापारियों में भय का माहौल है।

घटना के विरोध में आज बसना व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने बसना थाना पहुंचकर थाना प्रभारी शरद दुबे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर में रात्रिकालीन पुलिस गश्त तत्काल बढ़ाने, चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा मुख्य चौक-चौराहों पर दिन के समय यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती की मांग की गई।

व्यापारी महासंघ ने कहा कि नगर में लगातार चोरी की घटनाओं से व्यापारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बीएसपी ने पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र परिवार ने विश्वविख्यात पंडवानी गायिका, पद्म विभूषण से अलंकृत लोककला की अप्रतिम साधिका तथा भिलाई इस्पात संयंत्र की पूर्व कर्मी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका निधन न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि संपूर्ण देश की सांस्कृतिक एवं लोककलात्मक परंपरा के लिए अपूरणीय क्षति है।

भिलाई के समीप स्थित गनियारी ग्राम में जन्मी तीजन बाई ने अत्यंत साधारण परिवेश से निकलकर अपनी अद्भुत प्रतिभा, अथक साधना और संघर्ष के बल पर पंडवानी जैसी समृद्ध लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने महाभारत की कथाओं को अपने ओजस्वी गायन, सशक्त अभिनय और विशिष्ट प्रस्तुति शैली के माध्यम से जीवंत स्वरूप प्रदान किया। उनकी कला ने भारतीय लोकसंस्कृति को विश्व के अनेक देशों तक पहुँचाते हुए भारत की सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं।

तीजन बाई ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए पंडवानी की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा और अपनी विशिष्ट कापालिक शैली की प्रस्तुति से इस लोकविधा को नई ऊर्जा एवं व्यापक स्वीकार्यता प्रदान की। वे केवल एक लोकगायिका नहीं थीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सशक्त संवाहक और लोककलाओं की वैश्विक पहचान थीं।वर्ष 1986 में वे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ीं। संयंत्र ने उनकी असाधारण प्रतिभा को सदैव सम्मान और प्रोत्साहन दिया। वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित होने के उपरांत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करते हुए पदोन्नति एवं अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए गए। वे सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की उन गौरवशाली कर्मियों में रहीं, जिन्होंने अपनी कला और उपलब्धियों से संयंत्र, छत्तीसगढ़ तथा पूरे भारत का नाम विश्वभर में गौरवान्वित किया।

भारत सरकार ने उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें क्रमशः पद्मश्री (1987), पद्म भूषण (2003) तथा पद्म विभूषण (2019) सहित अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया। वे छत्तीसगढ़ की उन विरल विभूतियों में थीं, जिन्होंने भारतीय लोककला को वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मी तीजन बाई के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन कला-साधना, संघर्ष, समर्पण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का अनुपम उदाहरण है। उनकी अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र परिवार दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने तीजन बाई के निवास पहुँचकर श्रद्धांजलि दी

भिलाई। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की अप्रतिम धरोहर, पद्मविभूषण से सम्मानित एवं विश्वविख्यात पंडवानी की अप्रतिम साधिका डॉ. तीजन बाई के निवास पहुँचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

उन्होंने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपने अद्वितीय कला-साधना, ओजस्वी वाणी और आजीवन समर्पण से छत्तीसगढ़ की लोकधारा को वैश्विक मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका अवसान केवल एक महान लोककलाकार का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों और असंख्य प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें। मंत्री श्री यादव दिवंगत तीजन बाई के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि डॉ. तीजन बाई का संपूर्ण जीवन

हमारी लोकपरंपराओं, संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित रहा। उनकी साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्वभर में स्थापित करने में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। राज्य की कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित आदर्श और विरासत को सदैव सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 'सेव अ लाइफ' सीपीसीआर कार्यशाला आयोजित

भिलाई। इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग द्वारा विगत दिनों में 'सेव अ लाइफ' पहल के अंतर्गत मासिक 'हैंड्स-ओनली सीपीसीआर (कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन) प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जन-जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में आपातकालीन हृदयाघात की स्थिति में त्वरित जीवनरक्षक सहायता प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक लोगों को सीपीसीआर तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है।

यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. उदय कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन डॉ. तनुजा आनंद, डॉ. अमित अग्रवाल एवं डॉ. प्रिया पंकज ने एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डीएनबी रेजिडेंट चिकित्सकों के सहयोग से किया। कार्यशाला में एक प्रतिभागी ने अपने वास्तविक जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार कार्यस्थल पर एक सहकर्मी को अचानक हृदयाघात आने पर उन्होंने प्रशिक्षण से प्राप्त सीपीसीआर तकनीक का समय पर प्रयोग कर उसका जीवन बचाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रेरक अनुभव ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को भावुक एवं प्रेरित किया तथा यह संदेश

दिया कि सीपीसीआर केवल एक चिकित्सकीय तकनीक नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन बचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा प्रशिक्षण मैनिकिन पर सीपीसीआर का अभ्यास किया। एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं डीएनबी रेजिडेंट्स ने प्रत्येक प्रतिभागी को सही तकनीक, शरीर की उचित स्थिति तथा प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन की विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। साथ ही आयोजित संवाद सत्र में आपातकालीन हृदय देखभाल एवं सीपीसीआर से संबंधित प्रतिभागियों के सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया।

'डाइट' ने समय सीमा मे पूरा किया डी. एल एड मूल्यांकन

भिलाई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अछोटी दुर्ग में डी.एल एड प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा का केंद्रीय मूल्यांकन कार्य निर्धारित समय सीमा मे पूरा कर लिया गया।

17 जून से प्रारम्भ केंद्रीय मूल्यांकन कार्य बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राचार्य पदेन मूल्यांकन केंद्र अधिकारी प्रभात मरकले के मार्गदर्शन में 28 जून को पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा केंद्र को लगभग 17 हजार कॉपियां मूल्यांकन करने दी गई थी। जिसमें शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और निजी महाविद्यालय के लगभग 30 से 40 सहायक प्राध्यापकों द्वारा मूल्यांकन कार्य किया गया। मूल्यांकन कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्राचार्य के आदेशानुसार सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी संध्या शर्मा, जनरल सुपरवाइजर हेमंत साहू सुपरवाइजर सत्येंद्र शर्मा हेड वैल्यूअर डॉ नीलम दुबे, डिप्टी वैल्यूअर डॉ वंदना सिंह,संदीप दुबे,सुषमा हिरवानी,आभा वर्मा,वेद डडसेना और संबंधित लिपिक शशांक मेश्राम को नियुक्त किया गया था। इन्होंने समस्त मूल्यांकन सफलता पूर्वक सम्पन्न किया।

संयंत्र में कर्मचारियों हेतु वेल्थ मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन

भिलाई। इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विभाग द्वारा ज्ञानार्जन एवं विकास केन्द्र के सभागार में वेल्थ मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रभावी वित्तीय नियोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजय द्विवेदी रहें।

इस अवसर पर कुल 103 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में विशेष रूप से 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत वित्तीय नियोजन एवं संपत्ति प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जे.एन. ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र एक्सिस बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को वित्तीय नियोजन, निवेश रणनीतियाँ, सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण, कर-बचत निवेश विकल्प तथा प्रभावी वेल्थ मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए समय रहते वित्तीय योजना बनाने के महत्व पर

भी प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में संजय द्विवेदी ने कर्मचारियों को वित्तीय रूप से जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विशेषकर सेवानिवृत्ति के निकट पहुँच रहे कर्मचारियों के लिए सुनियोजित वित्तीय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु इस प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्मिक विभाग की सराहना की।

कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) मिहिर मनोहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी भावभीनी विदाई

भिलाई। इस्पात संयंत्र की सेवा से जून माह 2026 में कुल 86 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया, जिसमें खदान बिरादरी के 05 व संयंत्र के 81 गैर-कार्यपालक शामिल हैं। भिलाई निवास में आयोजित समारोह में संयंत्र के गैर-कार्यपालकों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन- संकार्य) जे. एन ठाकुर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजय द्विवेदी, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन-कर्मचारी सेवाएं) मनीष पंत और उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एससीसीए) राजेंद्र प्रसाद ने कार्मिकों को सेवानिवृत्ति आदेश प्रदान किया।

गणमान्य अतिथियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें स्वस्थ एवं सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अंत में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन के नए पड़ाव के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। संयंत्र प्रबंधन ने विदा होने वाले इस्पात बिरादरी के सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सुप्रियो सेन ने किया।

भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ, जिला भिलाई की नई टीम घोषित

- प्रमुख पदों पर अहम नियुक्तियां

भिलाई। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ जिला भिलाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देशन प्रदेश संयोजक कांतिलाल जैन के मार्गदर्शन एवं जिला संगठन प्रभारी श्रीरामजी भारती एवं जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की सहमति से जिला संयोजक विनोद उपाध्याय द्वारा की गई । नई टीम में सूर्यकान्त पाण्डेय अम्बिका द्विवेदी श्रीमती नीता चौरसिया ,अरुण नायर, डॉ? अनु राणा को सह संयोजक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है । वहीं डाकेश्वर परगनिहा तथा रजनीकांत अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया क्षेत्र में गुरुनाम सिंह को जिला मीडिया प्रभारी एवं कृष्ण कुमार सिंह को जिला आईटी सेल प्रभारी एवं मृत्युंजय द्विवेदी को जिला सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया

है। राकेश ओझा तथा रिकी अग्रवाल एवं बिमलेश्वर पांडे को क्रमशः सह सोशल मीडिया प्रभारी सह मीडिया प्रभारी तथा आईटी सेल सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गयी है। संगठन को मजबूत करने के लिए गोविन्द वर्मा को कार्यालय प्रभारी एवं महेश वर्मा को कार्यालय सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला कार्यसमिति सदस्य एवं मंडल संयोजक में भी प्रमुख नामों में सुरेश सर गोकुलेश तिवारी विवेक यादव, अजय श्रीवास्तव लोकप्रकाश चौधरी, श्रीमती रश्मि अमितेश, रजनीश सिंह, वैभव लाकुण्डे, राजेश चौबे, इसी अफजल अहमद अमित सिंह, श्रीमती सोनाली माधवन, श्रीराम जी, डॉ जितेन्द्र तिवारी गानेन्द्र सिंह, श्रीमती सीमा कन्नौजे श्रीमती उर्वशी वर्मा, राघवेंद्र साहू शीतल दुबे श्रीशुभम त्रिपाठी श्रीदेवदत्त शर्मा, बीपी सिंह, तारकेश्वर, राजगुप्ता, सत्येन्द्र गुप्ता, अनिल विश्वकर्मा श्रीप्रकाश नायक। विष्णु राजपूत, श्रीगंगाराम साहू, नरेंद्र निषाद, छत्रपाल साहू श्रीमती सरिता चौबे राकेश वर्मा को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इस टीम से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है जिला संयोजक विनोद उपाध्याय ने कहा कि नई टीम शिक्षा के क्षेत्र में संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने और संवाद में जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी। वहीं, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की अपेक्षा जताई।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जयंती पर मंत्री गजेन्द्र यादव ने श्रद्धासुमन अर्पित किये

दुर्ग। भाजपा कार्यालय दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर शिक्षाविद् एवं राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उनका अटल संकल्प भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला उनका दूरदर्शी चिंतन, त्याग और समर्पण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अक्षय स्रोत है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू सहित दुर्ग भाजपा परिवार के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर बनवाएं मात्र 3 दिन में
5 साल पुरानी ITR फाइल बनवाएं
मात्र 5000/- में
(व्हाट्सएप पर बनवाएं)
www.onlytds.com
GST-Return
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
TDS रिफंड
CMA DATA
MSME रजिस्ट्रेशन
Food लाइसेंस
संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544

सेवा सेतु पोर्टल बना जन-सुविधाओं का सशक्त माध्यम

- अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी शासकीय सेवाएं,

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से विकसित सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं का सशक्त डिजिटल माध्यम बनकर उभर रहा है। इस अभिनव पहल के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं अब एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे शासन की सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ-साथ आमजन का समय एवं आर्थिक संसाधनों की भी बचत होगी।

इन प्रमुख सेवाओं का मिलेगा लाभ : सेवा सेतु पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र सुधार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार की सुविधा 7 दिवस, विवाह प्रमाण पत्र सुधार तथा विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस, व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 15 दिवस, नल कनेक्शन हेतु आवेदन 30 दिवस तथा नगर पालिका क्षेत्र में संपत्ति नामांतरण की सुविधा 30 दिवस की समय-सीमा में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य शासकीय सेवाएं भी पोर्टल पर क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध हैं। डिजिटल सेवाओं से आमजन को बड़ी राहत सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब अपने आवेदन की जानकारी एवं उसकी प्रगति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नगर निगम क्षेत्र सहित आसपास के नागरिकों को बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

महापौर इंटकवेल पहुंचकर देखी सफाई व्यवस्था,

दुर्ग। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और शिवनाथ नदी में आए तेज उफान का असर अब शहर की पेयजल व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। नदी के बढ़े जलस्तर के कारण नगर पालिक निगम के 24 एवं 42 एमएलडी इंटकवेल के सायफन में बार-बार जलकुंभी, झिल्ली, पॉलीथीन तथा अन्य तैरता कचरा फसा हुआ है इसके चलते रविवार को शहर के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रही। सफाई अभियान लगतार जारी है।जो जल्द सामान्य हो जाएगी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर अलका बाघमार स्वयं शिवनाथ नदी स्थित इंटकवेल पहुंचीं और मौके का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने इंटकवेल के सम्प के नीचे उतरकर सायफन में फंसे कचरे की स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए युद्धस्तर पर सफाई अभियान चलाने तथा शहर की जलापूर्ति को शीघ्र सामान्य करने के निर्देश दिए।

आईआईटी भिलाई में तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

भिलाई। समग्र शिक्षा के सहयोग से आईआईटी भिलाई में तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 400 शिक्षकों को आठ बैचों में तीन-तीन दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम के संरक्षक एवं मुख्य अतिथि आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने अपने संबोधन में शिक्षकों की राष्ट्र एवं समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्वावलंबी बनने, कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा विद्यार्थियों में उत्तम चरित्र और नैतिक मूल्यों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. महबूब आलम एवं डॉ. ध्रुव प्रताप सिंह हैं। अपने संबोधन में डॉ. महबूब आलम ने कहा कि शिक्षक दीपक के समान होते हैं, जो स्वयं जलकर विद्यार्थियों के जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। वहीं डॉ. ध्रुव प्रताप सिंह ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए बताया कि वे अपने विद्यालय के शिक्षकों के योगदान को सदैव सम्मानपूर्वक स्मरण करते थे।

इस अवसर पर डॉ कुलदीप कुमार कटारिया, डीन (शैक्षणिक कार्य) तथा डॉ महावीर शर्मा, और डॉ मईलमुरुगन भौतिकी एवं रसायन विभागों के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में वृद्धि, कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार //

क्रमांक/क्यू/तह./वा./2026
बिलासपुर, दिनांक 03/07/2026
ग्राम सेमरताल

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम सेमरताल प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. बिलासपुर तहसील व बिलासपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका यदुनंदन कौशिक पिता/पति कुन्नुलाल निवासी ग्राम सेमरताल के द्वारा मृतक/मृतिका पीरित कुवर उर्फ प्रीत की मृत्यु दिनांक 13/01/2006 का प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई दिनांक 22/07/2026 को दावा आपत्ति पेश कर सकता है। सुनवाई तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)
सील

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

ईश्तहार

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक डिकेश साहू पिता उत्तम साहू, उम्र-24 वर्ष, जाति-तेली, निवासी-ग्राम बेन्दोझरिया, पो. कुनकुनी, थाना व तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) एवं आवेदिका आकांक्षा कुमारी पिता बसंत कुमार, उम्र-26 वर्ष, जाति-सतनामी, निवासी अर्जुनी, तहसील व थाना अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा इस न्यायालय में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 मे तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आशयित विवाह की सूचना दी गई है। उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03.08.2026 को 03.00 बजे मेरे न्यायालय में होगी।

उभयपक्ष के विवाह के संबंध में जिस किसी को आपत्ति/उजर करना हो तो वे निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/उजर पर सुनवाई नहीं की जायेगी।

आज दिनांक 01-07-202+6 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
विवाह अधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)
सील

चोरी : क्या यह हमारे सिस्टम का चरित्र बनती जा रही है?

■ संपादकीय

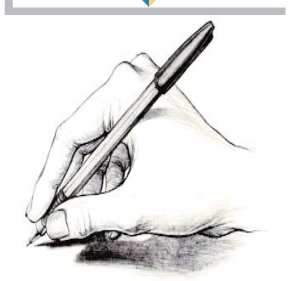

'चोरी' कभी अपराध मानी जाती थी, फिर वह आदत बनी, और अब ऐसा लगता है कि वह व्यवस्था का एक स्वीकृत व्यवहार बनती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस दौर में देश डिजिटल क्रांति, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन निगरानी, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन सर्विलांस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, उसी दौर में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन की लूट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीक जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चोरी के तरीके भी उतनी ही तेजी से आधुनिक होते जा रहे हैं।

एक समय था जब भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जाती थी। आज स्थिति कई बार ऐसी दिखाई देती है कि चोरी होती है और पकड़े जाने पर सीनाज़ोरी भी। 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' जैसे राजनीतिक संकल्पों और पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद यदि मंदिरों से लेकर मंत्रालयों तक, पंचायतों से लेकर परियोजनाओं तक और भर्ती परीक्षाओं से लेकर खनिज निधियों तक गड़बड़ियों की खबरें लगातार आती रहें, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर समस्या कहाँ है?

धार्मिक आस्था के केंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे। देश के अनेक मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों में दान-पेटियों की राशि, चढ़ावे के आभूषणों और आय-व्यय के रिकॉर्ड को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आए हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरों ने कर्मचारियों की करतूत उजागर की तो कहीं ऑडिट रिपोर्टों ने गड़बड़ियों की परतें खोलीं। यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि यहां केवल धन की नहीं, जनता की आस्था की भी चोरी होती है।

शराब नीति से जुड़े विवादों ने भी देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। विभिन्न राज्यों में आबकारी नीतियों, लाइसेंस वितरण और कथित कमीशनखोरी के आरोपों ने यह दिखाया कि नीति निर्माण और निजी हितों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। कई मामलों में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, अदालतों तक मामले पहुंचे, लेकिन इससे व्यवस्था की साख पर लगे प्रश्नचिन्ह समाप्त नहीं हुए।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) फंड का उद्देश्य उन गांवों तक विकास पहुंचाना था, जहां से देश की खनिज संपदा निकलती है। लेकिन, अनेक राज्यों में आरोप लगे कि अस्पताल, स्कूल, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च होने वाला पैसा कहीं और चला गया। जिन लोगों के नाम पर योजनाएं बनीं, वे आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं की स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। मनरेगा, आवास योजना, पंचायत निधि और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में फर्जी मस्टर रोल, कागजों पर बने तालाब, बिना निर्माण के भुगतान, मृत व्यक्तियों के नाम पर मजदूरी और एक ही काम के लिए कई बार भुगतान जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। यह केवल सरकारी धन की चोरी नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों की चोरी है।

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप दिखाई देता है। जब पुल उद्घाटन से पहले गिर जाएं, सड़कें कुछ महीनों में उखड़ जाएं और भवनों में दरारें पड़ जाएं, तब सवाल केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं रह जाता। यह सीधे नागरिकों की सुरक्षा और जीवन से जुड़ा मामला बन जाता है। बिहार सहित कई राज्यों में पुलों के गिरने की घटनाओं ने यह प्रश्न उठाया है कि आखिर भुगतान गुणवत्ता के लिए होता है या केवल कागजों के लिए?

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जी नियुक्तियां, छात्रवृत्ति घोटाले और कोविड काल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जुड़े विवाद बताते हैं कि जब व्यवस्था का नैतिक संतुलन बिगड़ता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर तकनीक होने के बावजूद चोरी रुक क्यों नहीं रही? ई-टेंडरिंग है, ऑनलाइन भुगतान है, आधार सत्यापन है, ड्रोन हैं, जीपीएस है, सीसीटीवी है, सोशल मीडिया है। फिर भी गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। इसका अर्थ साफ है कि समस्या केवल तकनीक की नहीं है। समस्या जवाबदेही की है, दंड प्रक्रिया की है, संस्थागत निगरानी की है और सबसे बढ़कर नैतिकता की है।

कानून का भय तब समाप्त हो जाता है जब दोषियों को यह विश्वास हो जाए कि जांच वर्षों चलेगी, मुकदमे दशकों तक लंबित रहेंगे और अंततः मामला किसी फाइल में दब जाएगा। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के अनेक मामले उजागर होने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता।

फिर भी पूरे देश और पूरे सिस्टम को भ्रष्ट घोषित कर देना न्यायसंगत नहीं होगा। आज भी लाखों ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक संस्थाएं पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। व्यवस्था इन्हीं लोगों के कारण चल रही है। लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोगों की बेईमानी पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाती है।

असल सवाल यह नहीं है कि चोरी कहाँ-कहाँ हो रही है। सवाल यह है कि क्या हमने चोरी को एक सामान्य सामाजिक व्यवहार के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है? यदि सार्वजनिक धन की लूट, संसाधनों की बंदरबांट और अधिकारों की चोरी को हम केवल खबरों तक सीमित रखेंगे, तो यह धीरे-धीरे व्यवस्था का स्थायी चरित्र बन जाएगी। लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि जवाबदेही है। जब तक चोरी करने वालों को त्वरित और कठोर दंड नहीं मिलेगा, जब तक जांच निष्पक्ष और समयबद्ध नहीं होगी, और जब तक समाज ईमानदारी को सम्मान तथा भ्रष्टाचार को सामाजिक तिरस्कार नहीं देगा, तब तक तकनीक भी इस बीमारी का इलाज नहीं बन सकेगी।

कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते-लड़ते उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां चोरी अब अपवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था का एक स्वीकार्य हिस्सा समझी जाने लगी है? यदि ऐसा है, तो यह किसी घोटाले से भी बड़ा राष्ट्रीय संकट है।

'भजनहा शैली' का परिष्कृत रूप है पंडवानी

-योग मिश्र

नारायण प्रसाद जी को लोग भजनहा (भजन गाने वाला) कहकर संबोधित करते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके समय तक पंडवानी शब्द प्रचलन में नहीं आ पाया था। पंडवानी शब्द बाद में प्रचलित हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद के पंडवानी गायकों को पंडवानी गायक के रूप में संबोधित किया जाता है, साथ ही इन्हें शाखाओं के साथ (वेदमति या कापालिक) जोड़कर चिन्हित किया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि पंडवानी गायन के साथ ही साथ इस विषय पर अब काफी काम हो चुका है, लेकिन जिस समय नारायण प्रसाद जी इस विधा को मंच पर प्रस्तुत करना आरंभ किये थे तब यह बाल्यावस्था में था। तब इसे भजन के रूप में देखा जाता था, और इसके गाने वाले को भजनहा अर्थात भजन गाने वाले के रूप में।

छत्तीसगढ़ी पंडवानी कथा गायन का जो रूप आज हम देखते हैं वह अपने मूल रूप से बहुत अलग है। देहाती आंगनों, चौपालों से निकलकर नगरीय मंचों तक पहुंचने की पंडवानी गायन की इस यात्रा का स्वरुप क्या है यह जानना भी रुचिकर है। यद्यपि नगण्य मात्रा में ही सही पर अपने मूल रूप में यह परम्परा कुछ गांवों में आज भी जारी है। सन 1945 के पहले के कालखंड में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उनका बहुत लेखा-जोखा आज हमें नहीं मिलता परन्तु इसके बाद के समय में क्या घटित हुआ उसके ब्यौरे उपलब्ध हैं। मुख्यधारा के हिन्दू समाज से बढ़ती निकटता और व्यवसायीकरण के प्रति बढ़ते झुकाव ने पंडवानी गायन की परम्परा को वर्तमान रूप तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निबाही। सन 1945 में पंडवानी के पितामह कहलाने वाले श्री झाडूराम देवांगन का उदय हो रहा था उनके उदय के साथ ही पंडवानी की प्रस्तुति और स्वरुप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

परधान बाना वाद्य बजाकर, देवार सारंगी बजाकर तथा भिम्मा तूमा बजाकर नृत्यगान करते हैं: यदि हम अतीत की ओर देखें तो पाते हैं कि समूचे

गोंडवाना क्षेत्र में गोंड जनजाति समृद्ध किसान और सामाजिक रूप से प्रभावशाली थी। इनके यहाँ कथागीतों के आयोजनों की परिपाटी भी थी। मान्यता है कि यह कथागीत आरम्भ में किसी गोंड द्वारा ही गए जाते थे, उन्ही कथागायकों के परिवार समूहों ने कालांतर में एक कथा वाचक जाति का रूप ले लिया। परधान, देवार और भिम्मा ऐसी ही जनजातियां हैं। परधान लोग बाना नामक वाद्य बजाकर, देवार लोग सारंगी बजाकर तथा भिम्मा लोग तूमा बाजा बजाकर नृत्यगान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में कथागायन की वाचिक परम्परा सदियों पुरानी: परधान कथावाचक सदियों से गोंडवानी, पंडवानी और रामायनी जैसे वाचिक आख्यानों का गायन करते रहे हैं। डॉक्टर सोनऊराम निर्मलकर जिन्होंने देवार समुदाय पर गहन शोध किया है के अनुसार देवार समुदाय के कथागायक भिक्षाटन के दौरान अनेक अन्य कथानकों के साथ महाभारत की छोटी-छोटी कथाएं (पंडवानी) भी गाते थे। प्रसिद्ध विद्वान् शेख गुलाब ने भिम्मा समुदाय पर लिखी अपनी पुस्तक में लिखा है कि भिम्मा समुदाय के कथागायक साल में एक बार अपने गोंड जजमानों के यहाँ वर्षा के देवता भीमसेन के कथागीत गाते हैं जिससे प्रसन्न होकर भीमसेन पानी बरसाते हैं।

नारायण लाल वर्मा प्रथम पंडवानी गायक हुए: पंडवानी के पितामह झाडूराम देवांगन के वरिष्ठ शिष्य चेतन देवांगन बताते हैं उन्होंने सुना है कि बहुत पहले शिवरीनारायण क्षेत्र के सतनामी समुदाय के लोग अपनी चौपालों में उनकी वाचिक परम्पराओं में प्रचलित घटोत्कच ब्याह, नकुल ब्याह एवं सहदेव ब्याह जैसे महाभारत कथा प्रसंग गाते थे। बाद में झाडूराम देवांगन से पहले अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ रावण-झीपन गांव के नारायण लाल वर्मा संभवतः पहले ज्ञात पंडवानी गायक हुए हैं। प्रतीत यह होता है कि पंडवानी के वर्तमान रूप का प्रचलन संभवतः नारायण लाल वर्मा द्वारा किया गया था।

भीमसेन ने अपना तूमा बाजा लमसेना को भेंट दिया था ऐसी किंवदंती है: पांडवों और विशेष तौर पर भीमसेन से गोंड आदिवासी विश्वासों का गहरा नाता है। गोंड उन्हें वर्षा लाने वाला देवता मानते हैं। श्री शेख गुलाब ने लिखा है, गोंड विश्वास के अनुसार किसी समय भीषण सूखा पड़ा। पानी नहीं बरसा, फसल नष्ट हो गयी।पशु-पक्षी सब भूखे मरने लगे। गोंड ठाकुर खेती के लिए पानी को तरसने लगे। पानी नहीं बरसेगा, खेती नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे।पानी के लिए सब सोच में पड़ गए, गुनिया और ओझाओं ने टोने-टोटके किये। देवताओं को प्रसाद चढ़ाया गया, बलि दी गई पर कुछ नहीं हुआ। गोंड ठाकुर जानते थे कि पानी बरसाने वाला भीमसेन हैं, उन्ही की कृपा से पानी बरसता है। वे बादलों में पानी भरकर लाते हैं तब जाकर पानी की वर्षा होती है। इस बार भीम सेन नाराज हो गए हैं, उनके प्रसन्न होने पर ही पानी बरसेगा। वे भीमसेन को खुश करने के उपाय सोचने लगे।

वर्षा के देव भीमा देव को मनाने समुदायगत आदिरूपों में गाई जाती थी पंडवानी: आज भी समूचे छत्तीसगढ़ के गावों में भीमा देव के देवस्थान होते हैं, लकड़ी का एक मोटा गोल-मटोल खम्बा अथवा प्रतिमा भीमा देव का प्रतिनिधित्व करती है। बस्तर क्षेत्र में भीमा वर्षा के देव के रूप में पूजे जाते हैं। प्रति वर्ष उनकी भीमा जात्रा भादों माह के शुक्रवार को गांव भर के लोग मिलकर मानते हैं। यदि वर्षा अच्छी तरह हो गयी तो नारियल, धूप बत्ती से सामान्य पूजा करते हैं परन्तु वर्षा न होने की दशा में भीमा जात्रा सारा गांव मिलकर बड़े स्तर पर आयोजित करता है । गोंड आदिवासी युवक-युवतियां इसमें बढ़-चढ़ कर नृत्य-गान करते हैं। भीमा देव का सिरहा बुलाया जाता है उस पर चढ़कर भीमा देव खेलता है। उसे मेंढा या भैंसा की बलि दी जाति है। वह प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा का आश्वासन देता है।

पंडवानी के नए अध्याय की जनक तीजनबाई: सन 1970 का दशक तक आते-आते पंडवानी गायन की स्थिति और भी बदल गयी थी। पारधी या बहेलिया जाति की तीजन बाई द्वारा पंडवानी गायन आरम्भ करने के साथ छत्तीसगढ़ी पंडवानी गायन की दुनियां में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ।

पंडवानी गाने पर तीजन की होती थी पिटाई : सन 1985 में श्री निरंजन महावर को दिए एक साक्षात्कार (चौमासा में प्रकाशित) में तीजनबाई ने कहा था, बचपन से मेरी आवाज़ अच्छी थी। मैं ऊँचे स्वर में ददरिया, करमा और सुवा गीत गया करती थी। एकबार पास के गांव की एक डोकरी (बूढी स्त्री) हमारे घर आई और उसने मुझे तम्बूरा दिखाकर कहा कि तू इस पर काम कर। मैंने तम्बूरा बजाना शुरू कर दिया। मेरे नाना ब्रिजलाल पंडवानी जानते थे, हमारे गांव में भी एक-दो बार पंडवानी गाने वाले आए थे, में उन्हें सुन-सुनकर पंडवानी याद करने लगी। जब कुछ याद हो गया तब एक बार तम्बूरा और खंजड़ी लेकर गांव वालों के सामने एक कार्यक्रम किया। पर मेरे पति को मेरा यह काम पसंद नहीं आया, उसने मंच पर ही मेरी पिटाई कर दी। मैं पढ़ी-लिखी नहीं थी, मुझे आधी-अधूरी कथा आती थी। तब मैंने उस समय के एक अनुभवी रागी उम्मेद सिंह से पंडवानी कथा सीखना आरंभ किया। उन्ही से मैंने विभिन्न पात्रों के अभिनय का अभ्यास किया। और अंततः पंडवानी गायन में अपना स्थान बनाया।

व्यंग्य

आलोचना

शरद जोशी

'लेखक विद्वान हो न हो, आलोचक सदैव विद्वान होता है। विद्वान प्रायः भौंडी बेतुकी बात कह बैठता है। ऐसी बातों से साहित्य में स्थापनाएँ होती हैं। उस स्थापना की सड़ांध से वातावरण बनता है जिसमें कविताएँ पनपती हैं। सो, कुछ भी कहो, आलोचक आदमी काम का है।' आज से आठ वर्ष पूर्व आलोचना पर अपने मित्रों के समूह में बोलते हुए यह विचार मैंने प्रकट किए थे। वे पत्थर की लकीर हैं। लेखक का साहित्य के विकास में महत्व है या नहीं है यह विवादास्पद विषय हो सकता है पर किसी साहित्यिक के विकास में किसी आलोचक का महत्व सर्वस्वीकृत है। साहित्य की वैतरणी तरना हो तो किसी आलोचक गैया की पूँछ पकड़ो, फिर सींग चलाने का काम उसका और यश बटोरने का काम कमलमुख का।

आलोचना के प्रति अपनी प्राइवेट राय जाहिर करने के पूर्व मैं आपको यह बताऊँ कि आलोचना है क्या? यह प्रश्न मुझसे अकसर पूछा जाता है। साहित्य रत्न की छात्राएँ चूँकि आलोचना समझने को सबसे ज्यादा उत्सुक दिखाई देती हैं इसलिए यह मानना गलत न होगा कि आलोचना साहित्य की सबसे टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इसलिए कि मैं कभी इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाता। मैं मुस्कराकर उन लड़कियों को कनखियों से देखकर कह देता हूँ, 'यह किसी आलोचक से पूछिए, मैं तो कलाकार हूँ।'

खैर, विषय पर आ जाऊँ। आलोचना शब्द लुच् धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। लुच् धातु से ही बना है लुच्चा। आलोचक के स्थान पर आलुच्चा या सिर्फ लुच्चा शब्द हिंदी में खप सकता है। मैंने एक बार खपाने की कोशिश भी की थी, एक सुप्रसिद्ध आलोचक महोदय को सभा में परिचित कराते समय पिछली जनवरी में वातावरण बहुत बिगड़ा। मुझे इस शब्द के पक्ष में भयंकर संघर्ष करना पड़ा। आलोचक महोदय ने कहा कि आप शब्द वापस लीजिए। जनता ने भी मुझे चारों ओर से घेर लिया। मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि हिंदी भाषा में नया शब्द देना कितना खतरा मोल लेना है। मैंने कहा, मैं शब्द वापस लेता हूँ। पर आप यह भूलिए नहीं कि आलोचना शब्द 'लुच' धातु से बना है।

अस्तु, बात आई गई हो गई। मैंने इस विषय में सोचना और चर्चा करना बंद सा कर दिया। पर यह गुत्थी मन में हमेशा बनी रही कि आलोचक का दायित्व क्या है? वास्तव में साहित्य के विशाल गोदाम में घुसकर बेकार माल की छँटाई करना और अच्छे माल को शो-केस में रखवाना आलोचक का काम माना गया है, जिसे वह करता नहीं। वह इस चक्कर में रहता है कि अपने परिचितों और पंथ वालों का माल रहने दें, बाकी सबका फिंकवा दें। यह शुभ प्रवृत्ति है और आज नहीं तो कल इसके लाभ नजर आते हैं। कोशिश करते रहना समीक्षक का धर्म है। जैसे हिंदी में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि मैथिलीशरण गुप्त, निराला और कविवर कमलमुख में कौन सर्वश्रेष्ठ है। एक राष्ट्रकवि है। एक बहुप्रशंसित है और तीसरे से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

समीक्षकों के इस उत्तरदायित्वहीन मूड के बावजूद पिछला दशक हिंदी आलोचना का स्वर्णयुग था। जितनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई उनसे अधिक आलोचकों को सादर भेंट प्राप्त हुई हैं। कुछ पुस्तकों का संपूर्ण संस्करण ही आलोचकों को सादर भेंट करने में समाप्त हो गया। समीक्षा की नई भाषा, नई शैली का विकास पिछले दशक में हुआ है। (दशक की ही चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आलोचक व्यक्तित्व का कँटीला विकास भी इसी दशक में हुआ है)। हिंदी का मैदान उस समय तक सूना था जब तक आलोचना की इस खंजर शब्दावली का जन्म नहीं हुआ था। इस शब्दावली के विशेषज्ञों का प्रकाशक की दुकान पर बड़ा स्वागत होते देखा है। प्रकाशक आलोचक पालते हैं और यदि इस क्षेत्र में मेरा जरा भी नाम हुआ तो विश्वास रखिए, किसी प्रकाशक से मेरा लाभ का सिलसिला जम जाएगा।

मैंने अपने आलोचक जीवन के शैशव काल में कतिपय प्रचलित शब्दावली, मुहावरावली और वाक्यावली का अनूठा संकलन किया था जिसे आज भी जब-तब उपयोग करता रहता हूँ। किसी पुस्तक के समर्थन तथा विरोध में किस प्रकार के वाक्य लिखे जाने चाहिए, उसके कतिपय थर्ड क्लास नमूने उदाहरणार्थ यहाँ दे रहा हूँ। अच्छे उदाहरण इस कारण नहीं दे रहा हूँ कि हमारे अनेक समीक्षक उसका उपयोग शुरू कर देंगे।

समर्थन की बातें

इस दृष्टि से रचना बेजोड़ है (दृष्टि कोई भी हो)। रचना में छुपा हुआ निष्कलुष वात्सल्य, निश्छल अभिव्यक्ति मन को छूती है। छपाई, सफाई विशेष आकर्षक है।

रूप और भावों के साथ जो विचारों के प्रतीक उभरते हैं, उससे कवि की शक्ति व संभावनाओं के प्रति आस्था बनती है।

कमलमुख की कलम चूम लेने को जी चाहता है। (दत्तू पानवाला की, यह मेरे विषय में व्यक्त राय देते हुए संकोच उत्पन्न हो रहा है परंतु उनके विशेष आग्रह को टाल भी तो नहीं सकता)।

मनोगुंफों की तहों में इतना गहरा घुसने वाला कलाकार हिंदी उपन्यास ने दूसरा पैदा नहीं किया।

कविता संसार

अरी बरखा तुम खूब बरसना

अशोक पटेल 'आशु'

बरखा आये घटा छाए,
प्रीत-प्रिया की याद सताए।
अरी बरखा तुम खूब बरसना
अंतरमन मेरा ये भीग जाए।

बर्षों से है मन मेरा प्यासा,
प्यास मेरी यह बुझ जाए।
रोम-रोम है मन मेरा आतुर
तुझसे मिलना हो जाये।

उमड़-घुमड़ के बरखा बरसे
बदरा बैरन बिजली चमके।
तुम बिन बरखा सुना लागे
धक-धक मेरा दिल ये धड़के।

अरी बरखा तुम भूल न जाना
नित-अहर्निश बारिश करना।
दर्द उठे जब इस दिल में मेरा
तन-मन को भीगा तुम जाना।

भूल न जाना दूर न जाना
ऐ बादल की तुम बरखा।
ऐसी बारिश हरदम करना
मुझसे प्रीत बनाये रखना।

मंदिर, राम सेतु और राजनीति: कैसे बदलते रहे नेताओं के सुर

-संजय सक्सेना

भारतीय राजनीति में भगवान राम का नाम दशकों से एक संवेदनशील और विवादित विषय रहा है। समय-समय पर अलग-अलग दलों और नेताओं के बयानों ने इस मुद्दे को गर्माया है, और हर बार यह बहस नए सिरे से शुरू हो जाती है कि कौन राम के प्रति कैसा नजरिया रखता है।2007 में केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सेतुसमुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इस हलफनामे में यह तर्क दिया गया था कि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माने जा सकते, और इसलिए राम सेतु के अस्तित्व को पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस हलफनामे पर देशभर में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा और तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। इस घटना को आज भी बीजेपी और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन कांग्रेस के खिलाफ एक प्रमुख राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम राम मंदिर आंदोलन के दौर से जुड़ा रहा है। 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन आज भी उन्हें निशाना बनाते हैं। संसद और सार्वजनिक मंचों पर उनके कुछ बयानों को लेकर भी विवाद हुए, जिनमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक प्रमाणों पर सवाल उठाने की बात कही जाती रही है। हालांकि, सपा नेता इन आरोपों को अक्सर संदर्भ से काटकर पेश किए जाने की बात कहते रहे हैं। 'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम' यह नारा 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा-बसपा गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और उसके समर्थकों की ओर से गढ़ा गया था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि सपा-बसपा गठबंधन हिंदुत्व की राजनीति के विरोध में खड़ा है। यह नारा आज भी चुनावी भाषणों में सपा को घेरने के लिए इस्तेमाल होता है।आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद को 'हिंदू' बताते हुए मंदिरों में पूजा-अर्चना करते और जनेऊ पहनते नजर आते हैं। आलोचक इसे चुनावी रणनीति बताते हैं, जबकि सपा नेताओं का कहना है कि यह उनकी निजी आस्था है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी की राजनीति मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण पर आधारित है, और इस वजह से राम मंदिर जैसे मुद्दों पर उनका रुख हमेशा सतर्क और गोलमोल रहा है।

गगनयान के परीक्षणों में इसरो को मिली बड़ी सफलता

- महेन्द्र तिवारी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता और दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपने इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) यानी सॉल्वे सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अत्यंत जटिल तकनीक में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग चार सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना और तीन दिन के सफल मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस पूरे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू अंतरिक्ष यात्रियों की पुख्ता सुरक्षा है और हाल ही में किए गए ये परीक्षण सीधे तौर पर इसी सुरक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

सॉल्वे सॉलिड मोटर का सफल परीक्षण क्रू एस्केप सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। यह एक विशेष प्रकार

का रॉकेट है जिसे इसरो ने विशेष रूप से केवल गगनयान के क्रू मॉड्यूल के उड़ान परीक्षणों के लिए विकसित किया है। इस सॉलिड मोटर को पीएसएलवी रॉकेट के स्ट्रैप ऑन मोटर के आधार पर तैयार किया गया है लेकिन इसमें गगनयान मिशन की विशेष और सख्त आवश्यकताओं के अनुसार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें धीमी गति से जलने वाले प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया है ताकि यह आवश्यक समय तक लगातार और नियंत्रित ऊर्जा प्रदान कर सके। इसके साथ ही इसमें सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी अत्यधिक उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक रॉकेट की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है। इस मोटर का मुख्य काम उड़ान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को मुख्य रॉकेट से तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर खींच ले जाना है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया यह ग्राउंड टेस्ट यह साबित करता है कि मोटर का प्रदर्शन इसरो के कड़े मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है।

इसके साथ ही इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट भी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से अपना मिशन पूरा करके वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसकी गति अत्यधिक तीव्र होगी। इस भयंकर गति को कम करने और भारी क्रू मॉड्यूल को समुद्र की सतह पर बहुत ही सुरक्षित रूप से उतारने के लिए पैराशूट प्रणाली का बिना किसी चूक के काम करना आवश्यक है। इसरो ने इस रिकवरी प्रणाली में कुल दस पैराशूट्स का एक जटिल और अचूक नेटवर्क तैयार किया है। इस प्रणाली के तहत सबसे पहले एपेक्स कवर अलग होता है जिसके तुरंत बाद गति को कम करने के लिए दो ड्रोग पैराशूट खुलते हैं। जब मॉड्यूल की तेज गति कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है तो अंत में तीन विशाल मुख्य पैराशूट खुलते हैं जो क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के पानी में बेहद सुरक्षित और धीमी गति से लैंड कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्पलैशडाउन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट की शानदार सफलता यह सुनिश्चित करती है कि पैराशूट खुलने की टाइमिंग और उनका तनाव सहने की क्षमता बिल्कुल सटीक है।

गगनयान मिशन भारत के लिए कई मायनों में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। इंसानों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजना केवल उपग्रह भेजने से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए इसरो अपने सबसे भारी और भरोसेमंद रॉकेट एलवीएम थ्री का उपयोग कर रहा है जिसे मानव उड़ान के अनुकूल बनाने के लिए ह्यूमन रेटेड किया जा रहा है। ह्यूमन रेटिंग का सीधा अर्थ यह है कि रॉकेट का हर एक पुर्जा और हर एक प्रणाली शत प्रतिशत सुरक्षित और भरोसेमंद होनी चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मॉड्यूल के भीतर एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए इसरो एक विशेष पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार ऑक्सीजन प्रदान करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी को नियंत्रित रखेगी। यह उन्नत प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो भारतीय वैज्ञानिकों की असीमित बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।

अंतरिक्ष से वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। जब यह मॉड्यूल वायुमंडल की घनी परतों से तेज गति से टकराता है तो घर्षण के कारण उसका बाहरी तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक और जानलेवा गर्मी से अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए क्रू मॉड्यूल के बाहरी हिस्से पर एक विशेष प्रकार का थर्मल हीट शील्ड लगाया गया है। यह शील्ड मॉड्यूल के भीतर के तापमान को बिल्कुल सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसरो ने इस हीट शील्ड का निर्माण भी स्वदेशी रूप से किया है और इसके कई सफल परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं।

शक्तिधाम स्थापना दिवस पर भक्तों का उमड़ा हुजूम

● 61 यूनिट रक्तदान कर दिया जनसेवा का संदेश

राजनांदगांव। शहर के वार्ड नंबर 1 स्थित शक्तिधाम महाकाली मंदिर में आज 6वां स्थापना दिवस भक्तिमय माहौल में धूमधाम से मनाया गया। प्रातः मां काली की अघोर महाआरती पश्चात वृक्षारोपण, रक्तदान एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जहां आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. प्रज्ञा सक्सेना एवं उनकी टीम ने सेवाएं दी। स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में ग्राम सहित दूर-दराज से आये लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया, वहीं रक्तदान में दूर-दराज से आये माता के भक्तों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए।

आज शहर के बाबुटोला वार्ड नंबर 1 स्थित शक्तिधाम महाकाली मंदिर में 6वां स्थापना दिवस भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री अनुप श्रीवास एवं शहर के प्रतिष्ठित अलौपैथीक विशेषज्ञ डॉ. उत्तम चावड़ा, भजन गायक व समाजसेवी चंद्रेश जैन उपस्थित रहे। उन्होंने मां काली की पूजा-अर्चना पश्चात मंदिर समिति के स्थापना दिवस पर शुभकामनायें दी एवं उज्वल भविष्य की कामना की।

मंदिर समिति के संस्थापक गुरुदेव हरीश यादव ने रक्तदान कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शक्तिधाम महाकाली मंदिर के प्रधान संस्थापक व मुख्या गुरुदेव हरीश यादव ने बताया कि इस वर्ष शक्तिधाम के स्थापना दिवस पर प्रातः मां महाकाली की आरती पश्चात छाया प्रदान करने वाले वृक्षों का रोपण किया गया। समिति के सदस्यों सहित दूर-दराज से आये माता के भक्तों ने 61 यूनिट ब्लड डोनेट किये। समिति द्वारा आयुर्वेद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसे लोगों का अच्छा प्रतिफल मिला।

टीम भिलाई एंथम ने याद किया तीजन बाई का योगदान

जनधारा समाचार

भिलाई। वर्ष 2018 में इस्पात नगरी भिलाई पर आधारित भिलाई एंथम तैयार करने वाली टीम ने पद्मविभूषण स्व. तीजन बाई के योगदान को याद किया है। टीम भिलाई एंथम ने तीजन बाई को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। टीम की संयोजक प्रोफेसर सुस्मिता बसु मजुमदार ने कहा कि अपने शहर भिलाई को एक आदरांजलि देने उन्होंने इसकी रचना की थी और पूरी टीम का मानना था कि इसकी शुरूआत छत्तीसगढ़ की धरोहर पद्मविभूषण तीजन बाई से होनी चाहिए। ऐसे में सीनियर सेकंडरी स्कूल सेक्टर-10 के 1988 बैच से बनीं टीम उनसे मिली थी।

बसु ने बताया कि भिलाई एंथम में वह अपनी लिखी लाइन से तीजन बाई से शुरूआत करवाना चाहती थीं लेकिन तीजन बाई ने कहा कि वह पंडवानी के अलावा कुछ और नहीं गा सकतीं। इसलिए टीम ने तय किया कि उनसे पंडवानी ही गाने कहेंगे। इस पर वे राजी हो गईं और रायपुर के स्टूडियो में पहुंच कर उन्होंने रिकार्डिंग के लिए पंडवानी गाना शुरू किया। बसु ने कहा कि शिफॉन की साड़ी और बिना आस्तीन वाले ब्लाउज़ में पंडवानी गाते हुए उन्हें हम सब मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। उन्होंने पूरे 45 मिनट अपने गायन से एक ऐसा जादू जगा दिया, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।

सुस्मिता ने कहा कि भिलाई एंथम के लॉन्च से ठीक पहले तीजन बाई को सीने में दर्द के कारण सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसे में वह लॉन्च में शामिल नहीं हो पाईं, जहाँ भिलाई से जुड़ी प्रख्यात हस्तियों अनुराग बसु, अरुंधति भट्टाचार्य, अनुज शर्मा, अमित साना, पामेला जैन, तत्कालीन सीईओ एम. रवि और भिलाई एंथम टीम के सदस्य मौजूद रहने वाले थे।

ऐसे में लॉन्च से पहले सुबह टीम भिलाई एंथम उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची। तब तीजन बाई लॉन्च में न आ पाने के कारण बहुत दुखी थीं, लेकिन साथ ही उनकी मुस्कान बता रही थी कि वह बहुत खुश भी थीं, क्योंकि टीम ने लॉन्च से पहले उन्हें भिलाई एंथम की एक सीडी की कॉपी और एक छोटा सा सितार भेंट किया। टीम का मानना है कि भिलाई एंथम का वास्तविक लांचिंग तीजन बाई के हाथों भेंट की गई सीडी के दौरान के लम्हे को मानते हैं। तब तीजन बाई ने खूब खुशी जाहिर की थी और पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी थी। पंडवानी गुरु तीजन बाई के निधन की खबर मिलने पर टीम भिलाई एंथम से जुड़े देश-विदेश के भिलाईयंस ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है।

एआई के ज्योतिष पर प्रभाव को लेकर मंथन हुआ

● ज्योतिष और संस्कृत के नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा

भिलाई। ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान, छत्तीसगढ़ की ओर से भिलाई निवास स्थित कॉफी हाउस में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह तकनीकी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें देशभर के 65 से अधिक प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्यों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रख्यात शिक्षाविद् और श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन आई. पी. मिश्रा ने कहा कि हमारे रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान का सार दिया गया है, वही हमारी असली ताकत है। मनुष्य की मेधा (बुद्धिमत्ता) और उसकी अंतर्दृष्टि को दुनिया की कोई भी मशीन या एआई कभी भी चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने इस दौरान श्री मिश्रा घोषणा की कि श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विश्वविद्यालय स्तर पर ज्योतिष और संस्कृत के नियमित कोर्स की शुरुआत की जाएगी।

अध्यक्षता कर रहे सेफी एवं भिलाई स्टील प्लांट ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. के. बंछोर ने कहा कि तकनीक जब हमारे नियंत्रण में रहेगी, तो वह ज्योतिष विज्ञान को और अधिक समृद्ध करेगी। समापन सत्र में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप, शिक्षाविद् प्रवीण तिवारी तथा उद्योगपति वीरेंद्र शुक्ला ने भी अपने विचार रखे।

संस्थान के मार्गदर्शक उमेश चितलांगिया ने वैदिक संस्कृत श्लोकों के माध्यम से पूरे एआई और ज्योतिष की आंतरिक संरचना व उनके अंतर्संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से समझाया। तकनीकी सत्र के मुख्य विषय विशेषज्ञ उदय रेड्डी ने पारंपरिक ज्योतिषियों को आधुनिक युग में स्थापित होने के डिजिटल मंत्र दिए।

वर्कशॉप के एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में संस्थान के महासचिव कार्यक्रम के सूत्रधार व मंच संचालक नंदलाल चौधरी ने लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से एआई द्वारा एक जीवंत कुंडली का विश्लेषण करने का तरीका सिखाया। अरुण सावने ने कहा कि ज्योतिषाचार्य एआई का उपयोग सिर्फ किसी एक विधा तक सीमित न रखें। ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान के अध्यक्ष बी. एम. बाली ने विपरीत स्वास्थ्य के बावजूद आयोजन में भागीदारी दी। उन्होंने एआई के प्रभावी उपयोग पर सारगर्भित प्रस्तुति दी।

यंग इंडियन पार्लियामेंट प्रतियोगिता में गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने बढ़ाया विद्यालय का गौरव

राजनांदगांव। शिक्षा एवं संस्कार के क्षेत्र में अग्रणी जिले की प्रतिष्ठित शाला गायत्री विद्यापीठ में लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रभावी संवाद कौशल तथा नेतृत्व क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित यंग इंडियन पार्लियामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के दो विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया। उक्त प्रतियोगिता युगांतर पब्लिक स्कूल में आयोजित था, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से 150 प्रतिभागी विद्यार्थियों के बीच विद्यालय के दो प्रतिभावान विद्यार्थी प्रियल राजा एवं हीरल भिमजियानी का चयन किया गया। प्रियल राजा को अपने प्रभावशाली, तार्किक एवं ओजस्वी वक्तव्य के लिए बेस्ट स्पीकर अवार्ड एवं हीरल भिमजियानी को सर्वोत्कृष्ट प्रश्नमंच के लिए मोस्ट परसुएसिव पॉलिसी एडवोकेट अवार्ड दिया गया। दोनों ही विद्यार्थी अगले चरण की प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

गायत्री शिक्षण समिति के अध्यक्ष डॉ. बृजकिशोर सुरजन द्वारा विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा किया कि यंग इंडियन पार्लियामेंट केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने का सशक्त मंच है। इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, नेतृत्व क्षमता, प्रभावी अभिव्यक्ति, टीम भावना, अनुशासन और समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता का विकास करते हैं। ऐसे मंच युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। गायत्री विद्यापीठ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ जीवन जीने की कला सिखाकर इस प्रकार के प्रतियोगिता हेतु एक अच्छा मंच प्रदान किया जाता है। यह इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी इस प्रकार की प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना रहे हैं।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के सीबीएसई प्राचार्य अंकित व्यास ने दोनों विद्यार्थियों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना भी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य 11 विद्यार्थियों को भी शानदार प्रस्तुति के लिए विशेष सम्मान दिया गया।

बारिश के साथ दिखने लगा 'मोर गांव-मोर पानी' अभियान का असर

दुर्ग। मानसून की सक्रियता के साथ ही जिले में संचालित मोर गांव मोर पानी महाअभियान के सकारात्मक परिणाम अब गांव-गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से हुई अच्छी वर्षा के कारण अभियान के तहत निर्मित आजीविका डबरियां, नवा तरिया तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाएं तेजी से पानी से भर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को नई मजबूती मिल रही है। सीईओ जिला पंचायत बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में एक ही वित्तीय वर्ष में 55,965 वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच, 15 परकोलेशन पॉण्ड, 834 रिचार्ज पिट, 1324 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं, 9663 सोख्ता गड्ढे, 123 ग्राम तालाब, 20518 कंटूर ट्रेंच, 26 चेक डैम तथा 28 बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया गया।

भू-जल स्तर बढ़ाने तथा वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 एवं मनरेगा के प्रभावी समन्वय से व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए गए हैं।

जिला स्तरीय रोजगार मेला 10 जुलाई को

दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय जिला-दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में 10 जुलाई 2026 को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय नया भवन परिसर पोटिया दुर्ग में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक रोजगार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त रोजगार मेला हेतु कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आई.टी.आई., डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग स्नातक, एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., नर्सिंग, जी.एन.एम., ए.एन.एम., डिप्लोमा पैरामेडिकल एवं अन्य योग्यताधारी आवेदकों के लिए कुल 15 नियोजकों से 1342 तकनीकी एवं गैर तकनीकी रिक्तियों प्राप्त हो चुकी है जो 08 जुलाई 2026 तक बढ़ सकती है एवं जिसकी जानकारी रोजगार विभाग के वेबसाईट अथवा छत्तीसगढ़ रोजगार एप पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है जिसके लिए रोजगार पंजीयन करवाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए जिला

न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली-1, (चकरभाठा) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

//उद्घोषणा//

मामला क्रमांक :- 202606251200004/अ-27/2025-26
ग्राम - टेमरी, प.ह.नं. 38
तहसील व जिला मुंगेली (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक फेकूराम पिता हंसाराम निवासी ग्राम टेमरी तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.) द्वारा ग्राम टेमरी प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. टेमरी स्थित भूमि खसरा नंबर 169/4, 169/5 रकबा क्रमशः 0.923, 0.809 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेख में बटवारा हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में यदि किसी को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे अपना दावा/आपत्ति दिनांक 15.07.2026 के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उद्घोषणा आज दिनांक 22.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील — **नायब तहसीलदार मुंगेली (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली-2 (खेरा-सेतगंगा) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

-: ईश्तहार:-

रा.प्र.क्र/...../ब-121/2025-26
ग्राम तालम प.ह.नं. ....
तहसील व जिला मुंगेली

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका रोशनी कुर्रे पिता यशवंत कुर्रे जाति सतनामी साकिन तालम तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.) द्वारा ग्राम तालम प.ह.नं. .... तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने स्वयं का जन्म दिनांक 15.11.2005 को होने के फलस्वरूप नगरपालिका/सचिव ग्राम पंचायत नागोपहरी के पंजी में जर्द कराने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

ततसंबंध में यदि किसी को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वह स्वयं अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 14.07.26 समय प्रातः 11.00 बजे दावा/आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है । निर्धारित समयावधी पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

ईश्तहार आज दिनांक 30.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया ।

सील — **कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली-1 (चकरभाठा) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

-: ईश्तहार:-

ई-कोर्ट प्रकरण क्रमांक 202606251200011/अ-6-अ/2025-26
ग्राम चकरभाठा प.ह.नं. 37
तहसील व जिला-मुगेली (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मधुरराम साहू पिता पेखनराम साहू निवासी ग्रमा चकरभाठा, तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.) द्वारा ग्राम चकरभाठा प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. टेमरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1484/1, 1486/1 रकबा क्रमशः 0.206, 0.364 हेक्टेयर के ऑनलाईन राजस्व अभिलेख में मधुराम दर्ज है । जो त्रुटिपूर्ण है । जिसे सुधार कर मधुरराम साहू दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

इस संबंध में यदि किसी को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे अपना दावा/आपत्ति ईश्तहार प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ईश्तहार आज दिनांक 19.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया ।

सील — **नायब तहसीलदार मुंगेली (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली-1 (चकरभाठा) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

-: ईश्तहार:-

मामला क्रमांक Q/अ-6-अ/2025-26
ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 30
तहसील व जिला-मुगेली (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अगमदास पिता स्व. हरीराम कांत निवासी ग्राम ठेंगा, तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.) द्वारा ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. खैरा-सेतगंगा स्थित भूमि खसरा नंबर 32/7, 37/4 रकबा क्रमशः 0.320, 0.276 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में परषोत्तम आ. जुलाराम वगैरह के नाम पर दर्ज है एवं खसरा नंबर 32/3 रकबा 0.214 हेक्टेयर जिसमें OFXBH पिता DF2GZ पता FG दर्शित है । अतः ऑनलाईन राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटि को सुधार कराने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है ।

इस संबंध में यदि किसी को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे अपना दावा/आपत्ति दिनांक 13.07.2026 के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

ईश्तहार आज दिनांक 30.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया ।

सील — **नायब तहसीलदार मुंगेली (छ.ग.)**

सुपोषण के लिए जनआंदोलन बनेगा सुपोषण वृक्ष-मुनगा अभियान

● महापौर अलका बाघमार ने लगाया मुनगा पौधा

दुर्ग। मुख्यमंत्री की मंशानुसार कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण वृक्ष-मुनगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी 222 आंगनबाड़ी केंद्रों में मुनगा के पौधों का रोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य मुनगा के पौष्टिक गुणों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप देना है।

इसी कड़ी में आज पोलसाय पारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महापौर अलका बाघमार ने मुनगा का पौधा रोपकर अभियान का शुभारंभ किया। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि मुनगा को सुपोषण का वृक्ष कहा जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों एवं अन्य भागों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके नियमित उपयोग से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ यह अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला सामाजिक अभियान है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्रत्येक परिवार अपने घर, आंगन, खेत, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर मुनगा के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प ले।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.) | Regional Office, Ambikapur (C.G.)

वाहन नीलामी सूचना

बैंक निम्नलिखित जब्त वाहन की बिक्री के लिए **"जहां है जैसा है"**, **"जो है जैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर सीलबंद बोली आमंत्रित करता है।

स. क्र.	ऋणी का नाम एवं पता	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक	बकाया राशि / शाखा, सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नं.	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि
01	**श्रीमती सोनिया अग्रवाल** कटंगडीह, छोटेगुमदा, घरघोड़ा, रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496665	संपत्ति का प्रकार- ट्रक, मेक और मॉडल- आयशर प्रो 2114 एक्सपी एल 2022 पंजीकरण संख्या CG13AS7663 चेसिस संख्या- MC2ESLRC0NF210659	कुडेकेला - सुमन बागे मो. 70004 28565 ₹ 29,52,584.15 06/07/2026 से साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज और खर्च	₹ 7,00,000/- ₹ 70,000/-

निरीक्षण की तिथि एवं समयः 22/07/2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच

1) वाहन के निरीक्षण के लिए, कृपया संबंधित शाखा प्रबंधक से परामर्श लें। 2) बोलियाँ क्षेत्रीय कार्यालय, भूतल, धनजल कॉम्प्लेक्स, नेमनाकल, अंबिकापुर में **23/07/2026 को अपराह्न 3 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। 3) बोलियाँ **23/07/2026 को अपराह्न 4:00 बजे** खोली जाएँगी। उच्चतम बोली स्वीकार की जाएगी। 4) उच्चतम बोली लगाने वाले को उसी दिन ऊपर बताए अनुसार **10%** अग्रिम राशि जमा करनी होगी और शेष राशि **24/07/2026** तक जमा करनी होगी। 5) पूरी राशि जमा करने के बाद, वाहन सफल बोली लगाने वाले को सौंप दिया जाएगा। 6) यदि सफल बोली लगाने वाला शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तो पहले जमा की गई अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। 7) बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने और नीलामी को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 8) वाहन, बोली प्रक्रिया और बोली के प्रारूप के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें। 9) यह उपर्युक्त उधारकर्ताओं और आम जनता की जानकारी के लिए है। 10) यदि कानून के अनुसार कोई जीएसटी है तो वह अलग से देय होगा।

दिनांक : 07.07.2026 स्थानः अंबिकापुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

नामांतरण सूचना विज्ञप्ति क्रमांक 17 वर्ष 2026-27

सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके नाम के सामने भूमि/भवन स्वामित्व परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

संबंधित हित वाले व्यक्ति सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अपने आपत्ति लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

स. क्र.	ना. प्र.क्र.	क्रेता का नाम	विक्रेता का नाम	वार्ड क्रमांक	नाम परिवर्तन का आधार जिस पर दावा/आपत्ति की जानी है
330	330	उमेश कुमार साहू आ. महेश साहू	नीतिन श्रीवास्तव आ. स्व. सतीश कुमार	वार्ड क्रमांक-57 उरला (पश्चिम)	पंजीकृत बयनामा
331	331	जयंती देवी आर. साहू पति गिरीश कुमार साहू विमल साहू, गिरीश कुमार विमल साहू, आ. भीमसेन साहू	अजमेर कौर पति दारा सिंह, गुरदीप सिंह कबरवाल, दलजीत सिंह कबरवाल, गुरप्रीत सिंह कबरवाल आ. स्व. दारा सिंह कबरवाल	वार्ड क्रमांक-24 आमदी मंदिर वार्ड	पंजीकत बयनामा
332	332	आशा गोलछा पति श्रीपाल गोलछा	भावना जैन पति सुनील कुमार चोपड़ा	वार्ड क्रमांक-23 दीप नगर	पंजीकृत बयनामा
333	333	युसुफ खान आ. स्व. हिम्मत खान	हिम्मत खान आ. बलदार खान	वार्ड क्रमांक-44 बाबा गुरूघासीदास	संधारण खसरा
334	334	पूजा अर्जुन गुरमे आ. अर्जुन गुरमे	राजकुमारी गुप्ता आ. राजकुमार गुप्ता	वार्ड क्रमांक-54 पोटियाकला (दक्षिण)	पंजीकृत बयनामा
335	335	एस. कीर्ति पिता एस. ईश्वरा राव	नारायण सिंह विष्ठ पिता बी.एम.विष्ठ	वार्ड क्रमांक-60 कातुलबोर्ड (दक्षिण)	पंजीकृत बयनामा
336	336	प्रफुल्ल गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रशांत गुप्ता आ. स्व. रामलखन गुप्ता	डॉ. आर.एल. गुप्ता आ. स्व. बलदेव सिंह गुप्ता	वार्ड क्रमांक-25 गायत्री मंदिर	न्याय नजूल जांच अधि. का आदेश, दिनांक-14.07.2021
337	337	प्रफुल्ल गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रशांत गुप्ता आ. स्व. रामलखन गुप्ता	सावित्री गुप्ता पति डॉ. आर.एल. गुप्ता	वार्ड क्रमांक-25 गायत्री मंदिर	न्याय नजूल जांच अधि. का आदेश, दिनांक-14.07.2021
338	338	प्रमोद फिलिप आ. स्व. एन.के. फिलिपोस	सारम्मा पति स्व. एन.के. फिलिपोस, फिलिप विनोद, शैला राजन आ. स्व. एन.के. फिलिपोस	वार्ड क्रमांक-23 दीपक नगर	हक-त्याग पत्र
339	339	किरण पटेल पति अनिरूद्ध कुमार पटेल	अवनिकांत सिंह आ. जयनारायण सिंह	वार्ड क्रमांक-16 सिकोला बस्ती (उत्तर)	पंजीकृत बयनामा
340	340	सूरज निषाद, चांदनी निषाद आ. ललतू निषाद	हलाल खोर/अलख/बल्लू/सूरित केंवट	वार्ड क्रमांक-56 वधेरा	बटवारा नामा
341	341	अनिदीता यादव पति भृगुनाथ यादव	अंकुश जैन आ. गेनमल जैन	वार्ड क्रमांक-59 कातुलबोर्ड (पूर्व)	पंजीकृत बयनामा

सहायक राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम, दुर्ग

राम मंदिर चढ़ावा मामले की सीबीआई जांच की मांग

● विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने केंद्र सरकार से की कार्रवाई की अपील

राजनांदगांव। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस घटना से देश-दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है।

विश्व हिंदू रक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक सोनी ने एक बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में इस मामले की जो जांच चल रही है, वह बेहद शुरुआती और छोटे स्तर की है। इस महाघोटाले और चोरी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है।

दीपक सोनी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि राम मंदिर पूरे विश्व के सनातनी हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। वहां के चढ़ावे में हेरफेर या चोरी की बात सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को इस मामले को पूरी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि सीबीआई जांच के जरिए इस बात का पता लगाया जाए कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन-कौन लोग संलिप्त हैं। दीपक सोनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मामले में शामिल हर छोटे-बड़े दोषी पर केंद्र सरकार ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो एक मिसाल बने। ताकि भविष्य में देश के किसी भी अन्य मंदिर में इस तरह की दुस्साहसपूर्ण घटना दोबारा न हो सके।

Chola Enter a better life
चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी-54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुइंडी, चेन्नई- 600 032.
शाखा कार्यालयः शॉप नं. 7वीं, करेंसी टावर, वीआईपी चौक, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर, छ.ग. 492001

नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि **मे. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनांस कम्पनी लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, **2002** के तहत इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा तथा **13(2)** के तहत सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन नियम, **2002** के नियम **3** के साथ पढ़ा जाए के तहत कर्जदारों को कॉल करते हुए सुरक्षा अधिकारों का उपयोग करके **डिमांड नोटिस** जारी किया, जिनके नाम कॉलम **सी** में विनिर्दिष्ट तारीखों के नीचे कॉलम **बी** में दिए गए हैं उन्हें कॉलम **डी** में दी गई बकाया राशि नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर ब्याज सहित चुकानी है। कर्जदार के राशि चुकाने में नाकाम रहने पर, यह नोटिस विशेष रुप से कर्जदारों को और सामान्य रुप से सार्वजनिक तौर पर दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी के अधिनियम की धारा **13(4)** के तहत नियम **3** के साथ पढ़ा जाए उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके साथ यहां कॉलम **एफ** में उल्लेखित नीचे दी गई संबंधित तारीखों पर कॉलम **ई** में वर्णित कम्पनी के पास गिरवी रखी गई संपत्ति पर भी **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है। विशेष रुप से कर्जदारों को और सामान्य रुप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि नीचे कॉलम **ई** में उल्लिखित संपत्तियों का सौदा न किया जाए और ऐसा कोई भी सौदा कॉलम **डी** में ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ वर्णित राशि के लिए **मे. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनांस कम्पनी लिमिटेड** के प्रभार के तहत होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा **13(8)** के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागत, शुल्कों और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करके सुरक्षित परिसंपत्ति का भुगतान कर सकते हैं।

कर्जदार का नाम/ ऋण खाता सं. एवं पता	मांग सूचना/ कब्जा सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जे की संपत्ति का विवरण
ऋण खाता - X0HERRH00003226064 X0HERRH00004142462 1. **जसकवर सिंह ढिल्लों पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह ढिल्लों (आवेदक),** 2. **परमिंदर कौर पति सुरेंद्र पाल सिंह ढिल्लों (सह आवेदक), दोनों का पताः निवासी-** एल.आई.जी.-I/42, स्लाइस-II, वीर सावरकर नगर, जरवाय अलियास, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.)- 492099. 3. **मेसर्स आंध्रा रोड कैरियर (सह-आवेदक),** इसके मालिक **जसकवर सिंह ढिल्लों** के माध्यम से, नुक्कड़ पेट्रोल पंप के पास, रिंग रोड नं. 2, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.) - 492099. 4. **मेसर्स अगम ट्रेडर्स (सह-आवेदक),** इसके मालिक **जसकवर सिंह ढिल्लों** के माध्यम से- शिवानंद नगर, खमतराई, रायपुर (छ.ग.) 492008.	09/04/2026 03/07/2026	₹ **21,47,790.00** 09/04/2026 तक उस पर ब्याज के साथ.	खसरा नंबर- खसरा **610, 611** का भाग, मौजा- जरवाय उर्फ हीरापुर- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वीर सावरकर नगर वार्ड नं. 01, प.ह.नं. 103/35, रानि.मं.- रायपुर-1, तहसील व जिला- रायपुर (छ.ग.), क्षेत्रफल **90** वर्ग मीटर या **968.4** वर्ग फुट में स्थित आवासीय संपत्ति लॉट नंबर एल.आई.जी.-I/42, स्लाइस-II के समस्त भाग व अंश। **चौहद्दीः उत्तर-** एल.आई.जी.-I/43, **दक्षिण-** एल.आई.जी.-I/41, **पूर्व-सड़क, पश्चिम-** एल.आई.जी.-I/46.

दिनांकः 06.07.2026, स्थानः रायपुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी/ चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कं.लिमि.

स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य

न्यायालय के आदेश को ठेंगा बल पूर्वक किया जा रहा है निर्माण

सूरजपुर। भैयाथान प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार कर जबरन कब्जा और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भैयाथान तहसीलदार कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम सिरसी में एक विवादित भूखंड पर बेदखली आदेश के बावजूद धड़ल्ले से किए जा रहे पक्के निर्माण कार्य पर तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से रोक स्थगन आदेश लगा दी है। लेकिन फिर भी जबरन निर्माण कार्य करायाज रहा है कोर्ट ने अनावेदकों को कड़ी चेतावनी देते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ हाजिर होने का हुक्म सुनाया है।

ग्राम सिरसी निवासी आवेदक जयमंगल पिता दल्लू राम की स्वामित्व वाली भूमि खसरा नंबर 439, रकबा 0.17 हेक्टेयर पर गांव के ही आनंद पिता दिलसाय और लक्ष्मण पिता शेषमन द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया था। इस मामले में न्यायालय तहसीलदार भैयाथान द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.01.2025 को अनावेदकों को

बेदखल कर आवेदक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया जा चुका था।

पटवारी रिपोर्ट में खुलासा

इस आदेश के बावजूद, अनावेदकों द्वारा राजस्व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उक्त भूमि के सड़क वाले हिस्से को तोड़कर वहां पक्के का सीट-युक्त मकान बनाया जा रहा था। हल्का पटवारी की जांच प्रतिवेदन में इस अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया।

तहसीलदार कोर्ट का कड़ा रुख

तहसीलदार भैयाथान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक जयमंगल के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। आगामी आदेश तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अनावेदकों को 09 जुलाई 2026 तक अपने आवश्यक राजस्व दस्तावेजों के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया गया है।

पुलिस को दिए गए सख्त निर्देश

मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाने के लिए तहसीलदार कोर्ट ने इस आदेश की प्रति थाना प्रभारी झिलमिली और चौकी प्रभारी बसदेई को भी भेजी है। पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर जाकर अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाएं और की गई कार्रवाई का पालन

प्रतिवेदन न्यायालय में सुनिश्चित करें। तहसील न्यायालय के स्थगन आदेश का परिपालन न करते हुए अनावेदक ने अन्यत्र ग्राम से मजदूर स्वरूप में लठेतों को बुलवाया था ताकि बलपूर्वक भवन निर्माण का कार्य किया जा सके जिनमें लगभग 20-25 लेबर मंगाकर निर्माण करवाया जा रहा था ताकि आवेदक गण यदि मौके पर रोक लगाने पहुंचे तो उन पर प्राण घातक हमला कर वहां से भगाया जा सके और भवन निर्माण आसानी से हो सके।

सूरजपुर में प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल

कलेक्टर-एसडीएम बदले, पर मलाईदार कुर्सियों पर अंगद की तरह जमे हैं प्रभारी मंडल संयोजक

जनधारा समाचार

सूरजपुर। जिला प्रशासन में पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस के बड़े-बड़े दावों के बीच सूरजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिले में प्रशासनिक सर्जरी के नाम पर कलेक्टर बदले, एसडीएम बदले, तहसीलदार बदले और यहां तक की अन्य विभागों के छोटे-से-छोटे कर्मचारियों के भी तबादले कर दिए गए। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला, तो वो हैं मलाईदार विभागों में वर्षों से अंगद के पांव की तरह जमे प्रभारी मंडल संयोजक। आखिर इन प्रभारियों पर प्रशासन की यह विशेष मेहरबानियों के क्या मायने हैं।

सूरजपुर में आदेशों की खुली अवहेलना: गौरतलब है कि पड़ोसी जिले एमसीबी में जिला कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक आदेश जारी कर सभी प्रभारी मंडल संयोजकों को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके मूल पद पर वापस भेज दिया है। इतना ही नहीं, राज्य के कई अन्य जिलों में भी शासन की मंशानुरूप प्रभारियों को हटाकर मूल पदस्थापना दी जा रही है। परंतु, सूरजपुर जिले में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। यहां राज्य सरकार के निर्देशों की सरेआम अवहेलना की जा रही है, जिससे संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली और मंशा दोनों ही संदेह के घेरे में हैं।

योग्य और काबिल कर्मचारियों की अनदेखी क्यों: जिले में एक से बढ़कर एक काबिल, वरिष्ठ और नियमित कर्मचारी मौजूद हैं, जो इन पदों की जिम्मेदारी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। इसके बावजूद नियमित अफसरों को दरकिनार कर चहेते प्रभारियों को मलाईदार कुर्सियां सौंपने के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा है

क्यों उठ रहे हैं प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल: प्रशासनिक नियम कहते हैं कि एक ही स्थान या पद पर लंबे समय तक जमे रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, लेकिन यहां सालों से एक ही चेहरा टिका हुआ है। मूल पद की जिम्मेदारियों को छोड़कर प्रभारी बनकर मलाईदार विभागों का सुख भोगने का यह सिलसिला चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रशासनिक साख पर बट्टा: जब शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकता है, तो इन प्रभारियों को किस सुरक्षा कवच के तहत बचाकर रखा गया है। जिले के जागरूक नागरिकों और कर्मचारियों में इस विसंगति को लेकर भारी आक्रोश है। अब देखना यह है कि पड़ोसी जिलों की तरह सूरजपुर जिला प्रशासन भी इस ढर्रे को बदलते हुए पारदर्शिता की नई मिसाल पेश करता है, या फिर ये प्रभारी इसी तरह व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए अपनी कुर्सियों पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे।

समय पर मिला खाद-बीज बना उम्मीद की नई फसल

एमसीबी। कहते हैं कि खेती में समय सबसे बड़ा धन होता है। यदि किसान को सही समय पर खाद, बीज और उर्वरक उपलब्ध हो जाएं तो उसकी आधी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम चैनपुर निवासी सीमांत किसान नरेन्द्र सिंह, पिता सुदन सिंह, के लिए भी इस खरीफ सीजन में यही अनुभव नई उम्मीद लेकर आया है।

नरेन्द्र सिंह के पास कुल 1.780 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें संपूर्ण 1.780 हेक्टेयर असिंचित भूमि शामिल है। सीमित संसाधनों के कारण समय पर कृषि आदान की व्यवस्था करना उनके लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन इस वर्ष आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुर शाखा मनेन्द्रगढ़ ने उनकी इस चिंता को दूर कर दिया। समिति से उन्हें खरीफ फसल के लिए आवश्यक कृषि सामग्री ऋण के

माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के समय पर अपनी खेती की तैयारी कर सके।

समिति द्वारा उन्हें 50 किलोग्राम की एक बोरी आई.पी.एल. पोटाश (एमओपी), 500 मिलीलीटर की एक बोतल इफको नैनो डीएपी, 45 किलोग्राम की चार बोरी एन.एफ.एल. नीम लेपित यूरिया तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम का लोहारी कोरिया धान (एमटीयू-1156) की 30-30 किलोग्राम की दो बोरियां उपलब्ध कराई गईं।

डुमरिया-भैयाथान रपटा पुल की अप्रोच रोड पर मरम्मत शुरू!

पुल बना था 15 लाख का सफेद हाथी

गिट्टी डालकर आवागमन बहाल करने की कवायद तेज

सूरजपुर। भैयाथान आज की जनधारा अखबार में जनहित की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद आखिरकार कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन जाग ही गया। भैयाथान विकासखंड के डुमरिया-केवरा मार्ग स्थित गोबरी नाला रपटा पुल की अप्रोच रोड की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही को बेनकाब करती खबर के छपते ही लोक निर्माण विभाग और संबंधित अमले में हड़कंप मच गया। शनिवार को आनन-फानन में जेसीबी मशीन, डंपर और निर्माण सामग्री के साथ पूरा अमला मौके पर पहुंचा और युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। सड़क पर गिट्टी डालने और समतलीकरण का कार्य प्रारंभ कर बंद पड़े आवागमन को सुचारू करने की कवायद तेज कर दी गई है।

लाखों का पुल फिर भी जनता बेहाल: गौरतलब है कि आज की जनधारा ने अपने अंक में लाखों रुपए का रपटा पुल बना सफेद हाथी, अप्रोच रोड के अभाव में बेकार, शीर्षक से इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। समाचार में विस्तार से बताया गया

था कि कैसे 15 लाख रुपये की लागत से पुल तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन दोनों ओर की अप्रोच रोड को अधूरा छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पहली ही बारिश में सड़क जानलेवा दलदल में तब्दील हो गई और दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया।

युवाओं में था आक्रोश, चंदे के पैसे से मरम्मत की थी तैयारी: इस प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। हालात यह थे कि परेशान युवाओं ने चंदे के पैसे जुटाकर खुद सड़क मरम्मत करने का फैसला ले लिया था। युवाओं के इस बढ़ते जोश और जनआक्रोश को भांपते हुए आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और आनन-फानन में सरकारी मशीनें मौके पर उतारनी पड़ीं।

ग्रामीणों की दो टूक अब खानापूर्ति नहीं, स्थायी समाधान चाहिए: प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का ग्रामीणों ने स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही दो टूक चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल अस्थायी रूप से गिट्टी डालकर खानापूर्ति करना पर्याप्त नहीं होगा। अप्रोच रोड का स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। हर साल बारिश में जनता को इस नारकीय स्थिति से मुक्ति मिलनी चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, युवाओं और ग्रामीणों ने एक सुर में माना कि यदि आज की जनधारा अखबार इस जनहित के मुद्दे को इतनी बेबाकी से नहीं उठाता, तो प्रशासन अपनी नींद से कभी नहीं जागता।

दर्जनों गांवों को मिलेगी बड़ी राहत: यह मार्ग डुमरिया, केवरा, गंगोटी सहित करीब एक दर्जन ग्रामीण इलाकों के लिए लाइफलाइन मुख्य संपर्क मार्ग है। सड़क के दलदल बनने से स्कूल जाने वाले नौनिहाल, किसान, प्रसव के लिए जाने वाली महिलाएं और मरीज भगवान भरोसे थे। शनिवार शाम जैसे ही मौके पर काम शुरू हुआ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। देखते ही देखते आज की जनधारा की असरदार पत्रकारिता और जनता के संघर्ष की गूंज पूरे इंटरनेट पर छा गई। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि अब जल्द ही उन्हें इस अधूरी सड़क के दलदल से स्थायी रूप से आजादी मिल जाएगी।

कुदरगढ़ चौकी प्रभारी ने किया पौधरोपण

दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

सूरजपुर। पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देना भी है। इसी सामाजिक सरोकार को निभाते हुए सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुदरगढ़ के चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस चौकी परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने न केवल खुद पौधा लगाया, बल्कि उसकी सुरक्षा और देखभाल का संकल्प भी लिया।

पर्यावरण गति देते हुए सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ चौकी प्रभारी द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। कुदरगढ़ पुलिस चौकी परिसर में चौकी प्रभारी और साथी पुलिसकर्मियों द्वारा पौधरोपण कर आम जनमानस को हरियाली और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया।

थाना परिसर को हरा-भरा बनाने की पहल: आमतौर पर पुलिस थानों को गंभीर माहौल के

लिए जाना जाता है, लेकिन कुदरगढ़ पुलिस इस धारणा को बदल रही है। चौकी प्रभारी की इस पहल के तहत परिसर में छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर चौकी प्रभारी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बदलते मौसम चक्र को देखते हुए आज पेड़ लगाना बेहद जरूरी हो गया है। पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आम जनता से भी की अपील: पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों ने स्थानीय नागरिकों और दर्शनार्थियों से भी इस मानसून सीजन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। कुदरगढ़ पुलिस की इस हरित पहल की स्थानीय ग्रामीणों और प्रबुद्ध जनों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। केवल पौधा लगाने तक सीमित न रहकर, पौधों के चारों ओर सुरक्षा घेरा भी लगाया जाएगा ताकि वे सुरक्षित बड़े हो सकें। खाकी वर्दी धारकों द्वारा पर्यावरण के प्रति दिखाई गई यह संवेदनशीलता समाज के अन्य वर्गों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है।

तेज बारिश में सुरक्षित आशियाने का आनंद ले रहे हैं सुंदरलाल

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले में भी अब मानसून ने अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया है। जिले में बीते तीन चार दिनो से रूक रूक कर हो रही तेज बारिश के बीच भी बैकुण्ठपुर जनपद के ग्राम जूनापारा में रहने वाले सुंदरलाल अपने परिवार के साथ रात को चैन की नींद सो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले पक्के मकान ने उनके परिवार के जीवन में सुख की एक नई परिभाषा लिख दी है। बारिश में अब यह परिवार कच्चे खपरैल घर की चिंता से मुक्त होकर खेती किसानी के लिए मेहनत करने में जुट गया है।

कच्चे घर का संकट: जूनापारा निवासी सुंदरलाल का परिवार बारिश में इतना निश्चिंत कभी नहीं रह पाता था बारिश के दिनों में उनके कच्चे मकान की समस्या आए दिन उन्हे परेशान करती थी। खेती के दिनों में दिन भर हाड़तोड मेहनत करके जब परिवार रात को आराम करने के लिए कच्चे घर में आता तो टपकती

खपरैल उनके बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद कष्टकारी हो जाती थीं। ऐसे में पूरा परिवार परेशान रहता था।

आवास ने बदली तस्वीर: आर्थिक स्थिति कमजोर होने से सुंदरलाल अपने लिए एक पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं थे ऐसे में गत वित्तीय वर्ष में उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हे पक्के मकान का लाभ स्वीकृत हुआ। शासकीय अनुदान राशि के साथ 90 दिन की मजदूरी से उन्हे बड़ा लाभ मिला और पूरे परिवार ने जुटकर अपना सपनों का आशियाना तैयार कर लिया।

आवास निर्माण प्रगति पर चर्चा के साथ बीबी जी रामजी के लाभ से अवगत होंगे ग्रामीण

आज पहला रोजगार सह आवास दिवस

बैकुंठपुर। विकसित भारत के संकल्प को लेकर ग्रामीण विकास में परिवर्तन करने हेतु लागू की गई वीबीजीरामजी योजना अब पूरे उत्साह के साथ ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। इस कड़ी में कल यानी 7 जुलाई को नवीन योजना वीबीजीरामजी के अंतर्गत पहला रोजगार सह आवास दिवस आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर कोरिया श्रीमती रोकिमा यादव ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता के बीच रोजगार सह आवास दिवस मनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

आवास कार्यों की पूर्णता पर फोकस: जिले में प्रगतिरत प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों को जल्द से

जल्द पूर्ण कराने के लिए रोजगार सह आवास दिवस पर हितग्राहियों के साथ पंचायत की टीम चर्चा करेगी। इसमें संसाधनों की आपूर्ति, जियो टैगिंग, लंबित किश्त भुगतान जैसे सभी विषय शामिल होंगे। साथ ही गांव में डीलर दीदी बनाने की दिशा में आवश्यक प्रोत्साहन एवं पहल की जाएगी ताकि हितग्राहियों को संसाधन जल्द उपलब्ध हो सकें और महिलाएं बेहतर स्वरोजगार की दिशा में सक्षम हों।

विकसित भारत जीरामजी: अकुशल श्रमिकों को एक सौ पच्चीस दिवस रोजगार की गारंटी देने वाली वीबीजीरामजी योजना के तहत श्रमिकों को कार्य की मांग, कार्य का आबंटन, ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली से लेकर मजदूरी भुगतान व अन्य लाभों के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाएगा। साथ ही मांग करने वाले परिवारों को कार्य की उपलब्धता, मनरेगा के अपूर्ण कार्यों की पूर्णता, लंबित जियो टैगिंग, ईकेवाईसी पर भी चर्चा की जाएगी। आम ग्रामीणों को क्यू आर कोड पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जनदर्शन से बदली दिव्यांग परशुराम तिवारी की जिंदगी

सूरजपुर। जिला प्रशासन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन एक प्रभावी एवं भरोसेमंद मंच है। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनदर्शन में आज कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम बगडा कोटेया निवासी दिव्यांग परशुराम तिवारी को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ है।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार परशुराम तिवारी 80 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण उन्हें चलना-फिरना बाधित था। वे बड़ी उम्मीद लेकर जनदर्शन में पहुंचे तथा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आवेदन प्राप्त होते ही कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए समाज कल्याण विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

नशे के खिलाफ पुलिस का महाअभियान

नशे को ना जिंदगी को हां का गूंजा नारा

जनधारा समाचार

सूरजपुर। सूरजपुर जिले को पूरी तरह नशामुक्त बनाने और युवाओं को बर्बादी के दलदल से बाहर निकालने के लिए जिला पुलिस सूरजपुर ने एक बेहद आक्रामक और प्रभावशाली कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन द्वारा नवजीवन नशे के विरुद्ध जन जागरूकता महाअभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस अभियान का सीधा और स्पष्ट संदेश है–नशे को ना कहें, जिंदगी को हां कहें।

सूरजपुर को नशामुक्त बनाने की सामूहिक शपथ

पुलिस प्रशासन ने जिले के नागरिकों से इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पुलिस ने जनता को आह्वान करते हुए कहा है, आइए सूरजपुर को नशामुक्त बनाने की लें हम शपथ। इस मुहिम का उद्देश्य केवल नशे के कारोबारियों पर नकेल कसना नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों की सोच को बदलना भी है।

इन चार दुश्मनों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी

पुलिस ने समाज को खोखला कर रही चार मुख्य बुराइयों को चिह्नित करते हुए जनता को सजग रहने के लिए कहा है,, शराब से दूर रहें। नशीली दवाएं ड्रग्स और अवैध सीरप कैप्सूल के जाल से बचें, गांजा के सेवन और तस्करी पर पूर्ण रोक, धूम्रपान को कहें अलविदा।

स्वस्थ शरीर से समृद्ध भारत तक का पांच सूत्रीय विजन

सूरजपुर पुलिस का यह नवजीवन अभियान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक बेहतर कल के निर्माण का रोडमैप है। इस अभियान के जरिए समाज में 5 बड़े बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन जब युवा नशे से दूर रहेगा, तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। सुखी परिवार, नशा न केवल इंसान को बल्कि पूरे हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ देता है। नशामुक्त परिवार ही सुखी परिवार है।

सशक्त समाज और समृद्ध भारत

सशक्त युवाओं से ही एक मजबूत समाज और अंततः समृद्ध भारत की नींव रखी जा सकती है। जिला पुलिस सूरजपुर की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हर नागरिक को पुलिस का मददगार बनना होगा। यदि आपके आसपास कोई नशे का अवैध कारोबार कर रहा है या युवाओं को भटका रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में मानसून तैयारियों की कि समीक्षा

जल निकासी, शुद्ध पेयजल एवं संचारी रोग नियंत्रण के दिए निर्देश

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा की बैठक में मानसून के दौरान संभावित आपदा से निपटने एवं जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियों तथा विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में नालों एवं जल निकासी मार्गों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित आपदा प्रभावित स्थलों पर सतत् निगरानी रखने, विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा हर समय सतर्कता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कलेक्टर ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु जल स्रोतों के नियमित क्लोरीनीकरण पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी

जल स्रोत - बोरवेल, हैंडपंप, कुएं, पानी टंकियां एवं अन्य पेयजल स्रोतों का नियमित रूप से क्लोरीनीकरण किया जाए तथा प्रत्येक स्रोत से पेयजल की सैंपलिंग एवं प्रयोगशाला में परीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जल के प्रमुख स्रोतों के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित करने, पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत एवं उनकी समुचित सफाई कराने तथा लीकेज को तत्काल सुधारकर दूषित जल की समस्या समाप्त करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने पेयजल से संबंधित किसी भी शिकायत पर तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई करने तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सतत निगरानी सुनिश्चित करने की बात कहा।

'सहकारिता बनेगी किसानों की समृद्धि का नया आधार'

सहकारिता सप्ताह के समापन पर जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी का हुआ आयोजन

कवर्धा। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह का समापन पीजी कॉलेज डोम, कवर्धा में जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी के साथ हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय ने की, जबकि पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 08 किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण, मछली कीट प्रदान किया। कार्यक्रम में निबंध, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता में 15 विजेता बालिकाओं को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सहकारिता सप्ताह का समापन किसी अभियान का अंत नहीं, बल्कि नए संकल्प और नई शुरुआत का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज हमें सहकारिता को नई दिशा देने का संकल्प लेना होगा और इसे केवल पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर बहुआयामी विकास का मजबूत माध्यम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता का वास्तविक अर्थ है, सभी लोगों का एकजुट होकर साझा उद्देश्य के लिए कार्य करना। आज सहकारिता के माध्यम से धान उपार्जन और बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, गैस एजेंसी संचालन तथा अन्य रोजगारमूलक गतिविधियों तक भी विस्तारित किया जाए। इससे किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में पहले 90 सहकारी समितियां थीं, लेकिन अब 40 नई समितियों के गठन के बाद उनकी संख्या बढ़कर 138 हो गई है। उन्होंने कहा कि आज महान शिक्षाविद् और राष्ट्रचिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। इसी ऐतिहासिक तिथि पर भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सहकारिता की भावना स्वाभाविक रूप से मौजूद है। बस्तर का

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोग मिल-जुलकर अनेक कार्य करते हैं, जो सहकारिता की सशक्त मिसाल है। उन्होंने कहा कि कबीरधाम का शक्कर कारखाना भी सहकारिता मॉडल की सफलता का उदाहरण है। गुजरात के बनासकांठा के अनुभव साझा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि वहां सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के साथ कई मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उसका लाभांश सभी सदस्यों में वितरित होता है। उन्होंने किसानों से सहकारिता को बहुआयामी जनआंदोलन बनाकर नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता का अर्थ है, साथ मिलकर कार्य करना और एक-दूसरे का सहयोग करना। उन्होंने कहा कि भारत के गांवों में प्राचीन काल से ही सहकारिता की भावना जीवंत रही है। गांवों में सुख-दुख, खेती-किसानी और सामाजिक कार्यों में लोग हमेशा मिलकर एक-दूसरे का साथ देते आए हैं, यही सहकारिता की वास्तविक पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद इस क्षेत्र को नई दिशा और गति मिली है तथा आज मंत्रालय के पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सांसद पाण्डेय ने सभी से सहकारिता की भावना को आत्मसात करते हुए सामूहिक विकास के लिए कार्य करने और विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किसानों की मेहनत और समर्पण ने बनाया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता की वास्तविक ताकत और महत्व को सबसे बेहतर किसान ही समझते हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है और यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जनभागीदारी का सशक्त आंदोलन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र को अलग पहचान मिलने से उसके विकास के नए अवसर खुलते हैं। सहकारिता के माध्यम से आज पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अनेक आजीविका आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि सहकारिता आंदोलन आने वाले समय में और व्यापक स्वरूप ग्रहण करेगा तथा छत्तीसगढ़ के समृद्ध और प्रगतिशील किसान पूरे देश में अपनी पहचान को और मजबूत करेंगे। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बिसेषर पटेल, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, पुलिस प्राधिकरण सदस्य भगत पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, श्रीमती दीपा पप्पु धुर्वे, डॉ. बीरेन्द्र साहू, रोशन दुबे, पूर्व जिला पंचाय अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे, संतोष पटेल, लोकचंद साहू, विजय पाटिल, कलेक्टर गोपाल वर्मा सहित जनप्रतिनिधि, किसान उपस्थित थे।

कुरूद में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

कुरुद। आज कुरूद नगर के डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाजार चौक में एक देश, एक प्रधान, एक निशान के प्रणेता डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदमकद प्रतिमा में नगरपालिका कुरूद एवं भाजपा कुरूद द्वारा पूजा-अर्चना कर जयंती अवसर पर माल्यार्पण कर भाजपा परिवार 6 जुलाई डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के इस पुण्य अवसर पर भाजपा के हमारे नेतागण और कार्यकर्ताओं मे कुरूद नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चन्द्राकर, श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत साहू, विधायक प्रतिनिधि भानु चन्द्राकर, पूर्व भाजपा नगर संयोजक भोजराज चन्द्राकर, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष मोहन अग्रवाल, पार्षदों मे मिथिलेश बैस, सितेश सिन्हा, आईटी सेल प्रदेश पदाधिकारी कमलेश चन्द्राकर, कमल शर्मा, प्रवीण रेड्डी, राजू चन्द्राकर सहित भाजपा के अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती में गगनभेदी जयकारों के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

बरसात में जलभराव की समस्या रोकने

अधिकारियों को महापौर रामू रोहरा ने दिए सख्त निर्देश

धमतरी। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए महापौर रामू रोहरा ने नगर पालिक निगम के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर शहर सहित सभी वार्डों में जल निकासी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नालियों की नियमित सफाई, जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान, बंद नालों को तत्काल साफ कराने तथा वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

महापौर रामू रोहरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के किसी भी वार्ड में बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। जलभराव की संभावना वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए समय रहते आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई, कचरे का नियमित उठाव तथा जल निकासी तंत्र को पूरी तरह सुचारु रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा फील्ड अमला लगातार निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर बनाए रखे। महापौर ने कहा कि बरसात के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निगम का पूरा अमला पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि नालियों में कचरा या प्लास्टिक न डालें तथा शहर को स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें, ताकि बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनी रहे और जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

रेलवे स्टेशन में पकड़ाया गांजा तस्कर

रायगढ़। जिले में जीआरपी (शासकीय रेलवे पुलिस) ने गांजा तस्करी मामले का खुलासा करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहा था। ट्रेन आने से पहले ही मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8.160 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है।

जीआरपी के अनुसार, रविवार सुबह थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करीब 24-25 साल का युवक, सांवले रंग का, जींस पैंट और लाल रंग की हाफ टी-शर्ट पहने प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसके नीले रंग के पिट्ठू बैग में गांजा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जीआरपी टीम

ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और बताए गए हुलिये के युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम बिनोद बाघ (27) निवासी बनबहाल, ओडिशा बताया।

आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर उसमें अलग-अलग पैकेटों में कुल 8.160 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को जीआरपी थाने लाया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहा था।

केलो डैम के 4 गेट खुले उफान पर आई नदी

- रपटा पुल के ऊपर बहने लगा पानी, रायगढ़ में लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट

रायगढ़। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए रविवार देर रात डैम के चार गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। इसके बाद केलो नदी उफान पर आ गई और सोमवार सुबह छोटे रपटा पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। रविवार दोपहर से जिले में रुक-रुककर हल्की और तेज बारिश हो रही है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के कारण केलो डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। डैम का अधिकतम जलभराव स्तर 233.00 मीटर है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 230.30 मीटर तक पहुंच चुका है। रात में पानी की आवक बढ़ने के बाद चार गेट खोलने का निर्णय लिया गया।

नदी किनारे प्रशासन अलर्ट : डैम के गेट खुलने के बाद केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के छोटे रपटा पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। संभावित खतरे को देखते हुए नगर निगम और प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

चार जोन में बनाई गई निगरानी टीम : लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने शहर को चार जोन में बांटकर अलग-अलग टीमों का गठन किया है। हर टीम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रविवार रात से ही टीमें सक्रिय होकर विभिन्न मोहल्लों और केलो नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं।

डैम की लगातार हो रही मॉनिटरिंग : केलो परियोजना के कार्यपालन अभियंता एम.के. गुप्ता ने बताया कि ऊपरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के कारण डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से एहतियातन चार गेट खोले गए हैं।

सरगुजा संभाग को बचाने का आखिरी मौका

संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा, प्रशासन को दी चेतावनी

- किसानों और ग्रामीणों की सुध ले सरकार, वरना आर-पार की होगी लड़ाई: अशोक पैकरा

सूरजपुर/भैयाथान। सरगुजा संभाग में किसानों की उपेक्षा, प्रशासनिक ढर्रे और बुनियादी जनसमस्याओं को लेकर सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समिति के वरिष्ठ सदस्य अशोक पैकरा के नेतृत्व में प्रशासन को एक कड़ा मांग पत्र सौंपकर चेतावनी दी गई है कि यदि जनहित और किसान हित से जुड़ी इन गंभीर मांगों का तत्काल निराकरण नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। समिति ने सीधे लहजे में कहा है यह सरगुजा संभाग को बचाने का आखिरी मौका है।

भ्रष्टाचार और दलालों पर सीधा प्रहार : समिति ने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की भैयाथान और ओड़गी शाखाओं में चल रही अव्यवस्थाओं पर गहरा आक्रोश जताया है। किसानों के लिए साप्ताहिक नकद निकासी सीमा को 20,000 से बढ़ाकर तत्काल 50,000 किया जाए। बैंक परिसरों में सक्रिय अवैध बिचौलियों और दलालों पर प्रभावी रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों के काट रहे चक्कर : समिति ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। नामांतरण और सीमांकन जमीन क्रय-विक्रय के बाद लंबित नामांतरण और रिकॉर्ड संशोधन का काम तत्काल हो।

जिन मामलों में सीमांकन के आदेश हो चुके हैं, वहां बिना देरी तुरंत सीमांकन किया जाए। किसान पुस्तिका बनवाने के लिए महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे किसानों को अविलंब राहत दी जाए।

बिजली संकट और उद्योगों की मनमानी पर घेरा : ग्रामीण अंचलों में बिजली की बदहाली और सीएसआर फंड के दुरुपयोग का मामला भी गरमाया हुआ है। भैयाथान स्थित हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा सीएसआर के तहत बांटे गए सिंचाई पंपों के लिए बिजली कनेक्शन और बिजली बिल का भुगतान स्वयं कंपनी करे। साथ ही, पासल प्लांट से ग्राम रजनी तक सीसी सड़क का निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत कुसमुसी, कुरीडीह, गोविंदगढ़ सहित अन्य गांवों में लो-वोल्टेज और बिजली खंभों की समस्या का तत्काल समाधान हो।

ये प्रमुख मांगें भी रहीं सुर्खियों में : कसानों को मिले डीजल कृषि कार्य के लिए किसानों को पेट्रोल पंपों से न्यूनतम 3,000 तक का डीजल डिब्बे में उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए जाएं। नया उप-पंजीयक कार्यालय भैयाथान और ओड़गी विकासखंड के नागरिकों की सुविधा के लिए भैयाथान में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना हो। प्राकृतिक आपदा 6-4 के लंबित मुआवजा प्रकरणों का तुरंत निपटारा हो।

बहू ने 3 साथियों संग मिलकर ससुर को मार डाला

- देर-रात घर में घुसकर लाठी-मुक्कों से हमला, हाथ-पैर बांधे, फिर मुंह में कपड़ा ठूंसा

जशपुर। जिले में बहू ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग ससुर को मार डाला। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपियों ने लकड़ी के फट्टे और मुक्कों से बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इसके बाद उनके हाथ-पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले, जिन्हें पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि ससुर और बहू के बीच लंबे समय से पारिवारिक

विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने तीन परिचित युवकों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। मामला दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़ाजोर का है।

जानिए पूरा मामला : 4 जुलाई 2026 को चुगरू प्रधान (70) अपने घर में मृत मिला। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के कई निशान थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल की जांच कर कई अहम सबूत जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक जांच टीम बनाई। साइबर जांच, तकनीकी जानकारी, मुखबिरों से मिले इनपुट और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को सुराग मिले। जांच में सामने आया कि चुगरू प्रधान और उनकी बहू सुगंती बेसरा के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के कारण सुगंती बेसरा ने अपने तीन परिचित युवकों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

रात में घर पहुंचकर की वारदात : पुलिस जांच के अनुसार, 3 और 4 जुलाई की देर रात चारों आरोपी मोटरसाइकिल से बुजुर्ग चुगरू प्रधान के घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाने के बाद उन्होंने लकड़ी के फट्टे और मुक्कों से उन पर हमला कर दिया।

बालोद में पुलिस हिरासत से फरार हुई महिला

बालोद। बालोद पुलिस हिरासत से चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाई गई महिला के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में पुलिस अभिरक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बालोद शहर के नयापारा क्षेत्र में करीब दो लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने रेखा सोरी को हिरासत में लिया था।

रेखा सोरी मूल रूप से कलकसा-मालीघोरी की रहने वाली है, जबकि वर्तमान में वह नयापारा में रह रही थी। शनिवार को पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी और पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था।

गांडा समाज के अध्यक्ष ने सांसद को जन्मदिन की दी बधाई

सरायपाली। महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी के 5 जुलाई को उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके गृहनिवास बसना में काफी संख्या में आत्मीय जनों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। इस अवसर पर सरायपाली जनपद के क्षेत्र क्रमण 14 से चुनी गई जनपद सदस्य व स्वच्छता समिति सभापति श्रीमती दीनता कुम्हार द्वारा भी सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी को उनके छायाचित्र भेंटकर उन्हें बधाई दी गई। इसके साथ ही सरायपाली गांडा समाज के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार अपने पुत्रों दीपक व समीर कुमार के साथ पुष्प गुच्छ भेंटकर बधाई दी है।

सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए कलेक्टर-एसपी

अतिक्रमण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

- नियमों प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के दिए निर्देश

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात प्रबंधन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-343 पर बने गड्ढों की मरम्मत कार्य

में तेजी लाने के निर्देश देते हुए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने मालवाहक वाहनों में यात्रियों के अवैध परिवहन पर विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी करें।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूल वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

साथ ही जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं

बलरामपुर। आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात जनदर्शन का आयोजन किया गया।

जनदर्शन में मांग व शिकायत के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए जिसमें आमजनों द्वारा विभिन्न विषयों संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये गए। प्राप्त आवेदनों का कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अरूण कुमार मुथा मेरा संपत्ति पुस्तक-
Registered lease deed duly registred in Book No. A-1, Volume No. 44675 at Pages 01 to 13, Document SI. No. 2560 (K), Dated 29/07/2009 जो मेरे निवास स्थान से कहीं गुम गया है।

जिस किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त पुस्तक प्राप्त हो वो व्यक्ति या संस्था इस प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर मेरे दूरभाष क्रमांक 7999397003 पर सम्पर्क कर सकता है।

इस प्रकाशन के 7 दिवस के पश्चात उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

भवदीय-
अरूण कुमार मुथा
मो. 7999397003

भूस्खलन से रेल सेवा बाधित, कौन-कौन सी ट्रेनें हुईं रद्द

मुंबई। मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली रेल सेवाएं सोमवार तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गईं। मध्य रेलवे के अनुसार, करजत-लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में दो जगह भूस्खलन होने से रेलवे की तीनों लाइनें प्रभावित हुई हैं। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, रीशेड्यूल और कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर जांचने की अपील की है।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि पहला भूस्खलन ठाकुरवाड़ी के पास हुआ, जबकि दूसरा हादसा खंडाला और मंकी हिल के बीच मध्य लाइन पर तड़के करीब 3:05 बजे हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे मुंबई-पुणे मार्ग पर रेल परिचालन रोकना पड़ा। रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने और रेल सेवाएं बहाल करने में जुटी हैं।

भूस्खलन से कौन-कौन सी रेल लाइनें प्रभावित हुईं?

करजत और लोनावला के बीच स्थित भोर घाट सेक्शन पश्चिमी घाट का सबसे चुनौतीपूर्ण रेल मार्ग माना जाता है। इस सेक्शन में मुंबई की ओर जाने वाली अप लाइन, पुणे की ओर जाने वाली डाउन लाइन और एक मध्य लाइन है। रेलवे के अनुसार, दोनों स्थानों पर हुए भूस्खलन का असर तीनों लाइनों पर पड़ा है। इसी वजह से मुंबई और पुणे के बीच ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित हुआ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन रोक दिया है और मरम्मत कार्य जारी है।

किन ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

रेलवे ने छह जुलाई के लिए कुल 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें सीएसएमटी-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस, सिंहगढ़ एक्सप्रेस और धुले एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनों को दूसरे मार्गों से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते तक सीमित किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है।

यात्रियों को क्या सलाह दी गई?

- ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा।
- रेलवे की टीमें लगातार बहाली का काम कर रही हैं।
- भारी बारिश के कारण हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
- यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर जांचें।
- केवल रेलवे की आधिकारिक सूचना और अपडेट पर ही भरोसा करें।
- सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही मुंबई-पुणे रेल सेवाएं सामान्य होंगी।

यात्रियों के लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की?

रेलवे ने कहा है कि ट्रैक से मलबा हटाने और रेल सेवाएं जल्द सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (022-22694040), ठाणे (9321336747), लोनावला (8356854238) और दादर (9136452387) से यात्री अपनी ट्रेन की स्थिति और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे क्यों हुआ बंद?

भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई-पुणे हाईवे सोमवार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल मुंबई और पुणे के बीच यात्रा न करें। एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक सेक्शन के बीच कंक्रीट का एक पिलर सड़क पर गिर गया, जबकि खोपोली-कुसगांव मिसिंग लिंक पर टनल-2 के पास भूस्खलन होने के बाद सुबह करीब चार बजे से यातायात डायवर्ट कर दिया गया।

वहीं पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर कई जगह जलभराव के कारण यातायात रोक दिया गया है। मावल और ताम्हिणी घाट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि लोहगढ़ किले के पास पाटन गांव में भूस्खलन के कारण एक परिवार के फंसे होने की सूचना पर बचाव अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) और हाईवे ट्रैफिक पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों को केवल बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन की ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

फिर सुर्खियों में तमिलनाडु लोकभवन

विजय सरकार में वन मंत्री के गंभीर आरोप

चेन्नई। विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने रविवार को तमिलनाडु में ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलग कानून बनाने की अपनी मांग दोहराई। पार्टी ने कहा कि इस दिशा में विधायी स्तर पर प्रयास जारी हैं और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

ऑनर किलिंग पर सख्त कानून की वकालत

पत्रकारों से बातचीत में सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने कहा कि VCK का स्पष्ट और अडिग रुख है कि ऑनर किलिंग जैसी जघन्य घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे अपराधों को किसी भी स्थिति में न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी तरह का संरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'विधानसभा में अपने पहले ही भाषण के दौरान मैंने ऑनर किलिंग रोकने के लिए एक अलग और समर्पित कानून बनाने की मांग उठाई थी। VCK ने पहले भी इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए हैं।'

'जल्द बनेगा समर्पित कानून'

वन्नी अरासु ने भरोसा जताते हुए कहा, 'बहुत जल्द आप ऑनर किलिंग के खिलाफ एक समर्पित कानून बनते देखेंगे। जब ऐसा होगा, तब आप भी इस पहल की सराहना करेंगे।'

गवर्नर पर संविधान की अनदेखी का आरोप

तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने के जवाब में मंत्री ने कहा कि उनकी गतिविधियां संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गवर्नर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के समानांतर प्रशासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।

'मुख्यमंत्री और कैबिनेट का सम्मान करना चाहिए'

मंत्री ने कहा, 'गवर्नर को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का सम्मान करना चाहिए। इसके बजाय वे समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से सीधे उनके पास शिकायतें और याचिकाएं देने की अपील कर रहे हैं। यह संवैधानिक परंपराओं और नियमों के विपरीत है।'

पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, इन सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे मतगणना भी कराई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने कब दिया इस्तीफा?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिली है। इसकी शुरुआत विधानसभा से हुई और राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक पहुंची। पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो, सबसे पहल 8 जून को पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने निजी कारणों से इस्तीफा

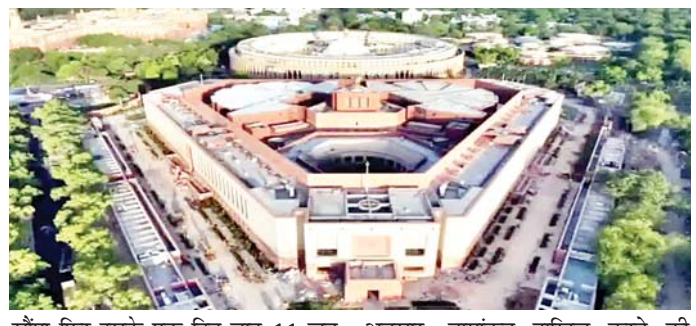

सौंपा फिर इसके एक दिन बाद 11 जून को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी पद का त्याग किया था। इनके कार्यकाल की बात करें, तो शुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक, सुष्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था।

गुजरात के मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा

चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह सीट भाजपा के आठ बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद 2 जून को खाली हुई थी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना और पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया सीटों पर भी उपचुनाव

चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत जारी की है। आयोग के सचिव बिनोद कुमार ने चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया। मंझलपुर उपचुनाव देश में हो रहे तीन विधानसभा उपचुनावों में शामिल है।

असम में कारोबार होगा आसान जमीन बिक्री के नियम बदलेंगे

किन अहम विधेयकों को मिली मंजूरी?

गुवाहाटी। असम कैबिनेट ने रविवार को सात अहम विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) और MSME इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने वाले विधेयक प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इन सभी विधेयकों को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस के लिए एकीकृत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और अमूल के नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा।

किस कानून में संशोधन का प्रस्ताव?

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मंजूर किए गए सात विधेयकों में असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 भी शामिल है। इस संशोधन के तहत धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास की जमीन केवल उन्हीं लोगों को बेची जा सकेगी, जिनके परिवार बरपेटा, बटाद्रवा और माजुली में पिछली तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने पर केंद्र सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। अब उन सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित विधेयक दोबारा लाया जाएगा।

कारोबार शुरू करना कैसे होगा आसान?

कैबिनेट ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के कारोबार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे उद्यमियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसे मिलेगी बड़ी राहत?

मंत्रिपरिषद ने असम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ (स्थापना एवं संचालन में सुविधा) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण न फैलाने वाले क्षेत्रों में स्थापित होने वाली स्वस्थ्य इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक सरकारी मंजूरी के बिना ही संचालन शुरू करने की अनुमति होगी।

पर्यटन क्षेत्र में कैसे होंगे बदलाव?

कैबिनेट ने असम पर्यटन (विकास एवं पंजीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026

को भी मंजूरी दी। यह विधेयक होमस्टे, होटल और अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि औपनिवेशिक दौर का सराय अधिनियम समाप्त कर दिया जाएगा और उसके आवश्यक प्रावधान नए कानून में शामिल कर दिए जाएंगे।

जन विश्वास और सैटेलाइट सिटी पर फैसला

बैठक में असम जन विश्वास विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा भूमि पुनर्वर्गीकरण से जुड़े कुछ प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उन अटकलों पर विराम लगेगा, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सैटेलाइट सिटी परियोजना निजी कंपनियों को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा, 'कई लोग कह रहे थे कि सरकार सैटेलाइट सिटी के विकास के नाम पर अडानी और अंबानी को जमीन देने जा रही है। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस परियोजना का विकास सरकार स्वयं करेगी।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट समूह राज्य में निवेश करते हैं तो इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

डायल-112 के जरिए मिलेगा एकीकृत इमरजेंसी सिस्टम

कैबिनेट ने एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को एक ही तकनीक आधारित 24म7 प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। नागरिक केवल 112 डायल करके इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेरगांव स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में नया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, असम पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम (डायल-112) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सी-डैक (C-DAC) की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है और अब असम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

2026 का 'लोकजतन सम्मान' वरिष्ठ संपादक राजेन्द्र शर्मा को

24 जुलाई को भोपाल में होगा आयोजन

भोपाल। इस वर्ष के 'लोकजतन सम्मान' से वरिष्ठ सम्पादक राजेन्द्र शर्मा (नई दिल्ली) को अभिनंदित किया जाएगा। राजेंद्र शर्मा लगभग आधी सदी से पत्रकारिता में हैं। 1979 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उन्होंने अपने आपको परिवर्तनकामी प्रतिबद्ध पत्रकारिता के प्रति समर्पित कर दिया था। जिस 'लोकलहर' से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उसके संस्थापक संपादक हरकिशन सिंह सुरजीत, उनके बाद सीताराम येचुरी के पश्चात अब वे लोकलहर के सम्पादक हैं। इसके अलावा वे सहमत, मुक्तनाद तथा अन्य संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों के संपादक भी रहे हैं। उनके अपने संपादन में 30 से अधिक किताबों का प्रकाशन हुआ है। उनके

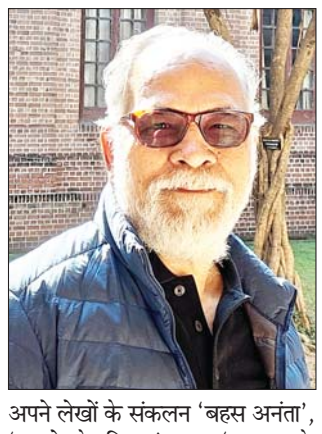

अपने लेखों के संकलन 'बहस अनंता', 'भूलने के विरुद्ध' तथा 'असत्य के प्रयोग' भी प्रकाशित हो चुके हैं, 'संस्कृति क्षेत्रे रणक्षेत्रे' प्रकाशनाधीन है। वे देशबंधु, राष्ट्रीय सहारा, जनवाणी, न्यूज़क्लिक जैसे कई समाचार माध्यमों के नियमित स्तंभकार हैं। पिछले कुछ समय से वे 'लोकजतन' में भी नियमित स्तंभ लिख रहे हैं। वे ऐसे पत्रकार-संपादक हैं, जो जटिल राजनीतिक विषयों पर सरल, सहज और चुस्त लेखन के अलावा राजनैतिक रिपोर्टिंग में व्यंग विधा का निबाह भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं।

यह सम्मान लोकजतन के संस्थापक-संपादक शैलेन्द्र शैली (24 जुलाई 1957- 07 अगस्त 2001) के जन्मदिन 24 जुलाई को दिया जाता है। इस सम्मान से ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के आज के दुःसमय में भी सच बोलने और लिखने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस सम्मान से अभी तक डॉ. राम विद्रोही (ग्वालियर), कमल शुक्ला (बस्तर-रायपुर), लज्जा शंकर हरदेनिया (भोपाल), अनुराग द्वारी (भोपाल), राकेश अचल (ग्वालियर), पलाश सुरजन (भोपाल), शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर (बस्तर) आदि प्रमुख पत्रकारों को अभिनंदित किया जा चुका है।

52 पुरुष व 10 महिलाएं, रिजॉर्ट में पार्टी और अश्लीलता

हर युवती को दिए 10 हजार; नैनीताल देह व्यापार का खुलासा

नैनीताल। नैनीताल के रामनगर के सांवल्दे स्थित एक्रोन रिजॉर्ट में शनिवार देर रात पुलिस ने देह व्यापार, शराब पार्टी और अश्लील गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 52 पुरुष और एक नाबालिग समेत 10 महिलाओं को पकड़ा है। इस दौरान रिजॉर्ट का महाप्रबंधक भाग गया। पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। 52 लोगों के साथ ही रिजॉर्ट के जीएम के खिलाफ पॉक्सो, देह व्यापार समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

मुख्य आरोपी मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र के मुल्ताननगर निवासी उमेंद्र है। उसके साथ करीम नगर निवासी मेहराजुद्दीन भी पार्टी में शामिल था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमेंद्र का मेरठ, बुलंदशहर सहित अन्य जगहों में कीटनाशक और कृषि उपकरणों से जुड़ा कारोबार है।

पुलिस के मुताबिक उसने कई प्रदेशों और विदेशों से युवतियों को पार्टी के लिए रिसॉर्ट में बुलाया था। मेरठ से उसने आनलाइन बुकिंग कराई थी। पूछताछ में उमेंद्र ने बताया कि उसकी बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी कंपनी है जो कृषि से संबंधित उपकरण बनाती है। वह कंपनी से जुड़े लोगों को नैनीताल में मनोरंजन के उद्देश्य से लेकर गया था।

उसने दस दिन पहले रामनगर आकर एकरॉन रिसार्ट में दो लाख 20 हजार रुपये भी जमा कराए थे। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उमेंद्र नैनीताल में गलत गतिविधियों में पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस से नैनीताल पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया।

प्रथम पेज का शेष

चंपतराय और अनिल का इस्तीफा..

महंत नृत्य गोपालदास इस बैठक में आने के लिए मुश्किल से माने। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी को उनको मनाने के लिए आगे आना पड़ा, तब जाकर बात बनी। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद न तो चंपत राय उन्हें देखने गए और न ही अनिल मिश्रा व गोपाल राव। कोई उन्हें ट्रस्ट की मीटिंग के लिए बुलाने भी नहीं गया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अस्वस्थ होने के बाद भी बैठक में पहुंचे और चढ़ावा चोरी प्रकरण से काफी आहत दिखे। बैठक में ट्रस्ट के कई सदस्य ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से बेहद नाराज दिखे। स्वामी परमानंद गिरी महराज तो आपे से बाहर थे। बेहद खफा। ट्रस्ट ने दान चोरी पर खेद जताया और वित्तीय व्यवस्था में बड़ी चूक को माना। बाकी संतो ने भी असंतोष जताया। सदस्य और संतों ने चढ़ावा चोरी और रामधन के गबन विवाद को लेकर भारी नाराजगी जताई। राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक को अब बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद आज बैठक में इस्तीफे पर फैसला हुआ। बैठक में वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि चढ़ावा चोरी हिंदुओं की से भावनाएं आहत हुई हैं। ट्रस्टी जगदुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ महाराज, युगपुरुष स्वामी परमानंद, कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरि व जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी बैठक में शामिल थे।

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य...

सबसे बड़ा हार्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

तीन बड़ी परियोजनाओं पर होगा कामः स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहली परियोजना के तहत 200 सीटर आधुनिक छात्र-छात्रावास बनाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए भी आवासीय सुविधा होगी। दूसरी परियोजना में कैंसर भवन का दूसरे से छठे तल तक विस्तार किया जाएगा। इसमें आधुनिक लैब, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और सिंगल रूम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तीसरी परियोजना के तहत छात्राओं के छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कमरे, डॉरमेट्री, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन हॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूतीः सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से चिकित्सा शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा, वहीं मरीजों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले...

धर्मवीर गांधी ने पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व ष्टरूचरणजीत चन्नी को बिना नाम लिए नसीहत दी है। डॉ. गांधी ने कहा- लोकतंत्र, संवधान, पंजाब व देश के हित में पंजाब के कांग्रेसी वर्कर्स लीडरों से त्याग व कुर्बानी की आस करते हैं।

इस मामले में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मोरिंडा मीटिंग को लेकर मीडिया ऐसे बात कर रही है जैसे पीओके (पाक के कब्जे वाला कश्मीर) की मीटिंग हो। मोरिंडा मीटिंग के बारे में भी आपको बता चुका हूं। हमारे वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर थी। जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। बहुत से लोग उनका स्वागत करने गए। बहुत से लोग उनसे मिलने गए। जो नहीं मिलने गए, हो सकता है आने वाले दिनों में भी वह मिलने जाएं। मोरिंडा की मीटिंग पीओके की मीटिंग नहीं थी। ऐसा मत करिए मेरी गुजारिश है। वह भी मीटिंग कांग्रेस की मजबूती के लिए थी।

एनआईए ने हाफिज सईद को...

पाकिस्तान से आतंकी साजिश चलाने का आरोप लगाया गया है।

पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूरः 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और दो दशक बाद हालात चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद, भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। इससे घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू किया गया।

एनआईए ने कहा कि यह पूरक चार्जशीट पहले दाखिल की गई 1,597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और जांच के दौरान जुटाए गए वैज्ञानिक एवं अन्य सबूतों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है। एनआईए ने 15 दिसंबर 2025 को दाखिल अपनी पहली चार्जशीट में पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट, जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीन आतंकियों और गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को नामजद किया था। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा/टीआरएफ को भी एक कानूनी इकाई के रूप में आरोपी बनाया था।

इंदिरा आवास योजना घोटालाः...

के गरीब परिवारों के लिए जारी की गई सरकारी राशि को साल 2017 में फर्जी तरीके से अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। आरोपी गौरव शुक्ला पर आरोप है कि उसने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के भोले-भाले हितग्राहियों के खातों से करीब 79 लाख रुपए का गबन किया। जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने आरोपी गौरव शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट कोरबा में करीब 3000 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

मेक इन इंडिया सिर्फ नारा...

अपने हाथों से रोजगार भी पैदा करता है और देश की रफ्तार भी तय करता है। छोटे उद्योग बंद होने से सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि लोगों का हुनर और रोजगार भी खत्म होता है। हम कारीगरों का हक नहीं छिनने देंगे। फेरारी और रोल्स-रॉयस जैसी कंपनियों के स्तर का हुनर रखने वाले इन कारीगरों को मदद मिलने के बजाय नियमों के बोझ से काम बंद करना पड़ रहा है।

देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में...

गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।

कार्यकाल के आधार पर नजमा को मिली नियुक्तिः नजमा हेपतुल्ला का नाम पहले के कार्यकाल के आधार पर शामिल किया गया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 4 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह गठन किया है। केंद्रीय वक्फ परिषद में भी दो गैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसी बदलाव के तहत मध्यप्रदेश में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने 4 जुलाई 2026 को जारी राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना में वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) के तहत बोर्ड के गठन की घोषणा की।

अबूझमाड़ में आज भी मानसूनी...

की गई तो पूरी सच्चाई सामने आई।

पता चला कि ये विडियो बीजापुर जिले के चोखनपाल से गंगालूर से आई है। जहां कई नदी और नाले हैं, जो बारिश के दौरान ऊफान पर हैं। चौंकाने वाली बात है कि स्थानीय ग्रामीण वर्षों से इन नदी नाले पर पुल-पुलिया की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।

इन गांवों के ग्रामीणों की जुबानीः बीजापुर के चोखनपाल, कमकानार, चिंनजोजेर हवाक, डुवालीपारा, मर्रिवाड़ा, मेटपाल गोंगला क्षेत्र से गंगालूर मार्ग पर पुल-पुलिया नहीं होने से स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में फजीहतों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर लोग अपनी मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों को कंधे पर उठाकर नदी-नालों को पार करने के लिए मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

ग्रामीणों ने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि चोखनपाल से गंगालूर मार्ग पर आवश्यक पुल-पुलियों का शीघ्र निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। यदि लंबे समय तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन-प्रशासन की होगी।

तिरछी नज़र से

जब B.Tech की डिग्री भी 'ग्रेजुएट' कहलाने के लिए कम पड़ जाए!

प्रभातदत्त झा

मैं आपकी तरह ही एक आम मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य हूँ. मेरा नाम अनुज है। मैं B.Tech करके 2025 में पास हुआ। मुझे नौकरी की कोशिश में 11 महीने हो गए। 500 से ज़्यादा रिज्यूमे भेजे। 20 इंटरव्यू दिए। 3 ऑफर मिले, पर सैलरी इतनी कि उसमें पेट्रोल और कैंटीन का खर्च नहीं निकलता।

मेरे पिता ने मेरी डिग्री के लिए 20 लाख रुपए लोन लिया था। अब उस लोन की EMI 18 हजार है। और मुझे मिल रही है-12 हजार की नौकरी। मतलब मैं हर महीने अपनी नौकरी से 6 हजार अपने लोन में लगा रहा हूँ - और यह गणित सुनकर देश का कोई भी अर्थशास्त्री रोएगा, क्योंकि इससे तो कम सिद्धांतों में उलझना है।

नौकरी के लिए क्या चाहिए? उनका कहना है - कोई 'स्किल' चाहिए। 4 साल कॉलेज में हमने क्या पढ़ा? थ्योरी, न्यूटन के नियम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वह कोडिंग जो 2015 में भी पुरानी थी। जब मैंने इंटरव्यू में बताया- 'मुझे यह आता है,' तो उन्होंने कहा- 'यह आउटडेटेड है, हमें AI और ML चाहिए।' मैंने कहा - 'वह क्या है?' उन्होंने मुस्कुराकर बताया 'जिसने आपकी डिग्री बेकार कर दी।'

दोस्त सुमित ने MBA किया। उसके 25 लाख लगे। अब वह 'बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव' है - जिसका काम कॉल सेंटर में लोगों को ठगना है। उसे हर दिन 100 कॉल करनी हैं। सैलरी 20 हजार। EMI 22 हजार। वह घर से पैसे माँगता है-और उसे 'नौकरीपेशा' कहते हैं। असल में वह अपनी डिग्री की लागत वसूलने में 12 साल लगाएगा - तब तक उसकी शादी होगी, बच्चा होगा, और वह अपने बच्चे को एडमिशन के चक्कर में फिर कोचिंग में डाल देगा।

यही तो हमारी युवा पीढ़ी की कहानी है - हम जितना पढ़ते हैं, उतना पीछे होते जाते हैं। हमारे पिता 10वीं पास थे, पर उनके पास घर था। हम 12वीं में 90% लाते हैं, पर किराए के मकान में रहते हैं। सरकार कहती है - 'शिक्षित बनो।' हम बने, तो सरकार ने हमसे पूछा 'अब जॉब तुम खुद ढूँढो, हम तो बस कॉलेज बनाते हैं।'

और सबसे बड़ी विडंबना - कॉलेज में हमें जो सिखाया जाता है, वह इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाता है, वह कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। और जो हम खुद सीखते हैं, उसके लिए हमें पैसे देने होते हैं - ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट फीस। यानी एक बार डिग्री के लिए दिए, दूसरी बार स्किल के लिए दिए, तीसरी बार नौकरी पाने के लिए दिए। और नौकरी मिली भी तो उसमें से तीनों EMI निकालनी हैं।

आज मैं 25 का हूँ। मेरे पास 22 साल की 'फॉर्मल एजुकेशन' है, 4 लाख के ऑनलाइन कोर्स हैं, 3 इंटर्नशिप हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं, पर जेब में 50 रुपए हैं। और माँ कहती है 'बेटा, तोहरी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ?' मैं कहता हूँ - 'फायदा यह हुआ कि मुझे एहसास हो गया कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है।'

कल एक शादी में गया। लोगों ने पूछा - 'क्या करते हो?' मैंने कहा- 'नौकरी की तलाश में हूँ।' उन्होंने सहानुभूति दी - मानो किसी रोगी को सांत्वना दे रहे हों। मैंने सोचा-मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, जो इस देश में बीमारी से भी बदतर है - क्योंकि बीमारी का इलाज है, पर बेरोज़गारी का नहीं।

सच कहूँ तो हमारी डिग्री ने हमें कुछ नहीं दिया, सिवाय एक 'प्रमाणपत्र' के कि हम 4 साल तक कॉलेज में बैठकर बोर हुए। और अब जब हम असली दुनिया में आते हैं, तो पता चलता है - यहाँ डिग्री नहीं, कनेक्शन चलते हैं। जिसके बाबूजी जानते हैं, वह कलेक्टर है; जिसके नहीं, वह संग्रहकर्ता है - सवाल पूछता है कि 'क्या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है?'

मुझे तो अब लगता है - 'न्यू इंडिया' में 'न्यू जॉब' का मतलब 'नई बेरोज़गारी' है। और हम इस बेरोज़गारी को 'स्टार्टअप' या 'फ्रीलांसिंग' का नाम देकर खुद को 'सेल्फ-एम्प्लॉयड' कहते हैं- क्योंकि 'बेरोज़गार' सुनने में बहुत बुरा लगता है। पर दोनों की जेब एक जैसी खाली है- बस एक नाम में फ़र्क है।

डिजिटल करेंसी और कैशलेस इकॉनमी

क्या हम बिना नोटों के संसार के लिए तैयार हैं?

शशांक झा

आज से ठीक एक दशक पहले अगर कोई आपसे कहता कि आपको अपनी जेब में एक भी रुपया (नोट या सिक्का) रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी पूरी दिनचर्या–सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक-महज एक स्क्रीन स्वाइप या QR कोड स्कैन से चल जाएगी, तो शायद आप हंस देते। लेकिन आज यह भारत और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सच्चाई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक बड़े तकनीकी संक्रमण (Transition) से गुजर रही है। लिक्विड कैश (नकद) की जगह अब बाइट्स और कोड्स ने ले ली है। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ हमारी सहूलियत तक सीमित है, या यह वैश्विक आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से री-प्रोग्राम कर रहा है? आइए, इस वित्तीय क्रांति की परतों को टटोलते हैं।

बदलाव की रफ्तार: आंकड़ों की जुबानी

कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ते कदमों को समझने के लिए किसी जटिल आर्थिक थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस आंकड़ों पर एक नजर डालना ही काफी है।

- **UPI का दबदबा:** अकेले भारत में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (PI) हर महीने अरबों रुपये के लेन-देन को संभाल रहा है। हालिया वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, डिजिटल ट्रांजैक्शन की सालाना वृद्धि दर 40% से अधिक बनी हुई है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** स्वीडन जैसी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही 'लगभग 100त्न कैशलेस' होने के करीब पहुंच चुकी हैं, जहां कुल जीडीपी का 1त्न से भी कम हिस्सा भौतिक नकदी में रह गया है।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** दुनिया के 90त्न से अधिक केंद्रीय बैंक (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का 'ई-रुपया' भी शामिल है) अपनी डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या इसे लॉन्च कर चुके हैं।

विशेषज्ञों की राय: वरदान या अदृश्य जाल?

इस डिजिटल लहर पर दुनिया भर के अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। इसके फायदे जितने चमकीले हैं, इसके पीछे छिपे जोखिम भी उतने ही गंभीर हैं।

'डिजिटल करेंसी न केवल लेन-देन की लागत को कम करती है, बल्कि यह समानांतर अर्थव्यवस्था (ब्लैक मनी) पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब हर पैसे का डिजिटल फुटप्रिंट होगा, तो टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी बेहद मुश्किल हो जाएगी।' - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नीति विश्लेषक

इसके विपरीत, कुछ विशेषज्ञ एक अलग चिंता जताते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पूरी तरह से कैशलेस होने से समाज का वह वर्ग हाशिए पर जा सकता है जो तकनीकी रूप से साक्षर नहीं है।

'कैशलेस इकॉनमी एक दोधारी तलवार है। जहां यह पारदर्शिता लाती है, वहीं यह नागरिकों की वित्तीय गोपनीयता (Privacy) को भी खत्म करती है। अगर पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया, तो सरकार या बैंक एक क्लिक से किसी भी व्यक्ति का वित्तीय एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं।'

चुनौतियाँ: जो इस रास्ते को पथरीला बनाती हैं

चमकते हुए डिजिटल डैशबोर्ड के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है:

- **साइबर सुरक्षा (Cyber Security):** आए दिन होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डेटा लीक इस व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी हैं। एक आम आदमी का डिजिटल वॉलेट सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
- **डिजिटल डिवाइड (Digital Divide):** शहरों में तो हर रेहड़ी-पटरी वाला QR कोड लिए खड़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली और इंटरनेट की अनिश्चितता डिजिटल इकोनॉमी के रास्ते का रोड़ा है।
- **मनोवैज्ञानिक खर्च (Psychological Spending):** मनोवैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के संयुक्त अध्ययन बताते हैं कि जब हम हाथ से भौतिक नोट गिनकर खर्च करते हैं, तो हमें 'खर्च का अहसास' (Pain of Paying) होता है। इसके विपरीत, सिर्फ स्क्रीन पर नंबर स्वाइप करने से लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च (Overspending) करने लगे हैं, जो व्यक्तिगत कर्ज को बढ़ावा दे रहा है।

भविष्य का मार्ग: संतुलन ही समाधान है

तो, क्या नकद पूरी तरह गायब हो जाएगा? इसका जवाब है–शायद नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। एक आदर्श अर्थव्यवस्था वह नहीं है जो जबरन पारंपरिक तरीकों को बंद कर दे, बल्कि वह है जो एक 'लेस-कैश' (Less-Cash) सोसाइटी का निर्माण करे, न कि पूरी तरह 'कैश-लेस' की जिद पकड़े। डिजिटल करेंसी को बैकअप के तौर पर भौतिक नकदी का सहारा मिलना जरूरी है ताकि किसी भी तकनीकी ब्लैकआउट या वित्तीय संकट के समय अर्थव्यवस्था ठप न हो।

निष्कर्ष : डिजिटल करेंसी और कैशलेस ट्रांजैक्शन महज एक ट्रेंड या वायरल टॉपिक नहीं हैं; यह मानव सभ्यता के विकास का अगला तार्किक कदम है। वस्तु विनिमय (Barter System) से सोने के सिक्कों, सिक्कों से कागज के नोटों, और नोटों से प्लास्टिक कार्ड्स तक का सफर अब स्मार्टफोन के स्क्रीन में सिमट गया है। विजेता वही देश और समाज होगा, जो मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों और वित्तीय साक्षरता के साथ इस बदलाव को गले लगाएगा। आपकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन आपका डिजिटल वॉलेट सुरक्षित और समझदारी से भरा होना चाहिए।

सहायक ब्रांच मैनेजर, इंडियन बैंक
(आर्थिक और बैंकिंग मामलों के एक्सपर्ट)
श्यामनगर,सतना मध्यप्रदेश

इस क्रांति के तीन मुख्य स्तंभ

इस वायरल और स्थायी आर्थिक बदलाव को तीन मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है:

स्तंभ	–	फिनटेक ऐप्स (UPI/Wallets)
मुख्य विशेषता	–	त्वरित और सुलभ
आर्थिक प्रभाव	–	खुदरा व्यापार में तेजी और नकदी प्रबंधन के खर्च में कमी।
स्तंभ	–	CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी)
मुख्य विशेषता	–	सरकारी संप्रभुता और सुरक्षा
आर्थिक प्रभाव	–	बैंकों पर निर्भरता कम करना और क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) पेमेंट को सस्ता बनाना।
स्तंभ	–	क्रिप्टोकरेंसी (Decentralized)
मुख्य विशेषता	–	बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के
आर्थिक प्रभाव	–	उच्च जोखिम और अस्थिरता, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक का नवाचार।

बरसात का मौसम है, पर बरतें पूरी सावधानी: जरा सी लापरवाही बन सकती है भारी नुकसान की वजह

नूपुर शर्मा

खिड़कों के बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की पहली बूंदें जितना सुकून देती हैं, उतना ही खतरा भी अपने साथ लेकर आती हैं। हर साल मानसून के दौरान लाखों घरों और दुकानों को सीलन, जलभराव और शॉर्ट-सर्किट जैसी घटनाओं से नुकसान होता है – और हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश नुकसान सिर्फ थोड़ी सी सतर्कता बरतकर पूरी तरह टाले जा सकते थे। सवाल यह नहीं कि बारिश आएगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उसके लिए कितने तैयार हैं।

छत और नालियां: सबसे पहली जांच

मानसून से पहले छत, दीवारों और पानी निकासी व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण जरूरी है। छत पर जमी काई, टूटी टाइलें या बारीक दरारें शुरुआत में मामूली लगती हैं, पर लगातार पानी के संपर्क में रहने से यही दरारें कंक्रीट के भीतर सरिया तक पानी पहुंचा देती हैं, जिससे संरचना कमजोर होती है। नालियों में फंसी पत्तियां और कचरा पानी की निकासी रोक देते हैं, और यहां रुका हुआ पानी सीलन व फफूंद को जड़ बनता है।

बिजली से जुड़ी सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी :

बारिश के मौसम में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा और सबसे घातक होती हैं। ढीले तार, खुले स्विच-बोर्ड और पुरानी वायरिंग नमी के संपर्क में आते ही खतरा बन जाते हैं। मानसून शुरू होने से पहले किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से पूरे परिसर की वायरिंग जंचवा लेना बुद्धिमानी है। इनवर्टर, स्टेबलाइजर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को ऊंचाई पर और नमी से दूर रखें।

कीमती सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा*

निचले इलाकों में स्थित घरों और दुकानों के लिए यह सलाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है – जरूरी दस्तावेज, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कीमती सामान हमेशा जमीन से ऊंचाई पर रखें। वाटरप्रूफ बॉक्स या मजबूत प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल एक छोटा निवेश है, जो बड़े नुकसान से बचा सकता है। वाहनों को भी जलभराव वाले स्थानों से दूर, ऊंचाई पर पार्क करें।

पेड़ और भवन की नींव पर नजर

कमजोर या सूखी शाखाएं तेज हवा में टूटकर मकान, वाहन या बिजली की लाइनों पर गिर सकती हैं – इनकी समय पर कटाई कराएं। साथ ही भवन के चारों ओर पानी जमा न होने दें, क्योंकि लगातार नमी नींव की मजबूती को धीरे-धीरे कमजोर करती है, भले ही यह असर तुरंत नजर न आए।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अतिरिक्त सतर्कता

दुकानों और कार्यालयों में अग्निशमन यंत्र, जल निकासी व्यवस्था और बिजली सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच जरूरी है। जहां संभव हो, भवन और व्यावसायिक संपत्ति का बीमा भी करा लेना चाहिए – यह ऐसा सुरक्षा कवच है जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक झटके को काफी हद तक कम कर देता है।

मानसून प्रकृति का वह उपहार है जो धरती को हरा-भरा और जीवन को तरोताजा करता है, बशर्ते हम उसका स्वागत तैयारी के साथ करें। दरवाजे की एक कील ठोंकने, एक तार को दुरुस्त कराने, एक नाली को साफ कराने जैसे छोटे-छोटे कदम ही असल में वह मजबूत नींव रचते हैं जिस पर परिवार का सुकून और संपत्ति की सुरक्षा दोनों टिकी होती हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए – क्योंकि बारिश का आनंद तभी पूरा है जब मन में कोई फिक्र न हो।

– बिलासपुर, छत्तीसगढ़

जीएसटी : 9 साल, 2.5 लाख करोड़ पार

आम आदमी की जेब और राज्यों का खजाना, कैसे बदला?

रायपुर के किराना व्यापारी संजय अग्रवाल की दुकान पर पहले 'वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स' की अलग-अलग बहीखाते होती थीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद उनकी उलझन तो कम हुई, लेकिन ऑनलाइन रिटर्न (GSTR-1, 3B) भरने की नई चुनौती भी आई। यह कहानी सिर्फ संजय की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय कारोबारियों और उपभोक्ताओं की है। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और आंकड़े बताते हैं कि यह सफर रिकॉर्ड राजस्व संग्रह से भरा तो रहा, पर आम आदमी तक इसकी मीठास अब भी पूरी तरह नहीं पहुंची है।

आम आदमी और छोटे कारोबारी को क्या फायदा? : जीएसटी का सबसे बड़ा वादा था 'टैक्स पर टैक्स' (Cascading Effect) खत्म होना और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होना। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 सालों में 100 से अधिक वस्तुओं को 28% के टॉप स्लैब से निकालकर 18% या 5% के स्लैब में रखा गया है।

उदाहरण के तौर पर: फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर (28% से घटकर 18%) एक रू. 50,000 की एसी पर आपको करीब रू. 5,000 की सीधी बचत हो गई है। रेस्टोरेंट में खाना (पहले सर्विस टैक्स+VAT मिलाकर 20.5% लगता था, अब 5% बिना ITC वाले) - महीने में रू 10,000 खर्च करने वाले परिवार को करीब रू 1,500 की मासिक बचत।

हालांकि, छोटे कारोबारियों (MSMEs) के लिए तीन अलग-अलग रिटर्न (GSTR-1, 3B, 9) और महीने की 10वीं, 20वीं, 30वीं की समय-सीमा अब भी एक उलझन भरा जाल है। रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी रमेश साहू कहते हैं, 'जीएसटी से कर तो सरल हुआ, पर कंप्लायंस का बोझ और मैनपावर खर्च दोगुना हो गया।

छत्तीसगढ़ की स्थिति : अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय आंकड़े न देखकर छत्तीसगढ़ पर नज़र डालें, तो राज्य ने इस साल जून (2026) तक करीब रू 3,200 करोड़ का मासिक GST संग्रह किया है, जो पिछले साल जून की तुलना में 12.5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के व्यापार मंडल (CGTMA) के अनुसार, लौह-अयस्क, सीमेंट और FMCG उत्पादों ने इस संग्रह में सबसे बड़ा योगदान दिया है। राज्य अब देश के टॉप-10 GST राज्यों में अपनी जगह बनाने के करीब है।

अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत की क्या राय है? : केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद मोहन कहते हैं: 'जीएसटी भारत के कर इतिहास की सबसे बड़ी संस्थागत उपलब्धि है। रू 60,000 करोड़ (2017) से रू 2.5 लाख करोड़ (2026) तक की यात्रा अभूतपूर्व है। लेकिन अगले 9 सालों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम 3-स्लैब संरचना को कितना सरल कर पाते हैं।' वहीं, FICCI के टैक्स कमेटी के प्रमुख श्री सुधीर मेहता ने जारी बयान में कहा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (फास्टैग लिंक, ई-वे बिल) ने कारोबार को पारदर्शी बनाया है, फिर भी स्लैब की जटिलताओं को कम करने की जरूरत है।

क्या चुनौतियाँ बाकी हैं? : सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, जीएसटी के 'नौ साल' में कई विवाद भी रहे हैं: राज्यों की क्षतिपूर्ति (Compensation Cess) जून 2022 में समाप्त हो गई। इसके बाद से कई राज्यों (विशेषकर पिछड़े और औद्योगिक राज्य) को राजस्व घाटा हो रहा है। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर इसे 'केंद्र की एकतरफा कर प्रथा' करार दिया।

न्याय की राह को सुगम बनाती हाई कोर्ट समर्पित बस सेवा : एक अनिवार्य आवश्यकता

न्यायालय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और छत्तीसगढ़ और उच्च न्यायालय इसका केंद्र है। बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय शहर के बसावट से दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जैसा कि सभी जानते हैं कि यहां हजारों की संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकार पहुंचते हैं ,ऐसे में न्यायालय की सुरक्षा समयबद्धता और सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाजनक सिटी बस सेवा अब केवल सुविधा नहीं बल्कि समय की मांग बन चुकी है यह केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक निवेश है जिससे न्यायपालिका की गरिमा और कार्य क्षमता दोनों में सुधार होगा

अन्य राज्यों में सफल प्रयोग:- दिल्ली मे वर्ष 2000- 2003 में एवं केरल में 2005 में कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए विशेष सटल सेवाएं उपलब्ध हैं इन सेवाओं के कारण वाहन निजी वाहनों का रोड पर दबाव 40% तक काम हुआ है कई राज्यों में राज्य परिवहन निगम के साथ अनुबंध कर फ्यूल सेफ्टी और राजनीति दरों पर संचालन का मॉडल अपनाया है जिससे सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ता है।

बोदरी का सफर:- पिछले कुछ वर्षों से बिलासपुर से बोदरी मार्ग पर यातायात का दबाव तेजी से बड़ा है परिवहन विभाग एव पुलिस रिकॉर्ड और ट्रैफिक सर्वे के आधार पर बोदरी मार्ग के यातायात की स्थिति कुछ इस प्रकार है एक अनुमान के मुताबिक

बिलासपुर रायपुर हाईवे NH 30 पर बोदरी के पास प्रतिदिन 15000 से 20000 के बीच वाहन गुजरते हैं इसमें शामिल है

न्यायिक आवाजाही:- 3000 से 4000 वहां कर और बाइक केवल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता स्टाफ और पत्रकारों एवं सरकारी अधिकारियों के होते हैं।

भारी वाहन:- रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से प्रतिदिन 4000 से अधिक भारी वाहन ट्रक ट्रेलर गुजरते हैं जो छोटे वाहनों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

हाई कोर्ट मार्ग पर यातायात का सबसे अधिक दबाव दो समय पर होता है

1. सुबह 9:30 से 11:30 जब कोर्ट का स्टाफ और अधिवक्ता आते हैं
2. शाम 4:30 से 6:30 जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होती है

इन घंटो में यातायात की गति 40% कम हो जाती है औसतन इस मार्ग पर प्रति माह 10 से 15 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं जिसमें दो पहिया वाहन सवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

पार्किंग स्थिति:- उच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग की क्षमता लगभग 1500 से 2000 वाहनों की है लेकिन वर्तमान में यहां आने वाले वाहनों की संख्या अक्सर इस क्षमता को पार कर जाती है बस सुविधा होने पर वाहनों का जमावड़ा 60त्न तक काम हो सकता है।

प्रस्तावित बस सेवा के बहुआयामी लाभ:-

1. आर्थिक बचत और ईंधन सुरक्षा
2. सुरक्षा और स्वास्थ्य
3. पर्यावरण योगदान
4. कार्य क्षमता में सुधार।

निष्कर्ष :- आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बिलासपुर रायपुर मार्ग पर बोदरी के समीप प्रतिदिन 15000 से अधिक वाहनों का दबाव रहता है इससे एक बड़ी संख्या उन दो पहिया वाहनों की है। जिसमें उच्च न्यायालय के कर्मचारी और जूनियर अधिवक्ता जान जोखिम में डालकर हाईवे पर यात्रा करते हैं बाहरी वाहनों की बढ़ती दबाव और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए समर्पित बस सेवा न केवल सुविधा बल्कि जीवन सुरक्षा का भी विषय हैं।

डॉ. निधि गुप्ता
एडवोकेट, एम.लिब.
(न्यायिक मामलों की विशेषज्ञ । आम आदमी और मध्यम वर्ग की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से प्रभावी विश्लेषण)

गुढ़ियारी थाने में शुरू हुआ ई-मालखाना

सोना-चांदी, ड्रग्स से लेकर हर जब्त सामान पर यूनिक बारकोड, रिकॉर्ड रहेगा पूरी तरह डिजिटल

रायपुर। राजधानी के गुढ़ियारी थाने में सोमवार को जब्त सामान के रखरखाव और रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए ई-मालखाना प्रणाली की शुरुआत की गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले ने इसका शुभारंभ किया। पुलिस का दावा है कि नई व्यवस्था से जब्त सामान की निगरानी, रिकॉर्ड और ट्रैकिंग पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। यह प्रणाली डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में गुढ़ियारी थाना प्रभारी बीएल चंद्राकर और मालखाना स्टाफ के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है।

शुभारंभ के दौरान अधिकारियों को ई-मालखाना की कार्यप्रणाली का डेमो भी दिखाया गया। इसमें डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान, रैकवार स्टोरेज और रिकॉर्ड ट्रैकिंग की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल, एडिशनल डीसीपी आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

स्कैनिंग करते ही मिलेगी लोकेशन

पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने बताया कि ई-मालखाना लागू करने से पहले थाने में रखे सभी जब्त सामान का भौतिक सत्यापन कराया गया। इसके बाद मालखाने को वैज्ञानिक तरीके से रैकवार व्यवस्थित किया गया। सामान को ए1,ए2, बी1, बी2 जैसी श्रेणियों में रखा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी लोकेशन तुरंत पता चल सके। हर जब्त वस्तु पर बारकोड लगाया गया है और उसका सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इससे अब सामान जमा करने, निकालने और खोजने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।

जब्त माल पर बारकोड : यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बारकोड सीधे उस सामान पर लगाया जाएगा जो पुलिस ने जब्त किया है। इसका फायदा ये है कि सामान की तुरंत पहचान हो जाएगी। स्कैन करते ही केस नंबर, जब्ती तारीख और वर्तमान लोकेशन दिख जाएगी। एक जैसे सामान में भ्रम नहीं होगा।

ई-मालखाना शुरू करने वाला गुढ़ियारी बना शहर का दूसरा थाना

पुलिस अधिकारियों के अनुसार ई-मालखाना व्यवस्था शुरू करने वाला गुढ़ियारी थाना शहर का दूसरा थाना है। इससे पहले कोतवाली थाना में ई-मालखाना व्यवस्था शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तकनीक के इस्तेमाल और अभिलेख प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में का यह मॉडल भविष्य में अन्य थानों में भी लागू किया जा सकता है।

'चेन ऑफ कस्टडी' का पूरा रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित

ई-मालखाना सिस्टम में हर जब्त सामान का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। इसी पूरे प्रोसेस को ही चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है, जो किसी भी केस में सबूत की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

तीन जगहों पर टैग किए जा रहे बारकोड

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बारकोड तीन अलग-अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। पहला जब्त माल पर, जब्ती पत्रक और मालखाना रजिस्टर में। जब्त सामान से जुड़ी हर जानकारी आपस में डिजिटल तरीके से लिंक रहे और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति न बने।

वासेपुर के गैंगस्टर का छत्तीसगढ़ में करोड़ों का साम्राज्य

- अंबिकापुर में 13 साल से छिपा था, चला रहा था बसें-एम्बुलेंस, दोबारा फरार, पार्टनर पर एफआईआर

सरगुजा। झारखंड के वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम (60) और उसका सहयोगी जावेद अंबिकापुर में 13 साल से छिपकर रह रहे थे। बस संचालक के साथ पार्टनरशिप में बसें और 40 से ज्यादा एम्बुलेंस चला रहा था। गैंगस्टर ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

दोहरे हत्याकांड मामले में शब्बीर आलम को आजीवन कारावास की सजा मिली है। धनबाद पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है। उसकी तलाश की जा रही थी। 3 दिन पहले झारखंड पुलिस अंबिकापुर पहुंची थी। छापेमारी से पहले गैंगस्टर और उसका साथी दोबारा फरार हो गए।

सरगुजा पुलिस ने सोमवार को गैंगस्टर के सहयोगी और पार्टनर बस संचालक बैदुल खान के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बैदुल खान ने यह जानते हुए कि शब्बीर आलम भगोड़ा घोषित है, उसे अपने यहां पनाह दी। बता दें कि वासेपुर के खूनी संघर्ष पर गैंग्स आफ वासेपुर फिल्म भी बन चुकी है। दरअसल, वासेपुर के गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके भाई शाहीद आलम ने 5 लोगों के साथ मिलकर डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को 2001 को धनबाद में गोली मार दी थी।

महिलाओं के लोन की रकम में 1.11 करोड़ की गड़बड़ी

- दुर्ग में वसूले गए पैसे जमा नहीं किए, बैंकिंग कंपनी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार

भिलाई। जिले में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में महिलाओं के लोन की रकम में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। पुलिस ने 267 महिला ग्राहकों से वसूली गई 1 करोड़ 11 लाख 93 हजार 173 रुपए की राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं करने के आरोप में दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। इस पूरे मामले का खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ। स्टेट हेड की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, इस मामले में 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

कंपनी की ओर से धमधा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी बैंक की ओर से महिलाओं को लोन मुहैया कराने और उसकी किस्तों की वसूली का काम करती है। मई 2026 में धमधा शाखा के ऑडिट के दौरान पता चला कि शाखा में पदस्थ कर्मचारियों ने ग्राहकों से वसूली गई लोन की किस्त, लोन क्लोजर की राशि और अन्य भुगतान कंपनी के खाते में जमा नहीं किए।

जिंदगी बचाने को खरीदा था दूध, मौत का कारण बना?

रायपुर में मेडिकल स्टोर पर सवाल, पुलिस-स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू

रायपुर। रायपुर में एक नवजात बच्ची की मौत के बाद शिशु आहार की गुणवत्ता और मेडिकल स्टोरों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दलदल सिवनी निवासी एक परिवार ने आरोप लगाया है कि मेडिकल स्टोर से खरीदा गया एक्सपायरी मिल्क पाउडर नवजात को पिलाने के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी ड्रग इंस्पेक्टर को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

दलदल सिवनी निवासी चंद्रशेखर कन्नोजे ने मौदहापारा थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी ने 29 जून को जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। प्रसव के बाद मां के दूध की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर डॉक्टरों ने नवजातों को अतिरिक्त पोषण के लिए मिल्क पाउडर देने की सलाह दी। इसी सलाह के आधार पर 30 जून को उन्होंने मेकाहारा गेट के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से एक ब्रांडेड मिल्क पाउडर का डिब्बा खरीदा। खरीदे गए मिल्क पाउडर से तैयार दूध दोनों में से एक नवजात बच्ची को पिलाया गया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत लगातार गंभीर होती गई, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

परिवार का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मिल्क पाउडर के डिब्बे की एक्सपायरी डेट देखी और बताया कि उत्पाद की अवधि समाप्त हो चुकी है। परिजनों का दावा है कि डॉक्टरों ने आशंका जताई कि एक्सपायरी उत्पाद के सेवन से बच्ची की तबीयत प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस संबंध में डॉक्टरों या अस्पताल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही यह पुष्टि हुई है कि मौत का कारण एक्सपायरी मिल्क पाउडर ही था।

शिकायत में परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि 2 जुलाई को जब उन्हें मिल्क पाउडर के एक्सपायर्ड होने की जानकारी मिली तो वे मेडिकल स्टोर पहुंचे और इसकी शिकायत की। आरोप है कि स्टोर संचालक ने पुराना डिब्बा वापस लेकर उसकी जगह दूसरा डिब्बा देने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बच्ची की हालत लगातार बिगड़ रही थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने तत्काल उपचार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद 5 जुलाई को बच्ची की मौत हो गई।

घटना के बाद परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मौदहापारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर खरीद-बिक्री से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संबंधित मिल्क पाउडर कब और किस स्थिति में बेचा गया था तथा शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई।

इधर, स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने परिजनों को कार्यालय बुलाया है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान संबंधित मिल्क पाउडर का बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि, सप्लाई चेन तथा मेडिकल स्टोर की बिक्री संबंधी रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी।

फिलहाल मेडिकल स्टोर संचालक की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, जांच एजेंसियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेज, मिल्क पाउडर की गुणवत्ता संबंधी परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही यह तय हो सकेगा कि नवजात की मौत का वास्तविक कारण क्या था और कथित एक्सपायरी मिल्क पाउडर की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका थी या नहीं।

देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट का झटका

चुनाव याचिका पर प्रारंभिक दलील खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भिलाई नगर विधानसभा सीट से विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव याचिका के एक अहम कानूनी मोर्चे पर झटका लगा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका में देवेंद्र यादव ने दो मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दे मानकर बिना साक्ष्य दर्ज किए ही उनका फैसला करने और याचिका को समाप्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की एकलपीठ ने 30 जून 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया।

अदालत ने साफ कहा कि जिन मुद्दों का फैसला विवादित तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है, उन्हें प्रारंभिक रूप से नहीं निपटाया जा सकता। ऐसे मामलों में पूरा विचारण पूरा करके ही फैसला होना चाहिए। प्रेम प्रकाश पांडे ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में मुख्य आरोप यह है कि देवेंद्र यादव ने चुनावी शपथपत्र में सोशल मीडिया खातों, आय, संपत्ति और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में इस याचिका पर पांच मुद्दे तय किए थे। देवेंद्र यादव की ओर से दायर अंतरिम अर्जी में दलील दी गई थी कि उन्होंने शपथपत्र में सभी जरूरी जानकारियां दी थीं, इसलिए बिना गवाहियों के ही इन मुद्दों पर फैसला हो जाना चाहिए। हालांकि, प्रेम प्रकाश पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि ये मुद्दे तथ्यों से जुड़े हैं, जिनका खंडन जवाब में किया जा चुका है। ऐसे में बिना साक्ष्य के फैसला संभव नहीं है।

हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि यह तय करना कि उम्मीदवार ने जानकारी छिपाई या नहीं, क्या चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण हुआ और उसका चुनाव नतीजे पर क्या असर पड़ा–ये सारे सवाल केवल साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही तय हो सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी फरवरी में देवेंद्र यादव की याचिका खारिज कर चुका है और उन्हें हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए कहा था। अब इस चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होगी।

समयमान वेतनमान पर उलझन 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाओ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के बीच गहरा असमंजस फैल गया है। क्रमोन्नति योजना को समयमान वेतनमान में समाहित करने की प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन सौंपकर विकल्प चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में कर्मचारियों को 9 जुलाई तक यह फैसला करना है कि वे पुरानी क्रमोन्नति योजना में बने रहें या नई समयमान वेतनमान व्यवस्था को अपनाएं। फेडरेशन का कहना है कि मात्र एक महीने की यह समय-सीमा बहुत कम है। दोनों व्यवस्थाओं के नियम पूरी तरह अलग-अलग हैं, जिससे कर्मचारी सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं।

क्रमोन्नति योजना में 12 और 24 वर्ष की सेवा पर लाभ मिलता है, वहीं समयमान वेतनमान 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर आधारित है। इसके अलावा हर विभाग की कैडर संरचना, पदक्रम और वेतनमान भी अलग-अलग हैं। ऐसे में हर कर्मचारी को अपने पूरे सेवा रिकॉर्ड, भविष्य की पदोन्नति और वित्तीय लाभों का अलग से मूल्यांकन करना पड़ रहा है। कई विभागों में अधिकारी भी स्पष्ट मार्गदर्शन देने में असमर्थ दिख रहे हैं, जिससे अलग-अलग कार्यालयों से मिल रही परस्पर विरोधी जानकारियां कर्मचारियों की उलझन को और बढ़ा रही हैं।

प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में वेतन, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों के हित में विकल्प की अंतिम तिथि 9 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई करने की अपील की है। फेडरेशन का दावा है कि वह प्रदेश के 134 कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।अब देखना यह है कि सरकार इस मांग को मानती है या नहीं। अगर समय-सीमा बढ़ाई गई तो हजारों कर्मचारियों को सही फैसला लेने का पर्याप्त मौका मिल सकेगा, अन्यथा कई को मजबूरन जल्दबाजी में विकल्प चुनना पड़ेगा।

दो बाइकों की टक्कर के बाद लगी आग: दो की मौत

बलरामपुर। जिले में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग भी लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। यह घटना वाड्रफनगर थाना क्षेत्र में बलंगी रोड के चुरैला नाला के पास हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों मोटरसाइकिलों पर दो-दो लोग सवार थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद दोनों बाइकों में आग लग गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण वाहनों में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को बचाने का प्रयास किया और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वाड्रफनगर पुलिस मौके पर पहुंची।

भूत-भविष्य बताने वाला बाबा फरार 40 लाख और गाड़ी लेकर गायब

रायपुर। तंत्र-मंत्र और चमत्कार के नाम पर एक बार फिर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर के कथित तांत्रिक नरेंद्र नयन शास्त्री पर गाजियाबाद के एक डॉक्टर को उनके भाई की संदिग्ध मौत का राज बताने के बहाने 40 लाख रुपये और एक वाहन ठगने का आरोप लगा है। आरोपों के सामने आने के बाद तांत्रिक फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

गाजियाबाद निवासी डॉक्टर ऋषभ चौबे के भाई की इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार सदमे में था और मौत के पीछे की असली वजह जानने के लिए बेचैन था। इसी दौरान डॉक्टर का संपर्क रायपुर के नरेंद्र नयन शास्त्री से हुआ। तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि विशेष पूजा, तांत्रिक साधना और अनुष्ठान के जरिए वह मौत का पूरा सच बता देगा।डॉक्टर ने विश्वास कर लिया।

शिकायत के अनुसार, तांत्रिक ने अलग-अलग पूजा-पाठ और साधना का हवाला देकर किस्तों में कुल 40 लाख रुपये वसूल लिए। इसके अलावा एक वाहन भी अपने कब्जे में ले लिया। महीनों बीत गए, लेकिन न तो कोई तांत्रिक क्रिया पूरी हुई और न ही मौत का कोई रहस्य खुला। जब डॉक्टर को धोखा होने का अहसास हुआ तो उन्होंने रायपुर के खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपी नरेंद्र नयन शास्त्री फिलहाल फरार है। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और लेन-देन के साक्ष्य जुटा रही है।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि शास्त्री ने आस्था की आड़ में अन्य लोगों को भी ठगा है या नहीं। यदि और पीड़ित सामने आए तो मामले की गंभीरता बढ़ सकती है। यह घटना एक बार फिर सवाल उठा रही है कि अंधविश्वास और संकट के समय का फायदा उठाकर कुछ लोग किस हद तक ठगी कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

स्वच्छता के लिए 50 अतिरिक्त कामगार मिलेंगे

भिलाई निगम में महापौर परिषद की बैठक, हुडको में सीवर लाइन बदलेगी, नए मंगल भवन का होगा सौंदर्यीकरण

भिलाई। भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में सोमवार को शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर नीरज पाल ने की, जबकि निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय भी मौजूद रहे। बैठक में सीवर लाइन की मरम्मत और नवीनीकरण, शहर की सफाई व्यवस्था, मंगल भवनों के संचालन और अन्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सभी प्रमुख प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।

बैठक में वार्ड क्रमांक 69 और 70 स्थित हुडको इलाके में पुरानी सीवरेज पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। लंबे समय से इस क्षेत्र में सीवर की समस्या बनी हुई थी। परिषद का मानना है कि पाइप लाइन बदलने के बाद लोगों को राहत मिलेगी और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी।

50 अतिरिक्त कामगार मिलेंगे

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 50 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निगम का कहना है कि बारिश या किसी भी आपात स्थिति में इन कर्मचारियों की मदद से सफाई का काम तेजी से किया जा सकेगा। वहीं जोन-3 के संतोषी पारा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को दो महीने के लिए संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही इसी भवन को 10 महीने के लिए किराये पर संचालन और रखरखाव के लिए देने से जुड़े नियम और शर्तों को भी परिषद ने मंजूरी दे दी।

खुर्सीपार स्टेडियम के मेंटेनेंस को लेकर भी हुई चर्चा

खुर्सीपार स्थित पुराने स्टेडियम और वहां बनी दुकानों के रखरखाव और तकनीकी कार्यों से जुड़े प्रस्ताव को सलाहकार समिति के पास भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे अगली महापौर परिषद की बैठक में रखा जाएगा।

वहीं निगम क्षेत्र में बने नए स्लॉटर हाउस को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। इस मुद्दे पर अगली बैठक में फिर से चर्चा होगी। बैठक के अंत में महापौर परिषद ने कहा कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उनके लागू होने से शहर में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।

गार्डन विकसित करने पर भी बनी सहमति

वार्ड क्रमांक 70 में बने नए मंगल भवन के आसपास गार्डन विकसित करने, परिसर का सौंदर्यीकरण करने और पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इसके अलावा गोकुल धाम, कुरूद में पशुपालकों को आवंटित भूखंडों से जुड़ी बची हुई प्रीमियम राशि और भू-भाटक जमा कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शहर के चौक-चौराहों के नामकरण का मुद्दा भी उठा। इस पर परिषद ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। पहले पूर्व महापौर परिषद के संकल्प की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अगली बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

हाईकोर्ट की रोक के बीच अटकी पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति

- हाईकोर्ट बोला-प्रक्रिया चलेगी, अंतिम आदेश नहीं, दूसरे जिलों के आरक्षकों को प्रमोशन देने को चुनौती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि, पुलिस विभाग प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

यह आदेश आरक्षकों की वरिष्ठता सूची में नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। याचिका सुरेंद्र कुमार देशमुख की ओर से दायर की गई है, जिसमें राज्य शासन समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में पुलिस मुख्यालय और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि आरक्षकों की वरिष्ठता तय करने के स्थापित नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई है।

विवाद उन आरक्षकों की वरिष्ठता को लेकर है, जो अपने खुद के अनुरोध पर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होकर गए हैं। नियमों के मुताबिक, यदि कोई आरक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरण लेता है, तो उसे नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए। यानी उस जिले में पहले से पदस्थ आरक्षकों के ऊपर उसे वरीयता नहीं मिल सकती। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस विभाग इस नियम को दरकिनार कर ऐसे आरक्षकों को भी प्रमोशन के लिए पात्र मान रहा है, जो स्वेच्छा से ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में आए हैं। आरोप है कि उनकी वरिष्ठता नए जिले में जॉइनिंग की तारीख से तय करने के बजाय उनकी मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर गिनी जा रही है। इससे मूल जिले के आरक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और वरिष्ठता सूची का पूरा क्रम बदल रहा है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007' के तहत वरिष्ठता से जुड़े प्रावधानों और बाद में किए गए संशोधनों का अवलोकन किया।

प्रकाशक एवं मुद्रक सुभाष मिश्रा द्वारा स्वामी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि. के लिए मिशन मीडिया प्रा.लि., रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं एचआईजी 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित।

प्रधान संपादक- सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक-भालचंद्र जोशी, स्थानीय संपादक-विवेक मिश्रा, आरएनआई रजि. नं.-52143/91, * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।